CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 17-07-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH14 User: dilip.lal Time: 07-16-2025 22:08 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 17 जुलाई 2025

अपना-अपना हित

रूस के साथ व्यापार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की चेतावनी भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत में अड़चन पैदा कर सकती है। यूक्रेन युद्ध रुकवाने में नाकाम रहे डॉनल्ड ट्रंप अब दूसरे जरियों से मॉस्को पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि इसमें सफलता की गारंटी नहीं और इससे दुनिया में नया तनाव पैदा हो सकता है।

50 दिनों की डेडलाइन । ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए रूस को 50 दिनों की मोहलत दी है, और यही डेडलाइन उन्होंने उन देशों के लिए रखी है, जो रूस से तेल समेत दूसरे सामान खरीदते हैं। अमेरिका की धमकी है कि इसके बाद इन देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यही बात नैटो महासचिव मार्क रूट भी दोहरा रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो सीधे-सीधे भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया कि इन देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन से शांति के लिए बात करनी चाहिए।

रूस से तेल खरीद मामला

बदली रणनीति । कुछ वक्त पहले तक ट्रंप इस बात पर डटे थे कि किसी भी सूरत में यूक्रेन युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन, जब उनका दबाव रूस पर कारगर नहीं हुआ, तो उन्होंने रणनीति बदल दी। अब वह यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या रूस पर हमला कर लोगे?

पुरानी कोशिश । अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस को झुकाने में बाकी दुनिया भी उसका साथ दे - खासकर भारत और चीन। साल 2022 में, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका की यही कोशिश है। पहले भी उसने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर सवाल उठाए थे और यहां से उसे इसका माकूल जवाब भी मिला था कि दुनिया के हर हिस्से के अपने-अपने हित होते हैं।

तेल का व्यापार । साल 2024-25 में भारत और रूस के बीच 68.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा फोकस में रहा तेल। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले तक देश की ज्यादातर तेल जरूरत मिडल ईस्ट से पूरी होती थी और तब रूस से केवल एक फीसदी क्रूड ऑयल ही आता था। आज यह हिस्सा एक तिहाई से ज्यादा है। मई में भारत ने रूस से हर दिन करीब 20 लाख बैरल तेल मंगाया था। इस व्यापार के पीछे साधारण-सा लॉजिक है, बचत।

मजबूती से रखी जाए बात । हर रिश्ते को मुनाफे में तौलने वाले ट्रंप भारत-रूस संबंधों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके दबाव बनाने के पीछे एक वजह BRICS भी है, जिसकी सक्रियता उन्हें पसंद नहीं आ रही। भारत को इस मामले में अमेरिका के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, जिसे पिछली बाइडन सरकार ने समझा भी था।

साड्डी दिल्ली

पहले गोरे का क़त्ल

विवेक शुक्ला

मूसलाधार बारिश बंद हो चुकी है। बारिश ने कश्मीरी गेट की सेंट जेम्स चर्च में लगे बुजुर्ग पेड़ों के पत्ते उजले कर दिए हैं। 1836 में बनी दिल्ली की पहली चर्च में दफन हैं कुछ नामवर और कुछ अनाम लोगों की कब्रें। उनके ऊपर से भी धूल हट गई है। कभी यहां होती थी ब्रिटिश रेजिडेंट विलियम फ्रेजर की भी कब्र। उनका 6 मार्च, 1835 को कश्मीरी गेट में घर से कुछ कदम आगे कत्ल हो गया था।

फ्रेजर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह के बीच सेतु का काम करते थे। उनका कत्ल दिल्ली में किसी गोरे की पहली हत्या माना जाता है। इस कत्ल से शाहजहांबाद से लेकर यहां तक के गांव थर्रा गए थे। उस दौर में दिल्ली का मतलब यही तो होता था। बहरहाल दिलचस्प है कि इस हत्या ने मिर्जा गालिब की चिंता काफी बढ़ा दी थी। गोपाल शुक्ल अपनी किताब 'मेटकाफ हाउस' में लिखते हैं- 'फ्रेजर का कत्ल बल्लीमारान में रहने वाले मिर्जा गालिब की उम्मीदों पर कहर बनकर टूटा। फ्रेजर गालिब की पेंशन बढ़ाने के लिए कलकत्ता में ब्रिटिश गवर्नर जनरल को खत लिख रहे थे।'

कहते हैं कि फ्रेजर को पहले कश्मीरी गेट के निक्सलन कब्रिस्तान में दफन किया गया। हालांकि कुछ समय बाद उनके अवशेष सेंट जेम्स चर्च में दफन किए गए थे। इस बीच, पुलिस फ्रेजर के कातिल को तलाश करने लगी। कत्ल नवाब शुजात अली खान ने किया था। वह दिल्ली के एक असरदार व्यक्ति नवाब शम्सुद्दीन अहमद खान का आदमी था। दरअसल, फ्रेजर ने शम्सुद्दीन के खिलाफ कुछ प्रशासनिक कार्रवाइयां की थीं। इसके चलते उसने शुजात को सुपारी देकर फ्रेजर का कत्ल करवा दिया। नवाब शम्सुद्दीन को लगता था कि अगर फ्रेजर को रास्ते से नहीं हटाया गया तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बहरहाल, पुलिस ने हत्यारे और हत्या के कारणों का पता लगाने में देर नहीं की। शुजात अली और नवाब शम्सुद्दीन को पकड़ लिया गया। उन्हें 3 अक्टूबर, 1835 को फांसी दे दी गई। सेंट जेम्स चर्च से निकलते हुए एक संगमरमर से बनी चर्च पर नजर जाती है। उस पर लिखा है- सर थॉमस थियोफिलस मेटकाफ। फ्रेजर के बाद मेटकाफ ही बने थे दिल्ली के रीजेंट।

एकदा

प्यार ने मिटाई दूरियां

Clarkebury Boarding Institute दक्षिण अफ्रीका का पहला ऐसा बोर्डिंग स्कूल था, जिसे थेंबूलैंड के काले लोगों के लिए क्रिश्चियन मिशनरी ने खोला था। पढ़ाई के बाद छात्रों को यहां रोज श्रम करना पड़ता था। माध्यमिक शिक्षा के लिए नेल्सन मंडेला को यहीं भर्ती किया गया। स्कूल में पहली बार उन्होंने बूट पहना तो लकड़ी के बने चिकने फर्श पर लड़खड़ाकर फिसलने लगे। देहाती कहकर कुछ ने मजाक उड़ाया, ठहाके भी लगाए, लेकिन वे शीघ्र ही उनके दोस्त बन गए। पढ़ाई के बाद श्रमिक के तौर पर काम करने के लिए उन्हें संस्थान के सर्वोच्च पदाधिकारी रेवरेंड सी हारिश का गार्डेन मिला। वहां वह सब्जी उगाने के साथ, बागवानी का हुनर भी सीख गए। यहीं उन्होंने हारिश के उस रूप को भी नजदीक से देखा जिसमें स्कूल सी सख्ती नहीं थी। गार्डेन में चुप्पी के साथ विचारों में खोई उनकी सूरत वह निहारते थे। नेल्सन मंडेला ने उन्हें रोल मॉडल मान लिया। हां, उनकी पत्नी, मंडेला से उतनी ही बातें करती थीं, जितनी उनकी चुप्पी थी। उनका प्यार और नाश्ता, एक तोहफे के रूप में उन्हें मिला, जिसे उन्होंने आजीवन संजोकर रखा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी अंतिम सांस तक उन्हें यह याद दिलाता रहा कि सभी गोरे कालों से घृणा नहीं करते। उनका यही भाव काले-गोरों में निकटता के निर्माण में सहायक बना। मंडेला का कहना था, प्यार के सिवा और कोई रास्ता नहीं।

Subrata Dhar

संकलन : हरिप्रसाद राय

मोटापे की महामारी घातक रूप ले रही है, मगर इलाज के नए तरीक़ों पर भी उठ रहे हैं सवाल

इस मर्ज़ की दवा भी कम ख़तरनाक नहीं

चंद्रभूषण

कुछ दिनों पहले एक OTT प्लैटफॉर्म पर दिलचस्प दृश्य दिखा। एक मशहूर कमीडियन की सिलेब्रिटी बेस्ड प्रस्तुति में रोमांटिक हिंदी फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित निर्माता-निर्देशक तशरीफ लाए थे। दोनों इतने दुबले दिख रहे थे कि हंसी-मजाक के इस प्रोग्राम में लाख कोशिशों के बावजूद उनकी रत्ती भर भी हंसी नहीं निकल रही थी। इसे देश पर मंडरा रही एक नई मुश्किल की बानगी समझा जाए।

अघोषित महामारी । डायबिटीज और अनियंत्रित रूप से वजन बढ़ने को पिछले कुछ वर्षों से भारत की एक अघोषित महामारी समझा जाने लगा है। इस सदी के पहले डेढ़ दशकों में आसन और प्राणायाम को लेकर एक लहर सी चलती दिखाई पड़ी तो लगा कि अक्सर खराब जीवनशैली से पैदा होने वाली इन बीमारियों का सामना लोग शायद अपनी संस्कृति में समाए पुराने नुस्खों से ही कर लें। लेकिन यह समझ अभी बचकानी-सी लगने लगी है।

दवा की डिमांड । अभी मिडल और हाई इनकम ब्रैकेट में बैठे ज्यादातर लोग किसी ऐसी दवा या मेडिकेशन प्रोग्राम की तलाश में हैं, जो जीवनशैली में बहुत बड़े बदलाव की मांग किए बगैर उनके वजन को overweight या obese वर्ग में न जाने दे, या ऐसा हो चुका हो तो उन्हें वापस सामान्य BMI के दायरे में ला दे। डिमांड है तो कहीं न कहीं से सप्लाई भी होने ही लगेगी। थोड़ा खोजने पर ऐसे क्लिनिक मिल ही जा रहे हैं, जो ठीक-ठाक पैसे लेकर विवाह-योग्य लड़के-लड़कियों या मनोरंजन उद्योग में अपना भविष्य देख रहे लोगों को उनका वजन काबू में ला देने का आश्वासन दे रहे हैं।

क्यों मुश्किल है रास्ता
- डायबिटीज और मोटापे का घातक कॉम्बिनेशन बढ़ रहा
- लाइफस्टाइल बदलना सिर्फ इच्छा की बात नहीं
- इलाज में इस्तेमाल दवाओं के खतरनाक साइडइफेक्ट

क्या है GLP-1 । ऐसे माहौल में glucagon like peptide-1 (GLP-1), अंग्रेजी के तीन अक्षर और उनसे जुड़ी एक गिनती कोरोना का हल्ला खत्म होने के साथ ही भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। GLP-1 एक नैचरल हार्मोन है और बाकी हार्मोनों की तरह यह भी एक बहुत जरूरी शारीरिक प्रक्रिया में ट्रिगर की भूमिका निभाता है। खुद glucagon का काम आंत की कोशिकाओं को शरीर में ब्लड शुगर छोड़ने के लिए राजी करने का है। ब्लड शुगर शरीर के आम चलाव-फिराव का मुख्य ईंधन है। आपने खाना खाया और glucagon ने यह सुनिश्चित किया कि शरीर के लिए जरूरी फ्यूल भोजन से यथाशीघ्र निकलकर आपके खून में पहुंच जाए। GLP-1, glucagon से मिलते-जुलते रासायनिक ढांचे वाला एक सहयोगी हार्मोन है।

एक हार्मोन, तीन काम । दिमाग के पिछले हिस्से से और आंतों से निकलकर यह तीन काम करता है। सबसे पहले तो शरीर को यह एहसास कराना कि भोजन हो गया, अब और खाने की जरूरत नहीं। दूसरा, अग्नाशय (पैंक्रियास) की कोशिकाओं को पर्याप्त इंसुलिन रिलीज करने को कहना, ताकि ब्लड शुगर नाम का ईंधन जलकर शरीर को ऊर्जा दे। और तीसरा, glucagon को नियंत्रित करे, ताकि ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा निकलने नहीं पाए। यह भी दिलचस्प है कि GLP-1 शरीर में प्राकृतिक रूप से सिर्फ दो मिनट टिका रहता है। इतने में ही उसका काम हो जाता है, फिर DPP नाम का एंजाइम उसे पचाकर बाहर कर देता है।

सीरियस साइड इफेक्ट । GLP-1 का इस्तेमाल दवा की तरह किया जा सकता है, इस बारे में गंभीर सोच-विचार नब्बे के दशक के मध्य में शुरू हुआ। तीस साल से ज्यादा समय तक इस समस्या पर काम करती आ रही डेनमार्क की फार्मासिस्ट लोटे ब्जेर नडसेन ने अभी हाल में भारत में छपे अपने एक इंटरव्यू में इस शोध और इसे दवा में बदलने की प्रक्रिया को लेकर गहराई से बातचीत की है। नडसेन ने लंबी कोशिशों के बाद किसी तरह वसा के एक अणु को GLP-1 के साथ नत्थी करने का रसायनशास्त्र खोज निकाला। इस जुगाड़ से शरीर में इस हार्मोन को हफ्ता भर टिकाया जा सकता है। ध्यान रहे, ये दवाएं रुग्णता की कुछ खास स्थितियों में, जब बाकी दवाएं काम नहीं करतीं, डॉक्टर के नुस्खे पर ही ली जा सकती हैं क्योंकि इनके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं।

सतर्कता की दरकार । यहां इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगले साल, 2026 में इनमें से एक दवा का पेटेंट समाप्त हो रहा है। दुनिया भर में जेनरिक दवाओं का बेताज बादशाह भारत इसका सस्ता विकल्प बाजार में उतारने में ज्यादा देर नहीं करेगा। अभी GLP-1 एगोनिस्ट्स की कीमतों ने इसके उपयोग की हद बांध रखी है। जैसे ही यह हद नीचे आई, भारत में लोग बड़ी मात्रा में इसका उपयोग करेंगे। लेकिन याद रहे, नडसेन ने अपने इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि इस दवा से अपना वजन घटाने वाले लोग दवा बंद करने के बाद क्या अपने सहज जीवन में वापस लौट सकेंगे। अगर हां, तो इसमें कितना समय लगेगा। बिल्कुल मूल तक जाकर काम करने वाले इस मेडिकेशन को लेकर भारत में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है।

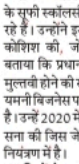

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

निमिषा को ग्रैंड मुफ़्ती ने कैसे दिलाई राहत

सुहेल वहीद

केरल की नर्स निमिषा प्रिया की सजा-ए-मौत टाल दिए जाने के पीछे केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबु बकर अहमद की भूमिका की चर्चा हो रही है। अबु बकर अहमद ने मीडिया को बताया कि उनसे स्थानीय विधायक चैंडी ओमन ने हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था।

संपर्क में सरकार । ग्रैंड मुफ्ती का कहना है कि यमन के सूफी स्कॉलर्स से उनके तालीम के सिलसिले के संबंध रहे हैं। उन्होंने इस मामले को देश हित में हल करने की कोशिश की, जो फिलहाल कामयाब रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को फांसी की सजा के मुल्तवी होने की खबर दे दी गई है। निमिषा प्रिया पर अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की 2017 में हत्या करने का आरोप है। उन्हें 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई। निमिषा प्रिया सना की जिस जेल में हैं, वह इलाका हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है।

हूतियों के हमले । लाल सागर में 2023 से ही हूती विद्रोही जब-तब अमेरिकी जहाजों पर हमले करते रहते हैं। इसके अलावा इस्राइल पर भी इनकी मिसाइलों के गिरने की खबरें आती रहती हैं। जनवरी 2024 में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को दूसरी बार आतंकवादी संगठन घोषित किया। हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थन

कॉमन रूम

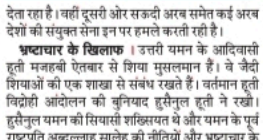

देता रहा है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब समेत कई अरब देशों की संयुक्त सेना इन पर हमले करती रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ । उत्तरी यमन के आदिवासी हूती मजहबी ऐतबार से शिया मुसलमान हैं। वे जैदी शियाओं की एक शाखा से संबंध रखते हैं। वर्तमान हूती विद्रोही आंदोलन की बुनियाद हुसैनुल हूती ने रखी। हुसैनुल यमन की सियासी शख्सियत थे और यमन के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह सालेह की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। उनके नाम पर हूती संगठन वजूद में आया।

विद्रोह की बुनियाद । 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान अन्य अरब देशों के साथ-साथ यमन में भी प्रदर्शन हुए। इस दौरान अब्दुल्लाह सालेह की हत्या कर दी गई। इसके चलते सुन्नियों के बीच हूतियों का जो विश्वास था, वह खत्म हो गया। इसके बाद हूतियों ने 2014 में जबर्दस्त सैन्य कार्रवाई करते हुए यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया। इन विद्रोहियों का कहना था कि राष्ट्रपति मंसूर हादी की सरकार सऊदी अरब और अमेरिका की बिल्कुल पिट्ठू है।

गृह युद्ध की मुसीबत । तभी से यमन गृह युद्ध की चपेट में है। UNHCR का कहना है कि अब वहां भीषण मानवीय संकट पैदा हो चुका है। गृह युद्ध और हमलों की मुसीबत के चलते करीब पचास लाख यमनी नागरिक अपने घर-बार छोड़ कर भागने पर मजबूर हुए हैं। इनमें अधिकांश सुन्नी हैं। उन्हें अपना इलाका छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके घर तबाह हो गए, नागरिक सुविधाएं समाप्त हो गईं। वाशिंगटन इंस्टिट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के अनुसार हूती विद्रोही जंग के हिसाब से ज्यादा मजबूत, तकनीकी रूप से निपुण और संगठित होते जा रहे हैं।

जारी है कोशिश । हूतियों के इस पसमंजर में केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबु बकर अहमद ने यमन में काफी प्रतिष्ठित सूफी इस्लामी स्कॉलर हबीब उमर बिन हफीज से निमिष प्रिया बारे में बात की। उन्होंने उत्तरी यमन के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच दैत या 'खून बहा' तथा अन्य विकल्पों पर सुलह कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दो साल पहले आठ हिंदुस्तानी पूर्व नेवी अफसरों पर जासूसी के आरोप में कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त उन लोगों की भी रिहाई सुनिश्चित की गई थी।

ऐसे बनी थी पहली मतदाता सूची

पीयूष पांडे

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के Special Intensive Revision यानी SIR पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर यह जानना दिलचस्प होगा कि देश में पहली मतदाता सूची कैसे तैयार हुई थी।

पहला इलेक्शन । पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था। इसके लिए मार्च 1951 तक पूर्ण मतदाता सूची तैयार हो गई थी।

क्रांतिकारी बदलाव । ब्रिटिश राज में जिन प्रांतों में चुनाव होते थे, वहां वोटर बनने के नियम अलग थे। मसलन - सिख निर्वाचन क्षेत्र में सिखों और मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिमों के अलावा कोई वोट नहीं डाल सकता था। वोटिंग राइट भी चुनिंदा लोगों के पास था। धर्म, संपत्ति, शिक्षा, जेंडर जैसे कई मापदंड इसका आधार थे। ऐसे में जब संविधान सभा ने तय किया कि भारत सभी वयस्कों को मताधिकार देगा, तो यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था।

जागरूकता अभियान । तब महिलाएं अपनी पहचान को पति या पिता से जोड़कर देखती थीं। ब्रिटिश राज में बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम फलां की पत्नी या फलां की बेटी के तौर पर दर्ज हुए थे। ऐसे में जागरूकता अभियान चलाए गए।

प्रस्ताव खारिज । संविधान सभा के सदस्य रहे टी. शाह ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर मतदाता सूची तैयार करने के साथ जनगणना कराने की मांग कर दी। हालांकि बाद में उनका प्रस्ताव खारिज हो गया।

AI Image

टाइम मशीन

मॉक इलेक्शन । पूर्वी पंजाब के चुनाव आयुक्त ने केंद्र से चिंता जताई कि राज्य के सभी बड़े प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान के कब्जे वाले लाहौर में चले गए हैं। ऐसे में मतदाता सूची कैसे छपेगी? राजस्थान के एक अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा, 'हमें इलेक्टोरल लिस्ट तैयार करने का कोई अनुभव नहीं है। कृपया कोई सैंपल तरीका या कोई ऐसा राज्य बताएं, जहां यह प्रक्रिया संचालित हुई हो।' इसके जवाब में चुनाव आयोग ने एक मैनुअल जारी किया, जिसमें चरण-दर-चरण बताया गया था कि सूची कैसे तैयार की जाए। एक राज्य में 1948 में मॉक इलेक्शन की योजना बनाई गई।

सवाल चिंताजनक । 1952 के पहले आम चुनाव में देश भर में 45% वोटिंग हुई। यह उस समय की साक्षरता दर - करीब 19% और हालात को देखते हुए बड़ी सफलता थी। पाकिस्तान में 20 साल तक इलेक्टोरल रोल नहीं बन पाई और वहां के लोकतंत्र का हाल सबको मालूम है। लेकिन, आज जब भारत अनुभव और संसाधनों से भरपूर है, तब भी बिहार में मतदाता सूची पर सवाल उठना चिंता का विषय है।

हर एक वोट कीमती । लोकतंत्र में आम आदमी के पास अपनी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा हथियार वोट ही है। कई उदाहरण हैं, जहां एक-दो या कुछ वोटों ने सियासत बदल दी। 2008 में राजस्थान में दिग्गज नेता सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे। वह उस वक्त कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी 21 सीटें ऐसी थीं, जहां जीत-हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम था।

कंपनियों का भी फ़ायदा

राहुल पाण्डेय

अक्सर यह बात कही जाती रही है कि कार्यक्षेत्र में जितनी विविधता होगी, वहां माहौल से लेकर कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन तक बेहतर होगा। यही बात एक HR फर्म की हालिया स्टडी में भी सामने आई है। अध्ययन में लगभग 10 में से 8 सेक्टरों में पाया गया कि संस्थानों में महिलाओं की मौजूदगी और बेहतर मुनाफे के बीच सीधा संबंध है। यह डेटा 30 अलग-अलग क्षेत्रों की 840 सूचीबद्ध कंपनियों से लिया गया था। जो कंपनियां विविधता के मामले में टॉप पर रहीं, उन्होंने टैक्स चुकाने के बाद बाकियों के बरक्स लगभग 50% अधिक मुनाफा कमाया। लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि भारत की कॉरपोरेट दुनिया में महिलाएं अब भी अहम प्रबंधकीय भूमिकाओं और कुल कार्यबल में बहुत कम हैं। HR फर्म मार्चिंग शीप की स्टडी बताती है कि 63.45% कंपनियों में किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय पद पर कोई महिला नहीं थी। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है।

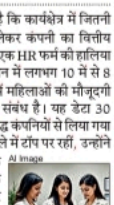

AI Image

आधी दुनिया

महिलाओं की वर्कफोर्स भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा घरेलू जिम्मेदारियां और बच्चों की देखभाल है। PLFS 2023-24 में 43.04% महिलाओं ने इन जिम्मेदारियों को काम न करने का मुख्य कारण बताया। शहरी क्षेत्रों में अकेली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास, सार्वजनिक परिवहन, और क्रेच सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी रुकावट है। हालांकि भारत सरकार ने महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, फिर भी आगे बढ़ने के लिए अभी ढेरों संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। समावेशी कंपनियों का बेहतर वित्तीय प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि विविधता न केवल नैतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है। सवाल है कि क्या भारत का कॉरपोरेट जगत और समाज इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार है?

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ लीपापोती न हो

15 जुलाई का संपादकीय 'सवालों भरी रिपोर्ट' पढ़ा। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री ने अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश मामले में आई रिपोर्ट को प्रारंभिक बताते हुए अटकलें न लगाने की अपील की है, लेकिन इस रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना किसी ठोस आधार के पायलटों के ऊपर प्रश्नचिह्न लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा विमानों के रूट की योजना और उसका निर्धारण और आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जांच की फाइनल रिपोर्ट जब भी आए, उसमें सभी जरूरी सवालों के जवाब मिलने चाहिए। जरूरी है कि रिपोर्ट में जिम्मेदार लोगों की पहचान और व्यवस्था में निहित त्रुटियों का स्पष्ट रूप में जिक्र हो। रिपोर्ट से लीपापोती का संकेत मिले तो जांच की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

बाल गोविंद, नोएडा

■ ट्रंप की तानाशाही

यह पत्र 14 जुलाई के संपादकीय 'ट्रंप का बदला' से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के फैसले दुनिया में अमेरिकी छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी विभागों में कटौती, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बंदिशें, 2020 में हुई हिंसा में शामिल लोगों को माफ करना और इसके उलट उन अधिकारियों पर कार्रवाई करना, जो इस मामले की कार्यवाही से जुड़े थे - लगता है कि ट्रंप सचमुच बदले की भावना से काम कर रहे हैं। उनके दूसरे टर्म पर गौर किया जाए, तो पता चलेगा कि वे हर उस आवाज को दबाना चाहते हैं जो उन्हें अपने खिलाफ जाती हुई लगती है।

पैंथर तोमर, किशनगंज

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

जयशंकर ने चिनफिंग को रिश्तों में प्रगति की जानकारी दी - खबर

- पर चीन रिश्तों की अहमियत समझे तब ना!

किरण ठाकुर

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

एक-दूसरे से बड़ा होने का भाव मिटना है मुक्ति

स्वामी विवेकानंद

हम ईश्वर की उपासना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी देह बीच में आ जाती है। प्रकृति उनके और हमारे बीच में पड़कर हमारी दृष्टि को अंधा कर देती है। लज्जा, मलीनता, दुख, पाप-ताप के भीतर भी हमें उनसे प्रेम करने की शिक्षा लेनी होगी।

सारा संसार धर्म और ईश्वर का प्रचार चिरकाल से करता आ रहा है। मैं ऐसे ईश्वर का प्रचार करना चाहता हूं, जो एकाधार से धर्म और अधर्म दोनों में ही है। यदि साहस हो तो इस ईश्वर को ग्रहण करो, यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। तभी यह धारणा नष्ट होगी कि एक व्यक्ति दूसरे से बड़ा है।

जितना ही हम इस मुक्ति तत्व के पास जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर के आश्रय में आते हैं, उतना ही हमारा दुख-कष्ट दूर होता है। तब हम नरक के द्वार को स्वर्ग द्वार से अलग नहीं समझेंगे। तब हम मनुष्य-मनुष्य में भेद कर यह नहीं कहेंगे कि मैं जगत के किसी प्राणी से श्रेष्ठ हूं। जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं होती कि हम संसार में उस प्रभु के सिवाय और किसी को न देखें, तब तक हम दुख-कष्ट से घिरे ही रहेंगे, तब-तक हम सबमें भेद देखेंगे।

एक ही वृक्ष पर सुंदर पंख वाले अभिन्न दो पक्षी हैं। एक वृक्ष के ऊपर वाले भाग पर और दूसरा नीचे वाले भाग पर बैठा है। नीचे का सुंदर पक्षी वृक्ष के मीठे और कड़वे फलों को खाता है। जिस पल उसने कड़वे फल को खाया, उसे कष्ट हुआ। कुछ क्षण के बाद ही एक और फल खाया और जब वह भी कड़वा लगा, तब उसने ऊपर की ओर देखा। ऊपर उसको दूसरा पक्षी दिखाई दिया, वह मीठे या कड़वे, किसी भी फल को नहीं खाता। वह अपनी महिमा में मग्न हो स्थिर और धीर भाव से बैठा है। धीरे-धीरे वह उस ऊपर वाले पक्षी की ओर बढ़ा। जब वह उसके एकदम निकट पहुंचा, तब उस ऊपर वाले पक्षी की अंगज्योति उसके ऊपर पड़ी और धीरे-धीरे उस ज्योति ने उसको ढंक लिया।

अब उसने देखा कि वह उस ऊपर वाले में ही परिणत हो गया है। तब से वह शांत, महिमामय और मुक्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में वृक्ष पर दो पक्षी कभी थे ही नहीं, केवल एक ही पक्षी था। नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले पक्षी की केवल छाया थी। इसी प्रकार हम ईश्वर से अभिन्न हैं। लेकिन जिस प्रकार एक सूर्य लाखों ओस की बूंदों पर प्रतिबिंबित होकर छोटे-छोटे लाखों सूर्य-सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी बहु जीवात्मरूप से प्रतिभासित होते हैं। यदि हम अपने प्रकृत ब्रह्मस्वरूप के साथ अभिन्न होना चाहें तो प्रतिबिंब को दूर करना आवश्यक है।

इन सब का एक ही उद्देश्य है। मुक्ति-लाभ को छोड़ हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। जाने या अनजाने हम सब पूर्णता पाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसे एक-न-एक दिन अवश्य ही पाएगा।

('मैं कौन हूं' पुस्तक से साभार)

दैनिक जागरण

स्वप्नों की पूर्ति के लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं

बेकार की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल लेने के कारण भारत, चीन, ब्राजील पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाने के जो संकेत दिए और यह भी धमकी दी कि रूस से ऊर्जा आपूर्ति जारी रखने वाले देशों पर 500 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, उसका कोई मूल्य-महत्व नहीं। यह बेकार की धमकी है। भारतीय नेतृत्व और भारत की जनता को इस धमकी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रंप की इस तरह की कई धमकियां खोखली साबित हुई हैं और उन्हें अपनी ही बातों से पलटना भी पड़ा है। इससे उनकी और अमेरिका की जगहंसाई ही हुई है। यह एक तथ्य है कि दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने अपने बयानों और नीतियों से अपनी फजीहत कराने का ही काम किया है। उन्होंने अपने मित्र देशों का भी भरोसा खोया है। अमेरिका को फिर से महान बनाने के नाम पर वे विचित्र से काम कर रहे हैं। उनके रवैये से अमेरिका में उनके अनेक समर्थक भी असंतुष्ट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ दिनों पहले तक यूक्रेन के राष्ट्रपति पर लाल-पीले हो रहे थे और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रति नरमी दिखा रहे थे, लेकिन जब यूक्रेन से खनिजों के दोहन पर समझौता हो गया और उधर पुतिन ने उनकी बातों और धमकियों को कोई भाव नहीं दिया तो उन्होंने अपना रवैया बदल लिया।

यदि ट्रंप को लगता है कि उनके विचित्र व्यवहार को कोई समझ नहीं पा रहा होगा तो इसका मतलब है कि वे मुगालते में हैं। अच्छा हो कि वे मुगालते से बाहर आएं और अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय कद एवं प्रभाव की चिंता करें। वैसे भी अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका का पहले जैसा प्रभाव नहीं रह गया है। ऐसे देशों की संख्या बढ़ रही है जो अमेरिका को आंख दिखाने से संकोच नहीं करते। यदि ट्रंप ने अपना रवैया नहीं बदला तो अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और अधिक कम होगा। यह सही है कि अमेरिका अब भी सबसे बड़ी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति है, लेकिन उसे चुनौती भी मिल रही है। यदि ट्रंप ने इस यथार्थ को नहीं समझा तो फौरी तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भले ही थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, लेकिन आगे चलकर उसका आर्थिक संकट बढ़ेगा ही। ट्रंप स्वयं को लोकतंत्र के चैंपियन और विश्व व्यवस्था के निर्धारक के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे तानाशाह सरीखा व्यवहार कर रहे हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे अपने स्वार्थों के फेर में कई तानाशाहों को बड़ी ही बेशर्मी से गले लगा रहे हैं। एक ऐसे ही अघोषित तानाशाह पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं। भारत भले ही ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब न दे, लेकिन उसे अपने हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति पर अडिग रहना चाहिए।

नाले में डूबा तंत्र

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसी सप्ताह एक ऐसी दर्दनाक घटना घटित हुई, जिससे समूची व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक नाले के मुहाने का पत्थर टूटा होने के कारण बरसात में नाले में गिरकर सुरेश नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसे में यह एक बड़ा प्रश्न है कि इस व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहले भी हो चुकी हैं। कभी बच्चा बह गया तो कभी बुजुर्ग। ये घटनाएं कब रुकेंगी? होना तो यह चाहिए था कि इस शर्मनाक घटना पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि आश्वस्त करते कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसकी ठोस योजना भी बनाते, लेकिन उम्मीद धूमिल ही नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने हंगामा किया तो पार्षद के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली गई। अब पार्षद पूछ रहे हैं कि इसमें उनका दोष कैसे? अंगुलियां अधिकारियों की तरफ उठ रही हैं और वे भी पल्ला झाड़ने के प्रयास में हैं। नगर आयुक्त तो घटना वाले दिन ही कहते रहे कि जब तक शव नहीं मिलता, वह किसी के नाले में गिरकर बह जाने की बात नहीं स्वीकार करेंगे। हालांकि, इस प्रकरण पर ठेकेदार, अभियंता और सफाई के लिए जिम्मेदार फर्म पर भी कार्रवाई की गई है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के निष्कर्ष क्या होंगे, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जब तक अधिकारी, जनप्रतिनिधि समन्वय और सहयोग का पाठ नहीं सीखते, हर साल कोई न कोई सुरेश नाले में बहता रहेगा। इस प्रवृत्ति पर रोक के प्रयास होने चाहिए। इस प्रकार का मामला केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो। देश के अनेक शहरों में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लिहाजा इस पर अंकुश की जरूरत है।

> जब तक अधिकारी, जनप्रतिनिधि समन्वय और सहयोग का पाठ नहीं सीखते, हर साल कोई न कोई सुरेश नाले में बहता रहेगा

खतरे में लोकतंत्र–संविधान का बेसुरा राग

डा. एके वर्मा

किसी की ओर से भी संविधान के खतरे में होने और लोकतंत्र के लिए संकट खड़ा होने की बात करना भ्रम फैलाना एवं संविधान की अस्मिता पर हमले जैसा है

भारतीय लोकतंत्र और संविधान प्रारंभ से ही अनेक झंझावातों से गुजरा है। शुरू में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, शरणार्थी-पुनर्वास, औपनिवेशिक मानसिकता, पाकिस्तान एवं चीन विवाद आदि से विदेशी विद्वानों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह जाएगा। भारत की जनता, सरकार और विपक्ष ने उन्हें गलत साबित किया। आज स्थिति विचित्र है। विपक्षी दल सत्तारूढ़ भाजपा/राजग को अपदस्थ करने हेतु न केवल उस पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन देश की संवैधानिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संविधान को ही लांछित करने का प्रयास करते हैं। यह लोकतंत्र के आत्मा पर प्रहार करने जैसा है। संविधान, संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक प्रक्रियाएं लोकतंत्र का आत्मा हैं। विपक्षी दल इन पर लगातार आक्रामक हैं। नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता संविधान की प्रति लहराकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान खतरे में है और उन्हें उसे बचाना है। संविधान में संशोधन करने और उसके खतरे में होने में बहुत फर्क है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि सरकार/संसद संविधान में बदलाव या संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के 'मूल-ढांचे' में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।

जो नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे स्वयं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। इसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। साफ है कि किसी के भी द्वारा संविधान नष्ट या उसके खतरे में होने और लोकतंत्र के लिए संकट खड़े हो जाने की बात करना भ्रम फैलाना और संविधान की अस्मिता पर आक्रमण जैसा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बार संविधान को केवल बदलने का ही नहीं, वरन नष्ट करने का भी प्रयास किया। 1959 में प्रधानमंत्री नेहरू ने केरल में नंबूदरीपाद की निर्वाचित वामपंथी सरकार को अकारण भंग कर अनुच्छेद 356 का मनमाना इस्तेमाल किया। जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने हेतु अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर आपातकाल लगाया तथा लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर हजारों नेताओं एवं बेगुनाह लोगों को 'मीसा' और 'डीआइआर' जैसे कठोर कानूनों के अंतर्गत जेल भेज दिया। इनमें 'अपील, दलील और वकील' का प्रविधान ही न था। अनेक दलों के नेता, जिन्हें कांग्रेस ने आपातकाल में जेलों में ठूंस दिया था, वे भी मोदी विरोध के चलते आज उसी कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं। आपातकाल में अखबारों पर 'सेंसरशिप' लगा दी गई थी। उसी दौरान कांग्रेस ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कुछ बड़े बदलाव किए और ऐसे प्रविधान जोड़े, जिसे संविधान-निर्माताओं ने अस्वीकार कर दिया था। इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय तक को नहीं छोड़ा और तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तियों की उपेक्षा कर न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था।

अवधेश राजपूत

विपक्ष काफी समय से संवैधानिक संस्थाओं और खासकर चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। चूंकि चुनाव ही सत्ता की सीढ़ी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में परास्त होने और अनेक राज्यों में अप्रासंगिक होने से चुनाव आयोग पर आरोप तथा लांछन लगाना विपक्ष के लिए काफी आसान हो गया है। कभी वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों और निर्णयों पर अंगुली उठाता है, कभी उसे भाजपा के इशारे पर काम करने वाला बताता है, कभी ईवीएम, मतदाता सूची में अनियमितता, डाटा देने में विलंब, दलीय पक्षपात आदि का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग की छवि नष्ट करने का प्रयास करता है। अनेक राज्यों में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार आदि के अवैध घुसपैठियों ने फर्जी तरीकों से आधार, पैन, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्राप्त कर कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूचियों में अपना नाम अंकित करा लिया है। यह लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि केवल भारतीय नागरिकों को ही मत देने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने इस पर अपना रुख सख्त करते हुए सभी राज्यों में 'मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण' का निर्णय लिया है। बिहार में वह ऐसे लोगों की पहचान संबंधी पहल कर चुका है, पर विपक्ष को इस पर आपत्ति है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी। न्यायालय ने आयोग की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। देखना है कि न्यायालय इस पर क्या अंतिम निर्णय लेता है?

राहुल गांधी तो विदेश में भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। गत अप्रैल में उन्होंने अमेरिका में भारतीय चुनाव प्रणाली पर 'गंभीर अनियमितताओं' का आरोप लगाया। जब नेता-प्रतिपक्ष ही लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश में ऐसे अनर्गल आरोप लगाएगा, तो न केवल भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक छवि खराब होगी, वरन जनता के मन में भी शंका उत्पन्न होगी। देश में मतदाताओं, प्रत्याशियों और दलों की विशाल संख्या, चुनावों की बारंबारता, प्रक्रियाओं की जटिलता, तकनीकी-प्रशासकीय चुनौतियां, सांप्रदायिक और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता आदि को समायोजित कर अत्यधिक मेहनत से संपन्न की जाने वाली कठिन चुनाव प्रक्रिया पर नेता और राजनीतिक दल एक मिनट में कालिख पोत देते हैं। यह अक्षम्य अपराध है। संभव है कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ अधिकारी, कर्मचारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में गलती करें, कुछ क्षेत्रों में जाने-अनजाने कोई त्रुटि हो, कुछ मतदाता सूचियों में कहीं अनियमितताएं भी दिखें, लेकिन चुनाव आयोग उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करता है और चिह्नित लोगों को विधि अनुसार दंड भी देता है, लेकिन विपक्ष द्वारा संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को लांछित करना अनुचित और अवांछनीय है।

यदि विपक्षी दलों ने लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा, तो जनता की आस्था लोकतंत्र और संविधान में घट सकती है जो लोकतंत्र, सत्तापक्ष और विपक्ष सभी के लिए हानिकारक होगी।

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स में निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

राष्ट्रशक्ति में रूपांतरित हो जनशक्ति

डा. सुरजीत सिंह

यदि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार में सही तरीके से उचित निवेश करे, तो सच में बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है

भारत जैसे विकासशील देश के लिए जनसंख्या एक दोधारी तलवार जैसी है। एक ओर यह देश की ऊर्जा और श्रमशक्ति का स्रोत है, दूसरी ओर यह संसाधनों पर अत्यधिक दबाव भी डाल रही है। पहले की पीढ़ियां बड़ी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी और पारिवारिक मजबूती के रूप में देखती थीं, परंतु आज का युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरणीय असंतुलन के संकटों जैसे प्रदूषण, जल संकट, जैव विविधता के ह्रास आदि को लेकर अधिक सजग है। इसलिए अब बहुत से लोग जनसंख्या को केवल संख्या नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। ग्रामीण युवाओं में भी जनसंख्या और परिवार नियोजन के प्रति चेतना बढ़ी है। स्कूलों में अब यौन शिक्षा और परिवार नियोजन को सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। लड़कियों में आत्मनिर्भरता की भावना बताती है कि शिक्षा प्राप्त लड़कियां प्रजनन संबंधी निर्णय स्वयं लेना चाहती हैं। युवाओं का दृष्टिकोण अब ज्यादा वैज्ञानिक, व्यावहारिक और भविष्य-केंद्रित होता जा रहा है।

डिजिटल युग और बेहतर शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं को परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण नीति और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अधिक जागरूक बनाया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, आदि प्लेटफार्म मोबाइल एप, आनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं, जनसंख्या से जुड़े अभियान के माध्यम से वे अधिक सजग और जागरूक हुए हैं। आज का युवा परिवार नियोजन पर खुलकर बात करता है और इस विषय पर संवाद को प्रोत्साहित भी करता है। स्मार्ट फैमिली-स्मार्टर फ्यूचर सोच वाला युवा बड़े परिवार के बजाय गुणवत्तापूर्ण जीवन, करियर, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व देता है। युवाओं को समझ आ चुका है कि बढ़ती जनसंख्या न केवल संसाधनों को प्रभावित करती है, बल्कि बेरोजगारी, झुग्गी-झोपड़ियों के फैलाव, प्रदूषण और सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है।

यदि जनसंख्या को कुशल मानव संसाधन में बदला जाए तो वह आर्थिक विकास का इंजन बन सकती है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि गर्भनिरोधक तरीकों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 19 वर्ष की लड़कियों में गर्भधारण दर 7.9 से घटकर 6.8 प्रतिशत रह गई है, जो इसका स्पष्ट संकेत है कि जनसंख्या नियोजन अब एक निजी जिम्मेदारी का विषय बनता जा रहा है। यह सर्वेक्षण समाज में उभरती नई प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है कि 20 से 24 वर्ष की 21.2 प्रतिशत लड़कियों द्वारा विवाह पूर्व भी गर्भनिरोधक का उपयोग किया गया। यह इसे स्पष्ट करता है कि महिलाओं की यौन शिक्षा एवं उनकी निर्णय क्षमता में वृद्धि हुई है। जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने से लगभग 45.5 प्रतिशत युवतियां आधुनिक गर्भनिरोधकों का उपयोग करती हैं। शिक्षा के प्रसार से होने वाले शहरीकरण से सिर्फ युवाओं की जीवनशैली ही नहीं, बल्कि प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। शिक्षा, डिजिटल पहुंच और नीतिगत परिवर्तन ने युवाओं को स्वतंत्र और जागरूक निर्णयकर्ता बना दिया है।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से बदलती तस्वीर। फाइल

जनसंख्या के प्रति अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण, जागरूकता और सक्रियता को देखते हुए आवश्यकता इसकी है कि भारत की जनसंख्या नीति को युवा-केंद्रित बनाया जाए, ताकि भारत न केवल जनसंख्या नियंत्रण, बल्कि जनसंख्या प्रबंधन और नवोन्मेष में विश्व का नेता बने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का विश्लेषण बताता है कि यदि भारत अपने युवाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सही तरीके से सही निवेश करे, तो 2040 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। नीति आयोग रिपोर्ट भी यह रेखांकित करती है कि युवा अब केवल नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि उद्यमी, स्टार्टअप निर्माता और नवप्रवर्तक के रूप में उभर रहे हैं। नीति आयोग का सुझाव है कि जनसंख्या नीति में युवाओं की सीधी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे वे स्वयं अपनी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य योजनाओं के निर्णयों में सह-निर्माता बन सकें।

15 से 34 वर्ष की 65 प्रतिशत आबादी के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक युवा देश है, जिसकी औसत आयु 29 वर्ष है। 2030 तक युवाओं की अनुमानित जनसंख्या 85 करोड़ हो जाएगी। यदि हम इस श्रम बल को कुशल बना पाए तो आर्थिक अवसर की सबसे बड़ी खिड़की भारत के समक्ष खुल सकती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 24 वर्ष के 22 प्रतिशत बेरोजगार युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत की 15 से 35 वर्ष की 52 प्रतिशत शहरी आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बनाने से न सिर्फ गरीब और अमीर के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में अंतर समाप्त होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े राज्यों में उच्च प्रजनन दर पर भी इसका असर पड़ेगा। इस युवा आबादी को देश के आर्थिक विकास का इंजन बनाने के लिए एक समन्वित मानव पूंजी विकास रणनीति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। इसके लिए कौशल विकास, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और स्वास्थ्य संरचना में सुधार कर इस कार्यशील आबादी का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। अब हमें जनसंख्या को नंबर की तरह नहीं, बल्कि संभावनाओं और अधिकारों के नजरिये से देखना चाहिए, जिससे जनशक्ति को राष्ट्रशक्ति में बदला जा सके।

(लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

बीज से वृक्ष की यात्रा

न्यूटन ने धरती पर गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को पहचाना था। देखा जाए तो इसमें धरती के आकर्षण से कुछ अधिक व्यापक सत्य यह है कि सेब धरती पर गिरा एक से अनेक होने के लिए। बीज की समग्र जीवन-शक्ति अपने वंश-विस्तार में संलग्न होती है। यही तथ्य सृष्टि-विस्तार को स्पष्ट करता है। स्थिर और निर्जीव सा प्रतीत होने वाला बीज धरती की कोख में पहुंचकर आकाश, हवा, पानी और सूरज का संस्पर्श पाकर गतिशील होकर वृक्ष बनता है, क्योंकि बीज में एक से अनेक होने का संकल्प है। प्रत्येक बीज में वंशवृद्धि की मूल प्रवृत्ति है।

इतना सूक्ष्म बीज विशाल वृक्ष कैसे बन जाता है? बीज का उगना विराट प्रकृति की कितनी ही छोटी घटना क्यों न सही, लेकिन बीज के माध्यम से मनुष्य ने प्रकृति को, प्राणियों को तथा जीवन को समझने का प्रयास किया है। बीज में जड़, शाखा, तना, फल, फूल और पत्ता दिखाई नहीं देता, परंतु बीज में उनका अस्तित्व विद्यमान है। भले वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। इसलिए बीज और वृक्ष भिन्न नहीं हैं। यदि सूक्ष्म न हो तो विराट की कल्पना नहीं की जा सकती। बीज वृक्ष की सुप्तावस्था है और वृक्ष बीज की जागरण अवस्था है। बीज से वृक्ष होने की यात्रा में कुछ अन्य उपकारक तत्व भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बीज वृक्ष नहीं बन पाता। बीज की भांति हमारे भीतर भी व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं, बस उन्हें साकार रूप देने में अपेक्षित पुरुषार्थ करने की देर है। कोई पुष्प नहीं जानता कि उनमें से कौन देवता के सिर चढ़ेगा और कौन श्मशान घाट जाएगा। हम पांच पंखुड़ी (पंचतत्व) वाले पुष्पों की जीवनयात्रा और भविष्य भी इन पुष्पों की तरह ही है। अंततः हमें भी खाक बन जाना है। विधि के ऐसे ही विधान में हमारा वैसा ही पुष्प बनकर जीना सफल है, जो अपने बीज वसुधा में छोड़ जाए और सुगंध आसमान में।

डा. निर्मल जैन

मोबाइल से मतदान की अभिनव पहल

ढोंढ़राज सुथार

ई-वोटिंग प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए

मतदान प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और समावेशी बनाना भारत में एक बड़ी चुनौती रही है। स्थानीय निकाय चुनावों में मोबाइल फोन आधारित ई-वोटिंग प्रणाली को लागू करने का बिहार का कदम इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। बिहार इस नवाचार को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 70.2 प्रतिशत मतदाताओं ने इस नई प्रणाली का उपयोग किया, जबकि 54.63 प्रतिशत ने पारंपरिक मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया। यह रुझान न केवल ई-वोटिंग की स्वीकार्यता को दर्शाता है, बल्कि इसके व्यापक उपयोग और भविष्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने की संभावनाओं को भी रेखांकित करता है।

लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग मतपेटी तक अपनी आवाज पहुंचा पाते हैं। भारत में, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में मतदान केंद्रों तक पहुंचना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। भौगोलिक दूरी, खराब परिवहन सुविधाएं, खराब मौसम की स्थिति और शारीरिक अक्षमता जैसे कारक मतदाताओं को मतदान करने से रोकते हैं। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में व्यस्त जीवनशैली और समय की कमी भी मतदान प्रतिशत को प्रभावित करती है। ई-वोटिंग इस समस्या का एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है। मोबाइल फोन आधारित मतदान प्रणाली मतदाताओं को अपने घर से, अपनी सुविधानुसार, सुरक्षित और तेजी से मतदान करने का अवसर प्रदान करती है।

हालांकि, ई-वोटिंग की राह चुनौतियों से खाली नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा है। डिजिटल वोटिंग सिस्टम को हैकिंग, डाटा चोरी और साइबर हमलों से बचाना अनिवार्य है। इसके लिए मजबूत एन्क्रिप्शन, सुरक्षित सर्वर और नियमित साइबर आडिट की आवश्यकता होती है। बिहार में लागू की गई प्रणाली ने इस दिशा में कदम उठाए, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए अधिक व्यापक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी। दूसरी चुनौती डिजिटल साक्षरता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग अभी भी स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से अनजान हैं। ऐसे में ई-वोटिंग को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान और तकनीकी प्रशिक्षण जरूरी है। तीसरी चुनौती तकनीकी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की कमी ई-वोटिंग में बाधा बन सकती है। इन समस्याओं को हल किए बिना इस प्रणाली को पूरी तरह लागू करना मुश्किल होगा।

बिहार के प्रयोग से साफ है कि लोग इस प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इसे सरल-सुरक्षित बनाया जाए। भविष्य में इसे और प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। यह प्रयोग अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाए तो भारत का लोकतंत्र और अधिक सशक्त और समावेशी बन सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सुनिश्चित हो प्रशासन की जवाबदेही

'निराश और हताश करती नौकरशाही' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने देश के प्रशासनिक तंत्र को लेकर सामयिक, यथार्थ और सटीक विवेचना की है। लचर प्रशासन तंत्र के कारण लज्जाजनक और दुखद घटनाएं घटित हो रही हैं। गुजरात का पुल हादसा इसका हालिया उदाहरण है। यह दर्शाता है कि हर जगह भ्रष्टाचार है। ऐसे मामलों में लोग जब आवाज उठाते हैं तो खानापूर्ति के नाम पर उसकी केवल जांच होती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं। कुछ कर्मियों को निलंबित कर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। सरकार नौकरशाही की कार्यप्रणाली देख रही है, जिसमें सक्रियता और कर्तव्यनिष्ठा का घोर अभाव दिखता है। उसे सुधारने और जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए अनुशासित, सक्रिय और जवाबदेह प्रशासन तंत्र सुनिश्चित करना ही होगा। लंबित पड़े प्रशासनिक सुधारों को मूर्त रूप देने में अब और देरी नहीं की जानी चाहिए।

कुलदीप मोहन त्रिवेदी, जरगांव, उन्नाव (उप्र)

पूर्वोत्तर में घुसपैठ पर नियंत्रण

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि उनके राज्य में स्वदेशी एवं मूल निवासी एक मत विशेष के लोगों की घुसपैठ से अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। कारण इस घुसपैठ से पूरे असम की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है एवं इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है आसपास के राज्यों से हो रही असम प्रदेश में घुसपैठ। फिर असम पिछले कई दशकों से बांग्लादेशी मुस्लिमों के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। उनका कहना है कि असम में बांग्ला भाषी सहित हर भारतीय नागरिक हमारी स्थिति को पूरी तरह से समझता है और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारे अडिग रुख का समर्थन भी करता है। एक तथ्य यह भी है कि भारत की स्वतंत्रता के समय राज्य के 35 जिलों में से एक भी जिला मुस्लिम बाहुल्य नहीं था, परंतु आज देखते ही देखते लगभग 15 जिले मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। वैसे यह दशा पिछले कई दशक से जारी है, क्योंकि यहां बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठ होता आ रहा है। यह स्थिति इस राज्य के लिए वाकई में चिंताजनक है, जिसे तत्काल नियंत्रित करने किए जाने की आवश्यकता है।

मनमोहन राजावत, शाजापुर, मध्य प्रदेश

मेलबाक्स

साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान

आज का डिजिटल युग जहां एक ओर हमें ढेरों सुविधाएं प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी भी नित नए तरीकों से आम नागरिकों को ठगने में लगे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की 2025 की रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। इस साल जनवरी से जून तक देशभर में साइबर फ्राड की 60 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 22 हजार शिकायतें तो सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थीं। इसका सीधा अर्थ है कि हर दिन औसतन 350 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी के सबसे आम तरीकों में शामिल हैं: फर्जी बैंक काल और केवाइसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी। इंटरनेट मीडिया पर लिंक भेजकर व्यक्तिगत डाटा चुराना। क्यूआर कोड स्कैम। नौकरी, लाटरी और इनाम जैसे झूठे वादों से लोगों को फंसाना। नकली आनलाइन शापिंग वेबसाइटों के जरिए ठगी। सबसे दुखद बात यह है कि वर्तमान वर्ष की पहली तिमाही में ही लोगों को लगभग 1,600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें से मात्र छह प्रतिशत राशि ही वापस मिल पाई है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं : साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। संबंधित पोर्टल की जानकारी स्थानीय भाषाओं में आम जनता तक पहुंचाई जाए। प्रत्येक जिले में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाएं। स्कूल-कालेज स्तर पर डिजिटल सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इससे आरंभिक समय से ही छात्रों में जागरूकता का प्रसार होगा।

चंदन कुमार, पत्रकारिता विभाग, चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

36 प्रतिशत वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी है ब्रिक्स देशों की, जबकि वर्ष 2030 तक ब्रिक्स का वैश्विक उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान होगा। वहीं, विश्व के 72 प्रतिशत दुर्लभ खनिज भंडार ब्रिक्स देशों के पास हैं।

विक्रांत निर्मला सिंह
शोधार्थी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

ब्रिक्स

नई विश्व व्यवस्था बनाने में सक्षम मंच

ब्राजील में हालिया आयोजित ब्रिक्स शिखर बैठक दो प्रमुख कारणों से वैश्विक चर्चाओं का केंद्र बनी। पहला, अमेरिका की इस मंच को लेकर असहजता और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण संरक्षण और सीमा-पार आतंकवाद जैसे विषयों पर दिए गए ठोस वक्तव्य। इन दोनों घटनाओं के निहितार्थ आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य को समझने के लिए आवश्यक हैं। वस्तुतः अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में नेतृत्वकारी भूमिका के दम पर एकध्रुवीय व्यवस्था को बनाए रखा है, जिसे ब्रिक्स सीधे चुनौती दे रहा है

ब्राजील में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत सदस्य देशों के प्रतिनिधि। फाइल

अधिकांश वैश्विक संगठनों में अमेरिका अब तक प्रभावी भूमिका में रहा है। यह भी कह सकते हैं कि उसका वर्चस्व अन्य देशों की तुलना में कहीं बहुत अधिक रहा है। ऐसे में ब्राजील में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स की शिखर बैठक को विशेष संदर्भ में देखा जा सकता है। वस्तुतः इस बैठक में इस मंच के प्रति अमेरिका का असहज होना स्पष्ट रूप से दिखा, जबकि भारत ने अपने हितों से संबंधित मामलों को तथ्यों के साथ मजबूती से रखा। यहीं से ही एक बड़ा अंतर महसूस किया जा सकता है।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जलवायु परिवर्तन और उभरती तकनीकों को ब्रिक्स के एजेंडे में लाना इस मंच को वैश्विक भविष्य की दिशा तय करने वाला एक वैचारिक और नैतिक नेतृत्व मंच बनाने की शुरुआत है। इसका सीधा आशय था कि ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक मंच नहीं, बल्कि वैश्विक नीति और विमर्श को दिशा देने वाला एक प्रभावशाली मंच है। यही कारण है कि अमेरिका में असहजता गहराती जा रही है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों पर भारी शुल्क लगाने की चेतावनी इस बेचैनी का स्पष्ट संकेत है। क्योंकि आज ब्रिक्स अन्य वैश्विक मंचों में कुछ पश्चिमी देशों के एकाधिकार की नीति के बिलकुल उलट सदस्य देशों के लिए विकास और समावेशिता का नया मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। इस बार की बैठक में जो साझा घोषणा-पत्र जारी किया गया, वह ब्रिक्स की भविष्य दृष्टि और वैश्विक योगदान को स्पष्ट करता है। यह दस्तावेज बहुपक्षीयता को सुदृढ़ करने, अंतरराष्ट्रीय कानूनों की रक्षा करने और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की बात करता है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ब्रिक्स में बढ़ती दिलचस्पी : पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स ने स्वयं को पश्चिमी गुट, विशेषकर जी-7 की तुलना में एक समतामूलक मंच के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि दुनियाभर की उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा बनना चाहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स को लेकर यह आकर्षण इतना बढ़ा कि वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए सम्मेलन में 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता में रुचि दिखाई, और 22 देशों ने औपचारिक आवेदन किया था। इस बढ़ती दिलचस्पी के पीछे दो प्रमुख कारण हैं : पहला, सभी सदस्य देशों को बराबरी का स्थान और निर्णय में समान भागीदारी। दूसरा, यह समूह आर्थिक संभावनाओं और व्यावहारिक विकास के नए द्वार खोल रहा है, विशेषकर उन देशों के लिए जिन्हें पारंपरिक पश्चिमी संस्थानों में अक्सर हाशिए पर रखा गया।

यहां इस बात को भी समझना आवश्यक है कि आइएमएफ जैसी संस्थाओं में उभरते देशों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुपात में अधिकार नहीं है। इसके अलावा ब्रिक्स ''वीटो'' जैसे विशेषाधिकारों के आधार पर निर्णय नहीं थोपता है। उदाहरण के लिए, ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में सभी सदस्य देशों के पास एक वोट होता है। इसके अलावा, यह बैंक 'कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट' के अंतर्गत सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने में तत्काल सहायता भी प्रदान करता है। यही विशेषता ब्रिक्स को जी-7 और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से अलग और अधिक लोकतांत्रिक बनाती है।

वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी ब्रिक्स एक व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत करता है। वर्ष 2010 में इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा मात्र 18 प्रतिशत था और उस समय इसे जी-7 के मुकाबले एक 'कमजोर आवाज' माना जाता था, किंतु अब यह धारणा टूट चुकी है। वर्ष 2023 में पहली बार ब्रिक्स देशों की सम्मिलित जीडीपी (क्रय शक्ति समता के आधार पर) जी-7 समूह की कुल जीडीपी से अधिक हो गई। इसके अलावा, नामिनल जीडीपी के आधार पर ब्रिक्स 2030 तक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में होगा, जो वैश्विक उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान देगा। इसके अलावा, अन्य आर्थिक संकेतक भी ब्रिक्स की बढ़ती ताकत को रेखांकित करते हैं। यह समूह वैश्विक निर्यात में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, कच्चे तेल का 43 प्रतिशत उत्पादन करता है और दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ मिनरल्स) का 72 प्रतिशत से अधिक भंडार अपने पास रखता है। ब्रिक्स वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे मानव संसाधन के दृष्टिकोण से समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

डालर के वर्चस्व को चुनौती : दशकों से अमेरिकी डालर वैश्विक वित्तीय प्रणाली का केंद्र बिंदु रहा है, किंतु ब्रिक्स देशों ने इस डालर-आधारित व्यवस्था के समानांतर एक नई प्रणाली की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। विशेष रूप से सदस्य देश आपसी व्यापार में अपनी स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत-रूस और रूस-चीन के बीच हाल के वर्षों में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ब्रिक्स द्वारा एक साझा मुद्रा विकसित करने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। विशेष रूप से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा के इस पर बयान के बाद चर्चा तेज हो गई। यद्यपि एक साझा मुद्रा का निर्माण तकनीकी, राजनीतिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण से आसान नहीं है, फिर भी यह अमेरिकी डालर के वैश्विक प्रभुत्व को सांकेतिक चुनौती देने जैसा है। यही कारण है कि आज पश्चिमी देशों में ब्रिक्स की इन डी-डालराइजेशन पहलों को लेकर गंभीर चिंता देखी जा रही है।

पश्चिमी देशों की चिंता : पश्चिमी देशों की इस चिंता को ऊर्जा क्षेत्र के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। वर्तमान में दुनिया के बड़े तेल उत्पादक रूस, ईरान और सऊदी अरब और दो सबसे बड़े उपभोक्ता चीन और भारत ब्रिक्स मंच का हिस्सा हैं। यदि इन देशों के बीच डालर के स्थान पर घरेलू मुद्राओं या किसी वैकल्पिक माध्यम से तेल व्यापार शुरू हो जाता है, तो यह डालर की प्रतिष्ठा को सीधी चुनौती होगी। उदाहरण के लिए, जब भारत ने प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल की खरीद स्थानीय मुद्रा में आगे बढ़ाई थी, तब अमेरिका और यूरोप की खीझ दिखाई पड़ी थी। इसलिए यदि ब्रिक्स देश आपसी व्यापार के लिए एक सफल गैर-डालर व्यापार माडल तैयार कर लेते हैं, तो इससे वैश्विक लेनदेन में डालर की मांग घटेगी और अंततः अमेरिका की आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रभुत्व पर गहरा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स की गतिविधियों को एक उभरते प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप द्वारा ब्रिक्स सदस्य देशों पर टैरिफ लगाने की खुली धमकी चाहे कठोर और अतिवादी हो, परंतु यह सच है कि ब्रिक्स का डी-डालराइजेशन एजेंडा दीर्घकाल में डालर की वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकता है।

यही कारण है कि आज विश्व स्वीकार कर रहा है कि ब्रिक्स एक वास्तविक प्रभाव रखने वाला ध्रुव है। ब्रिक्स देशों में अब पश्चिमी प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा। हालांकि, इसके बावजूद ब्रिक्स अभी वैश्विक नेतृत्व के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि ब्रिक्स के भीतर आंतरिक मतभेद स्पष्ट हैं। चीन और रूस जहां तेजी से नए सदस्यों को जोड़कर प्रभाव क्षेत्र का विस्तार चाहते हैं, वहीं भारत और ब्राजील इस विस्तार को लेकर आशंकित हैं कि इससे समूह में उनका अनुपातित प्रभाव कम न हो जाए। इसी प्रकार, सऊदी अरब और ईरान जैसे पारस्परिक प्रतिद्वंद्वी अब एक ही मंच पर हैं, तो उनके बीच की तनातनी को संभालना ब्रिक्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त, लोकतांत्रिक भारत और ब्राजील बनाम अधिनायकवादी चीन और ईरान की वैचारिक भिन्नता भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसलिए जहां एक ओर ब्रिक्स की विविधता इसे समावेशी बनाती है, वहीं दूसरी ओर यही विविधता आंतरिक एकता के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। फिर भी, आज ब्रिक्स ने विश्व मंच पर परिवर्तन की जो आहट दी है, उसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता।

'गैर-पश्चिमी' से 'नए वैश्विक मंच' का दिया जाए रूप

ब्रिक्स मंच पर भारत की भूमिका केवल एक सहभागी देश की नहीं, बल्कि एक संतुलनकारी नेतृत्वकर्ता की है। इस समूह में जहां एक ओर चीन और रूस अमेरिका एवं पश्चिमी गुटों के साथ सीधे टकराव में हैं, वहीं भारत की विदेश नीति बहुध्रुवीय संवाद और सहभागिता पर केंद्रित है। यही दृष्टिकोण भारत को ब्रिक्स के भीतर एक ऐसा केंद्र-बिंदु बनाता है, जो इसे पश्चिमी देशों और ब्रिक्स के बीच एक पुल की तरह प्रस्तुत करता है। भारत की यह क्षमता केवल आर्थिक आकार से नहीं, बल्कि उसकी बहुध्रुवीय कूटनीतिक सक्रियता से है।

भारत आज क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन, जी-20, जी-7 आमंत्रण समूह और ब्रिक्स में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इन विविध मंचों में भारत की स्वीकार्यता उसे एक विश्वसनीय 'ब्रिज-नेशन' बनाती है। विशेष रूप से 'ब्रिक्स प्लस' विस्तार के संदर्भ में भारत को चाहिए कि वह अपनी रणनीति स्पष्ट रखे और ऐसे देशों की सदस्यता का समर्थन करे जो न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हों, बल्कि राजनीतिक रूप से संतुलित, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में विविधता लाने वाले हों। भारत को आज चाहिए कि वह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया के देशों को शामिल कराने की दिशा में निरंतर अग्रसर रहे। इस रणनीति से भारत इस मंच को चीन अथवा रूस के प्रभाव में झुकने के बजाय ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ा सकता है।

भारत यदि ब्रिक्स प्लस के विस्तार को संतुलित, समावेशी और दक्षिणमुखी बनाए रखने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है, तो वह न केवल इस समूह की स्थिरता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य की बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में भी अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ भी करेगा।

(विक्रांत निर्मला सिंह)

खरी-खरी

लौट के बुद्धू घर को आए

रेखा शाह आरबी

मैदानी भागों में रहने वालों को पहाड़ लुभाते हैं। ऐसे में गजोधर भी पहाड़ों के मोह से मुक्त नहीं थे। उनकी तो अपने ब्याह के समय ही इच्छा थी कि वह हनीमून के लिए पहाड़ पर जाएं। पर खर्चे ने सोचने पर मजबूर कर दिए थे। खैर शादी के पांच साल बाद मुहूर्त बन ही गया और वह पहाड़ पर पहुंच गए। लेकिन वहां पर उनके जैसे लाखों पहुंचे थे। जो जाम-झाम उनके शहर में था, उससे बढ़कर वहां पर था। गजोधर अपने मूड को सही करने आए थे। यहां तो उल्टे उनके मूड की बैंड बज गई। पहाड़ भीड़-भाड़ वाले स्थान बन चुके थे। तो भड़क के बोल पड़े- बताओ इनके घर आए हैं और यह मुंह फुलाए हैं, मेहमानों की तो कदर ही नहीं है।

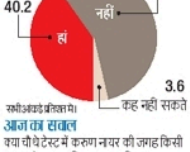

तो पहाड़ भी मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें देखकर मुंह न फुलाया जाए तो क्या किया जाए। नदी, तालाब, झरने सभी गुस्से, तकलीफ, पीड़ा के मारे उफन रहे हैं। अपने ही दुख में परेशान हैं। और तुम लोगों को मरने के लिए यहीं आना है। अरे इतने छोटे काम के लिए तुम सभी को यहां पर आने की क्या जरूरत है। वह तो सीवर, खुले मेनहोल, सड़क उफन रहे या किसी न किसी गड्ढे में डूबकर तुम अपना यह कार्यक्रम कर सकते हो। इसके लिए पहाड़ों पर जाकर नदी, तालाब, झरनों का टेंशन क्यों बढ़ाते हो। थोड़ा उनकी इज्जत के बारे में भी सोचो, बेवजह ही बदनाम हो जाते हैं।

और बोलते-बोलते ऊपर से दो भारी पत्थर उनकी कार के आगे गिराए तो गजोधर की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। वह कार घुमा कर घर की तरफ भागे। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।

उधर पहाड़ बड़बड़ा रहा था- इस बरसाती मौसम में न जाने क्यों सारे मूर्ख यहीं पर चले आ रहे हैं... मरने के कितने सारे आप्शन मैदानों में हैं। एक दूसरे के धर्म से लड़कर मरो या अगर यह रुचिकर नहीं लगे तो आजकल तो हर देश लड़ने मरने पर उतारू है। तो युद्ध क्षेत्र में चले जाओ, इतने बम-बारूद बरसाए जा रहे हैं कि धरती त्राहि त्राहि कर रही है। वहां पर मरने की बहुत सुविधा है। कम से कम हम पहाड़ को बख्श दो और शांति से जीने दो।

पोस्ट

लगता है कि देश में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं। राधिका यादव की हत्या से लेकर ओडिशा में छात्रा द्वारा आत्महत्या करना, केरल की महिला का मामला हो या कोलकाता में आरजी कर अस्पताल से लेकर ला कालेज में छात्रा के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के उत्पीड़न का सिलसिला अंतहीन दिखता है।
पल्लवी घोष@_pallavighosh

माना कि समोसा, जलेबी और लड्डू वगैरह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। इन्हें अधिक मात्रा में खाने से मोटापा, कोलेस्ट्राल और शुगर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस बहस में सवाल यह भी है कि बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, चाउमीन और मोमो वगैरह क्या खून बढ़ाते हैं? धमनियों में रक्त संचार बेहतर करते हैं? या शुगर कंट्रोल करते हैं?
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

भारत, चीन यदि रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो क्या अमेरिका 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा? क्या यूक्रेन के नाम पर अमेरिका भारत के साथ रिश्तों की बलि चढ़ा देगा? ऐसी धमकियां और बातें कुछ और नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक सनक या कहें पागलपन है।
कंवल सिब्बल@KanwalSibal

जागरण जनमत — कल का परिणाम

सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट को राहत देकर सही किया?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या चौथे टेस्ट में करुण नायर की जगह किसी अन्य को अवसर दिया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दही जलेबी छोड़कर खाओ मस्त सलाद,
सेहत पर करता असर खट्टा-मीठा स्वाद।
खट्टा-मीठा स्वाद बहुत जिह्वा को भाता,
पर करके बीमार आपको मजा चखाता।
बंधु दीजिए छोड़ पड़ी जो आदत ऐसी,
खाओ हेल्दी फूड छोड़कर दही जलेबी!
- ओमप्रकाश तिवारी

सद्गुरु शरण
संपादक, नईदुनिया, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश डायरी

महिलाओं से डिलीवरी डेट पूछते सांसद

मध्य प्रदेश में भाजपा लगभग दो दशक से सत्तासीन है, यद्यपि अब कुछ ऐसा हो रहा जो पहले कभी नहीं होता था। ऐसा लगता है कि सत्ता और संगठन के शीर्ष पदों पर विराजमान वरिष्ठ भाजपाई पावर का नशा पचा नहीं पा रहे। संलग्न तस्वीर सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव से गुजरने वाली 10 किमी लंबी सड़क की है जिसके सुधार के लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री का भी ध्यानाकर्षण करवा चुके हैं। इसके बावजूद शासन और प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी और इस वर्ष बारिश होते ही सड़क इस हालत में आ गई तो गांव की एक पढ़ी-लिखी एवं जागरूक महिला लीलावती साहू ने गत आठ जुलाई को एक वीडियो प्रसारित करके शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा।

दरअसल, लीलावती गर्भवती हैं, लिहाजा उन्होंने सड़क की बदहाली के कारण गर्भवती महिलाओं की चिंता एवं परेशानी का मुद्दा उठाया। इस पर भाजपा के दिग्गज नेताओं को मिर्च लग गई। स्थानीय सांसद राजेश मिश्रा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि गर्भवती महिला की डिलीवरी डेट तय रहती है, कृपया अवगत करा दें। हम उन्हें डिलीवरी से एक सप्ताह पहले उनके घर से उठवाकर अस्पताल भिजवा देंगे। भाजपाइयों का गुस्सा इतने पर नहीं थमा। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, ने ग्रामीणों की परेशानी पर सांत्वनादायक जवाब देने के बजाय प्रश्नवाचक प्रतिक्रिया व्यक्त की, कि ऐसे कोई वीडियो बनाकर प्रसारित कर देगा तो क्या सड़क बन जाएगी?

विडंबना है कि जो भाजपा अपनी बोलचाल की संयमित शैली और अनुशासन के लिए किसी समय 'पार्टी विद डिफरेंस' कही जाती थी, उसके नेताओं का सत्ता के नशे में अब ऐसा रवैया हो चुका है। एक जागरूक महिला के प्रति अशोभनीय टिप्पणी का यह प्रकरण उसी मध्य प्रदेश का है जिसकी भाजपा सरकार अपनी स्त्री-हितैषी नीतियों और व्यवहार के लिए देशभर में रोल माडल मानी जाती है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार विजय के लिए महिलाओं के एकतरफा समर्थन को श्रेय दिया जाता है। महिलाओं के प्रति इस सम्मान-भाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा जैसे संबोधन की लोक-उपाधि प्राप्त हुई जिस पर वह बहुत गर्व भी करते हैं। महिलाओं के सम्मान में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना समेत करीब डेढ़ दर्जन योजनाएं लागू कीं जिनकी लोकप्रियता देखकर कई अन्य राज्यों ने भी इन्हें अपनाया। प्रदेश में किसी भी शासकीय समारोह की शुरुआत कन्याओं के पैर पूजन से होती है। दुर्भाग्य है कि ऐसे राज्य में सांसद महिलाओं की डिलीवरी डेट जानना चाहते हैं और विभागीय मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि चाहे जितने वीडियो बना लो, सड़क इस तरह नहीं बनेगी। सड़क की मरम्मत करवाना मंत्री और सांसद की जिम्मेदारी है। उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए था कि शासन-प्रशासन की असंवेदनशीलता से हारकर प्रधानमंत्री का भी ध्यान आकृष्ट कराने के बाद ग्रामीणों को और क्या करना चाहिए जिससे सड़क बन जाए।

यही है सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव से गुजरने वाली बदहाल सड़क। वीडियोग्रैब

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का यह आचरण इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि हाल ही में पार्टी ने पचमढ़ी में अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए संवाद कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठों ने भाजपा नेताओं को प्रशिक्षित किया था कि उन्हें किस तरह संयम और अनुशासनपूर्वक पार्टी की रीति-नीति के आधार पर बोलना चाहिए। इस आयोजन की नौबत इसलिए आई, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के एक अन्य कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने आपरेशन सिंदूर में शामिल रहीं महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद निम्नस्तरीय टिप्पणी करके देश-दुनिया में भाजपा को शर्मिंदा करवा दिया था। आश्चर्य की बात है कि किसी कारणवश इस प्रकरण में भी भाजपा नेतृत्व तिलमिलाकर रह गया और विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आरएसएस और भाजपा की व्यवहार-शैली में संवाद को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इसी दृष्टि से प्रशिक्षण भी। इनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है कि उन्हें संवाद की किन संवेदनशीलताओं का ध्यान रखकर अपना पक्ष रखना चाहिए, यद्यपि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं की करतूत देखने के बाद संघ व भाजपा नेतृत्व यह सोचने पर बाध्य हुआ होगा कि इस प्रवृत्ति को किस तरह नियंत्रित किया जाए। अपने गांव के जागरूक प्रतिनिधि के तौर पर बदहाल सड़क के उद्धार की मांग उठा रही महिला को उसकी डिलीवरी डेट पूछकर अपमानित करने से अधिक निम्नस्तरीय आचरण क्या हो सकता है, भाजपा के साथ पूरे समाज के लिए विचारणीय है।

मंथन

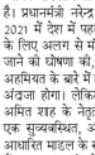

नीलू रंजन
nranjan@del.jagran.com

आत्मनिर्भर एवं खुशहाल गांव

गांवों को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से आरंभ किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभाव महज चार वर्षों में ही दिखने लगा है। वहीं, सहकारिता माडल धरातल पर सफल होता दिख रहा है

महानगरों की चकाचौंध और अर्थव्यवस्था के बड़े-बड़े आंकड़ों के बीच ग्रामीण जीवन में शांत, लेकिन व्यापक परिवर्तन की आहट मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब वर्ष 2021 में देश में पहली बार सहकारिता के लिए अलग से मंत्रालय आरंभ किए जाने की घोषणा की, तो इसकी असली अहमियत के बारे में शायद ही किसी को अंदाजा होगा। लेकिन चार वर्षों में ही अमित शाह के नेतृत्व में यह मंत्रालय एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और डाटा आधारित माडल के साथ ग्रामीण इलाकों में आम आदमी के जीवन में बड़े बदलाव का वाहक बनकर उभरा है।

एक ओर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बिना किसी बिचौलिए और शुल्क के किसानों को ऋण मुहैया कराकर उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सहकारी समिति से जुड़ी स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका जीवन संवारने का काम कर रहा है। एक समय में अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए चिंतित रहने वाली आदिवासी महिलाएं पोल्ट्री और डेयरी व्यवसाय से सालाना लाखों रुपये की कमाई कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाला सस्ता सरकारी ऋण ग्रामीण इलाकों में लखपति दीदियों की नई फौज तैयार कर रहा है। देखा जाए तो असली भारत हमारे गांवों में ही बसता है, जहां पहली बार सहकार से समृद्धि दस्तक दे रही है।

वैसे तो भारत सहकारी क्षेत्र की सफलता से पुराने समय से ही परिचित है। अमूल और इफको जैसी संस्थाएं दशकों से दुनिया में अग्रणी भूमिका में रही हैं। इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस ने 2024 में इन्हें दुनिया भर में टर्नओवर-टू-जीडीपी- प्रति व्यक्ति अनुपात के आधार पर पहले और दूसरे स्थान पर रखा था। ये उपलब्धियां पहले केवल प्रतिष्ठित ब्रांड्स तक सीमित थीं। लेकिन सहकारिता मंत्रालय अब उन्हें अंतिम छोर तक पहुंचा रहा है। दरअसल सहकारिता मंत्रालय ने लंबे समय से चली आ रही बिखरी और अप्रभावी सहकारी नीतियों से एकजुट और समन्वित तरीके से प्रभावी बनाने का प्रयास किया है।

सहकार से समृद्धि : सहकारिता मंत्रालय का सोच ''सहकार से समृद्धि'' पर आधारित है, जिसके माध्यम से एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और डाटा-आधारित माडल के माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव लाना है। आजादी के बाद से उपेक्षित सहकारिता क्षेत्र को पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का काम शुरू किया गया। इसके तहत 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 67 हजार से अधिक पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो रहा है और इन्हें कामन सर्विस सेंटर के रूप में बदला जा रहा है, जिसमें तीन सौ से अधिक सरकारी सेवाएं जैसे आधार का अपडेट करने और रेल टिकट बुकिंग तक की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम बड़ी मात्रा में सहकारी समितियों को सस्ता ऋण उपलब्ध करा रहा है। पिछले तीन वर्षों में यह 25 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आज की तिथि में साढ़े आठ लाख से अधिक सहकारी समितियों और लगभग 30 करोड़ सदस्यों का केंद्रीकृत डाटाबेस है, जिनके आधार पर ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं, जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी भागीदारी कुल कृषि ऋण में 20 प्रतिशत, उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत और चीनी उत्पादन में 31 प्रतिशत है। केवल डेयरी से जुड़ी सहकारी समितियों का देश की जीडीपी में 4.5 प्रतिशत का योगदान है।

सहकारी योजनाएं ग्रामीण इलाकों में व्यापक बदलाव की शुरुआत करने के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी इसे आगे बढ़ने की तैयारी है। इसके लिए सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना है, जिसमें ड्राइवर ही कंपनी के सह-मालिक होंगे।

आने वाले समय में मंत्रालय की कोशिश हर पंचायत में एक पैक्स की स्थापना करना है। इसके लिए दो लाख नए पैक्स बनाने होंगे। इससे सहकारिता गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। इन्हें पीएम किसान फसल बीमा और ग्रामीण कौशल विकास योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। सहकारी समितियां अब ग्रामीण विकास और उसमें जन भागीदारी का केंद्र बनकर उभरेंगी। इसके लिए सभी पैक्स को डिजिटल गवर्नेंस उपकरणों और स्थानीय संस्थाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके बाद ये समितियां प्रापर्टी का सत्यापन, ई-केवाइसी, विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं सुचारु रूप से कर सकेंगी। जाहिर है, सरकार का उद्देश्य गांव और उसके निवासियों को उद्यमशील, समावेशी एवं आत्मनिर्भर बनाना है। यह भारत के पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

****

हिन्दुस्तान
1936

अमेरिकी दबाव

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का सबको इंतजार है, ताकि दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता आ जाए। एक ओर, बताया जा रहा है कि कृषि और डेयरी उत्पादों पर समझौता अटक रहा है, तो दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का संकेत दिया है। यह सही है कि भारत एक बड़ा बाजार है और अमेरिका यहां बड़े फायदे की तलाश में है। विशेष रूप से कृषि और डेयरी उद्योग के दरवाजे अगर अमेरिका के लिए ज्यादा खुले, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका रहेगी। ट्रंप कोशिश में हैं कि 1 अगस्त से पहले ही भारत के साथ समझौता हो जाए। अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि भारत और कुछ अन्य देशों के साथ अच्छा समझौता होने जा रहा है। ध्यान रहे, इंडोनेशिया ने एक तरह से अमेरिका के लिए अपने बाजार को खोल दिया है, क्या भारत भी ऐसा ही कर सकता है?

वास्तव में, भारत को फूंक-फूंककर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आज भी 40 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय सीधे कृषि पर निर्भर हैं, जबकि डेयरी क्षेत्र 1.4 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरता है और आठ करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। कृषि और डेयरी, दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनको लेकर भारत की सरकारें बहुत संवेदना के साथ कदम उठाती आई हैं। एक बड़ा विवाद मांसाहारी दूध को लेकर है। भारत आयातित दूध के लिए सख्त प्रामाणीकरण चाहता है, इसके तहत यह बताना अनिवार्य हो जाएगा कि भारत आए दूध को किन गायों से प्राप्त किया गया है? क्या उन गायों को एनिमल फूड खिलाया गया है? यह गौरतलब है कि अमेरिका में गायों को मिल्क मशीन माना जाता है। ऐसी गायों से ज्यादा से ज्यादा दूध लेने के लिए उन्हें पशु-जनित आहार खिलाया जाता है। इन गायों से जो दूध प्राप्त होता है, उसे शाकाहारी या वेज नहीं माना जा सकता। ऐसे दूध का भारत में प्रवेश रोकने की एक सांस्कृतिक-सामाजिक मजबूरी भी है, जिसका आदर अमेरिका को करना चाहिए। यह बात छिपी नहीं है कि भारत में धार्मिक पूजा-विधान में दूध का बहुत प्रयोग होता है, अतः भारत यदि अमेरिकी डेयरी उत्पादों का प्रामाणीकरण चाहता है, तो कतई गलत नहीं है। हालांकि, यहां सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिका प्रामाणीकरण के लिए तैयार हो जाए, तो क्या भारत में वेज और नॉनवेज दूध का वर्गीकरण हो जाएगा?

भारत को अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के सामने अनावश्यक दबाव में नहीं आना चाहिए। अपने व्यापक हित को देखते हुए ही अमेरिका से व्यापार समझौता करना चाहिए।

भारत के वार्ताकारों को सावधान रहना चाहिए। अगर भारतीय बाजार में सस्ते अमेरिकी दुग्ध उत्पादों का प्रवेश हुआ, तो यहां दूध की पवित्रता खत्म हो जाएगी? साथ ही, डेयरी क्षेत्र में भारत की ताकत भी कम हो जाएगी। अनुमान है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, पर स्थानीय खपत ज्यादा होने की वजह से यहां से ज्यादा निर्यात नहीं हो पाता। अमेरिकी डेयरी उत्पादों को अबाध मंजूरी देने का एक बड़ा खतरा यह भी है कि मुश्किलों से गुजर रहे भारतीय डेयरी उद्योगों पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। कारोबार और रोजगार, दोनों पर संकट बढ़ेगा। अमेरिका को मनाना भले टेढ़ी खीर हो, पर भारत को यहां अपनी दाल गलानी ही पड़ेगी। टेस्ला जैसी अमेरिकी कंपनी की महंगी कारों का भारत में प्रवेश सहजता से हो चुका है, पर ध्यान रहे, अमेरिका के कृषि और डेयरी उत्पादों का प्रवेश उतना सहज नहीं है। चिंता होती है कि अमेरिका डॉलर और रूस जैसे एकाधिक मोर्चों पर भारत पर अनावश्यक दबाव बढ़ा रहा है। भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन रखते हुए ऐसे दबावों से जल्द उबरने के उपाय करने पड़ेंगे।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

Hindustan

17 जुलाई, 1950

बेसुरा राग

मास्टर तारा सिंह वयोवृद्ध और मान्य नेता हैं। उनके प्रति आदर का भाव रखना सभी के लिए उचित है। परन्तु आदर का भाव रखना एक बात है और उनकी बात को स्वीकार करना बिल्कुल दूसरी। किसी बात को स्वीकार तभी करना चाहिए, जब वह बुद्धिगम्य और हितावह हो। विवेक मनुष्य को इसीलिए मिला है कि, उससे वह हरएक बात की परख करे और इष्ट को ग्रहण तथा अनिष्ट को अस्वीकार करे। मास्टर तारा सिंह या और कोई कितने ही मान्य क्यों न हों, उनकी बातों को इसी कसौटी पर कसना चाहिए और तभी स्वीकार या अस्वीकार करना उचित है।

इस दृष्टि से विचार करने पर, हमें खेद होता है कि मास्टर जो कुछ ऐसी बात कह रहे हैं, जिसे स्वीकार करने के बजाय बेसुरा राग कहना अनुपयुक्त न होगा। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि घटनाओं से भी उन्होंने सबक नहीं लिया और वही बातें कह रहे हैं, जैसी कायदे आजम जिन्ना और मुसलमानों के द्वारा प्रचारित हो कर भारत-विभाजन का कारण हुईं। देश का हित यदि उनके लिये सर्वोपरि है तो संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना का उन्हें त्याग करना चाहिए। बल्कि, हम तो कहेंगे, जिस सिख जाति के स्वार्थ की दृष्टि से वह प्रतिपादन करते हैं, उसका हित भी दूरदृष्टि से, व्यापक भावना में ही है। मास्टर जी की मांग के अनुसार यदि 'सिखिस्तान' कायम किया जाय तो, प्रश्न यह है, वहां के हिन्दुओं को सिखों की मर्जी पर क्यों छोड़ा जाय और केन्द्र साम्प्रदायिक सिख राज्य की रक्षा का भार क्यों ग्रहण करे? तर्क सम्मत बात यह भी होती है कि सिख राज्य के हिन्दू यदि वहां से हटते हैं तो देश के अन्य भागों में सिखों को नौकरी आदि की सुविधाएं क्यों रहें और वे भी अपने साम्प्रदायिक राज्य में ही क्यों न सीमित किये जायें? इसका अर्थ हुआ कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच सिखिस्तान का स्वतंत्र व्यक्तित्व अत्यन्त कमजोर होगा। उधर, सिखों को नौकरी आदि की जो सुविधाएं अखिल भारतीय नागरिक रहने में प्राप्त हैं, वे न रहेंगी। सेना में आज जो सिखों का योग है, वह भी तब नहीं रहेगा। और इस तरह सिखों को सब तरह हानि ही हानि होगी। सिख राज्य का भूत मास्टर जी के ऊपर इतना छाया हुआ है कि उसके मोह में उसकी अव्यवहारिकता और हानियों को वह समझ नहीं पाते मालूम पड़ते हैं।

भारत और चीन को एक-दूजे की जरूरत

शशांक | पूर्व विदेश सचिव

अमेरिका व नाटो देशों की बौखलाहट संकेत है कि विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में, हम नहीं चाहेंगे कि बीजिंग पूरी तरह से हमारे खिलाफ हो जाए।

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिंगापुर व चीन की यात्रा बदलती विश्व व्यवस्था के अनुकूल मानी जाएगी। सिंगापुर में बेशक 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया, मगर गलवान में पांच साल पहले हुई हिंसक झड़प के बाद पहली बार किसी भारतीय विदेश मंत्री के चीन जाने पर चर्चा स्वाभाविक ही है।

जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने तियानजिन पहुंचे थे। अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। वास्तव में, यह भारत-चीन संबंधों का भी 'प्लैटिनम जुबली' दौर है। दोनों देशों की 75 वर्षों की इस द्विपक्षीय कूटनीतिक यात्रा में कई पड़ाव आए हैं। लिहाजा, उचित ही दोनों नेताओं ने संबंधों की स्थिरता पर जोर दिया। कैलास मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने में चीन के सहयोग की सराहना भी की गई। यही नहीं, दोनों ने एक-दूसरे देश में लोगों की आवाजाही बढ़ाने और सीधी उड़ान सेवा की दिशा में अतिरिक्त कदम उठाने पर भी सहमति जताई।

पिछले साल अक्तूबर में ब्रिक्स सम्मेलन के इतर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही यह संकेत मिलने लगे थे कि भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर लौटने लगे हैं। चूंकि अगले महीने फिर से ये दोनों शासनाध्यक्ष एससीओ बैठक में मिलने वाले हैं, इसलिए भारतीय नेताओं की हाल-फिलहाल में चीन-यात्रा बड़ी है। उल्लेखनीय है, पिछले दिनों एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक भी हुई थी, जिसके घोषणापत्र में पहलगाम हमले का जिक्र न होने और बलूचिस्तान का वर्णन करके पाकिस्तानी हितों की वकालत करने के कारण भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में, यह जरूरी था कि भारत आतंकवाद के मसले पर मजबूती से अपनी बात रखे, जो एस जयशंकर ने बखूबी किया।

यह विडंबना है कि एससीओ जब बना था, तब आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करना इसके प्राथमिक उद्देश्यों में एक था, लेकिन अब इसी मसले पर इसके सदस्य देशों में मतभेद दिखने लगे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का खुलेआम पोषण करता है, जिसका परोक्ष रूप से चीन साथ दे रहा है। भारत इसी दुरभिसंधि के खिलाफ मुखर है। हालांकि, भारत-चीन रिश्तों में आती गरमाहट को नाटो के हालिया फैसले के बरअक्स भी देखना चाहिए।

दरअसल, नाटो के देशों ने अब निर्णय लिया है कि वे अपने हथियार यूक्रेन को देंगे और बाद में अमेरिका से खरीदकर भी उसे मुहैया कराएंगे। हालांकि, बाद में इस खबर पर स्पष्टीकरण भी जारी किया गया, लेकिन माना यही जा रहा है कि नाटो देश अब यूक्रेन का खुलकर साथ देंगे, वे रूस का मुकाबला करना चाहते हैं। इससे वैश्विक आपूर्ति-शृंखला पर खासा असर पड़ सकता है, जो भारत और चीन, दोनों को प्रभावित करेगा।

वैसे, एस जयशंकर की इस यात्रा से चीन के हित भी सधे। वास्तव में, पिछले कुछ दिनों से उसके नेता शी जिनपिंग सार्वजनिक तौर पर नहीं दिख रहे थे। इसके कारण पश्चिमी मीडिया चीन में संभावित सत्ता-परिवर्तन का दावा करने लगा था। मगर अब जिनपिंग और जयशंकर की मुलाकात की तस्वीरें सार्वजनिक होने के बाद कहा जा रहा है कि चीन ने भारत के माध्यम से विश्व को संदेश दे दिया है।

एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जब चीन आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान के साथ है, तो उसके साथ संबंध क्यों रखे जाएं? ऐसा कहने वाले लोग वास्तव में दोनों देशों के रिश्तों की जटिलताओं को नहीं समझते। चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो वह विश्व मंच पर बेपरदा भी हो गया। फिर, भारत ने पाकिस्तान, चीन और तुर्किये गठजोड़ से अकेले सफल मुकाबला करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। चूंकि विश्व व्यवस्था में कोई देश स्थायी दुश्मन नहीं होता, इसलिए अपने हितों के अनुकूल भारत ने चीन के साथ संबंध आगे बढ़ाए हैं। अमेरिका और नाटो देश की बौखलाहट संकेत है कि विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में, भारत को सोच-समझकर आगे बढ़ना ही होगा। हम नहीं चाहेंगे कि बीजिंग पूरी तरह से नई दिल्ली के खिलाफ हो जाए।

इतना ही नहीं, अमेरिका ने टैरिफ-जंग छेड़कर विश्व अर्थव्यवस्था में जो उथल-पुथल मचाई है, उससे भारत और चीन, दोनों को मुकाबला करना है। अमेरिका हमारा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, इसलिए हम अमेरिकी बाजार को भी नजरंदाज नहीं कर सकते। मगर उस पर पूरी तरह से निर्भरता हमारे लिए उचित नहीं, इसलिए चीन और रूस जैसे देशों के साथ आपसी संबंधों का भी हमें ख्याल रखना होगा। यदि अमेरिका अपने सीमा शुल्क बढ़ाता है, तो हमारे कारोबार पर इसका असर पड़ सकता है। लिहाजा, समय से पूर्व विकल्प की तलाश ही हमारी बुद्धिमानी मानी जाएगी और जहां-जहां हमारे हित जुड़े हुए हैं, हमें वहां-वहां मिलकर काम करना होगा।

हालांकि, नाटो महासचिव मार्क रूट ने यह चेतावनी दी है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देश रूस पर युद्ध रोकने का दबाव नहीं बनाएंगे, तो उन्हें 100 फीसदी सीमा शुल्क बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। यह कुछ और नहीं, पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की बौखलाहट है। उसे डर है कि वैश्विक व्यापार अथवा लेन-देन में अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करने की कवायद चल रही है। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं है। उसे अपनी इस घरेलू बहस से ऊपर उठना चाहिए। यह डॉलर, पाउंड और यूरो के बीच की जंग है। सन् 1971 से पहले तो डॉलर स्वर्ण मानक से जुड़ा हुआ था, मगर यही देखा गया कि यूरोप के देश इससे बचने लगे थे, जिसके बाद अमेरिका इस मानक से पीछे हटने को मजबूर हुआ था और 'पेट्रोडॉलर' की संकल्पना सामने आई थी, यानी तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार की मुद्रा डॉलर बना दी गई।

बेशक, ब्रिक्स में सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के शामिल होने से अमेरिका में डॉलर के विमुद्रीकरण को लेकर डर पसर रहा है, लेकिन भारत ने हाल-फिलहाल में इस मुद्रा से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। हम तो अब भी विदेशी व्यापार डॉलर में ही करने के हिमायती हैं। हां, कभी-कभी ब्रिक्स देशों की एक वैकल्पिक मुद्रा की बातें उठती जरूर हैं, लेकिन इसे हकीकत बनने में अभी खासा वक्त लगेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

धर्मस्थलों पर वीआईपी दर्शन कराने का नाजायज धंधा

रमेश ठाकुर | स्वतंत्र पत्रकार

भारत अनेक धर्मों, मतों और संप्रदायों-समुदायों का देश है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, जहां इतनी धार्मिक विविधता होगी और आस्था-विश्वास के इतने रूप होंगे! इस बात का अंदाजा सिर्फ इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि पूरे भारत में 5,400 ऐसे प्रमुख धर्मस्थल हैं, जहां रोजाना लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इनमें से काशी विश्वनाथ, अयोध्या के राम मंदिर, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी मंदिर, जगन्नाथ पुरी, शिरडी साईं मंदिर, ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह, खाटू श्याम, बांके बिहारी मंदिर, कृष्ण जन्मस्थली जैसे प्रमुख आस्था केंद्रों में तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर रोज रहती है।

मगर इनमें से कई धर्मस्थल पर जन-आस्था के दोहन का दुश्चक्र चल रहा है। चौंकाने वाला ताजा मामला काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा है, जहां पुलिस ने बीते 10 जून को मंदिर परिसर में 21 फर्जी पुजारियों और पंडों को पकड़ा। ये श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर पांच सौ से लेकर हजार रुपये तक की अवैध वसूली कर रहे थे। पिछले सप्ताह राजस्थान में मेंहदीपुर बालाजी मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं और व्यवस्थापकों के बीच खूब मारपीट हुई, मामला थाने तक पहुंच गया। पिछले सप्ताह मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन का झांसा देकर भक्तों से अवैध वसूली करने वाले फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अजमेर से इसी जनवरी में पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा था। धरपकड़ के बावजूद यह धंधा मंदा नहीं पड़ता। ये तत्व कुछ दिन शांत रहते हैं, फिर से सक्रिय हो जाते हैं।

पुलिस ने हाल में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 21 फर्जी पुजारियों को पकड़ा। वीआईपी दर्शन के नाम पर ये श्रद्धालुओं से वसूली कर रहे थे।

दरअसल, धर्मस्थलों पर वीआईपी संस्कृति एक विचलन है। काशी विश्वनाथ में पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को जो कुछ बताया, उसे सुनकर आला अधिकारी भौचक्क रह गए। इन आरोपियों ने बताया कि वे काफी लंबे वक्त से यह कार्य करते आ रहे हैं। वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से उगाही का बाकायदा एक संगठित गिरोह सक्रिय है। इसमें सैकड़ों सदस्य शामिल हैं, जो प्रमुख धर्मस्थलों में दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठते हैं। इन लोगों की स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अफसरों व सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों से सांठगांठ होती है। फिलहाल ऐसे गिरोहों के खिलाफ यहां अभियान चल रहा है।

देश भर के मंदिरों, दरगाहों में अवैध तरीके से दर्शन कराने और प्रसाद-लॉकर के नाम पर मनमाने रुपये ऐंठने वालों की भरमार है। फर्जी पुजारियों, बाबाओं, पंडों और खादिमों की संख्या भी बढ़ी है। दरअसल, वसूली गैंग के सदस्य श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का लालच देते हैं। मंदिरों में उमड़ती भारी भीड़ को देखकर श्रद्धालु आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं। धर्मस्थलों पर बढ़ती 'वीआईपी संस्कृति' के कारण अब कई निजी कंपनियां भी इस धंधे में कूद पड़ी हैं। वे बाउंसर उपलब्ध करा रही हैं। कुछ ऐसी कंपनियों को पुलिस ने पिछले दिनों पकड़ा है। मथुरा में एक फर्जी बाउंसर ग्रुप की ऐसी हरकत की जानकारी जब मंदिर प्रबंधन को लगी, तो उसने दो बाउंसरों को गिरफ्तार करवाया।

हमारे धर्मस्थल कभी समतावाद के उदाहरण हुआ करते थे। वहां कोई सेठ नहीं, कोई विशिष्ट नहीं, सब के सब बस भक्त। पवित्र स्थलों में समता के इस विचार को फिर से स्थापित करने की जरूरत महसूस होने लगी है। इस वीआईपी संस्कृति पर बीते दिनों उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी घोर चिंता जताई थी। वह बेंगलुरु स्थित एक धर्मस्थल में नए क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर 'वीआईपी दर्शन' की संस्कृति बिना देर किए खत्म होनी चाहिए। सच यह है कि इस संस्कृति को हम-आप जैसे लोग ही फलने-फूलने देते हैं। खास दिखने और भीड़ से बचने की प्रवृत्ति के कारण ही हम वसूली गैंग के हाथों लुटते हैं।

काशी विश्वनाथ जैसा अभियान देश के सभी तीर्थस्थलों, मंदिरों और दरगाहों में चलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि आस्था के केंद्रों पर चल रही ऐसी अवैध गतिविधियां तत्काल रोकी जा सकें, क्योंकि इससे न सिर्फ धर्मस्थलों की गरिमा घटती है, बल्कि आम श्रद्धालुओं की आस्था को भी गहरी ठेस पहुंचती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ईर्ष्या को ऊर्जा बनाएं

एक तारा अपने आस-पास चमक रहे दूसरे तारे से ईर्ष्या नहीं करता। बारिश की कोई बूंद अपने साथ की बूंद से ईर्ष्या नहीं करती। धरती पर गिरा पत्ता भी तने से लटके हुए पत्तों के लिए शुभकामनाएं देना बंद नहीं करता। कोई कांटा गुलाब की चुगली नहीं करता। मगर जब लोग किसी और को अपनी मनचाही जिंदगी जीते या अपनी मनचाही चीजें हासिल करते देखते हैं, तो उन्हें जलन होती है।

ईर्ष्या होना स्वाभाविक है और इसमें कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह व्यक्ति को 'रेसिंग ट्रैक' पर ले जाए। फिर वह व्यक्ति जीवन में अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है। इस तरह की ईर्ष्या का अनुभव हरेक विजेता ने अपने जीवन में एक या एक से ज्यादा बार जरूर किया होगा। लेकिन अगर ईर्ष्या की भावना आपके अंदर क्रोध, जलन और चिंता पैदा कर रही है, तो आप सिर्फ ईर्ष्यालु नहीं हैं, आप असहाय महसूस कर रहे हैं और किसी दूसरे के पास जो है, उसे पाने की अपनी क्षमता को कम आंक रहे हैं। अगर आप ईर्ष्या के पौधे को मेहनत की बजाय क्रोध से सींचेंगे, तो वह आपको अंदर से मार डालेगी। ईर्ष्या से आप अपने अंदर या तो कैक्टस उगा सकते हैं या काजू।

ईर्ष्या एक प्रकार की ऊर्जा है, जो आपकी भावनाओं के अनुसार बढ़ती या घटती है। अगर आप ईर्ष्या करते रहेंगे, तो यह बढ़ती ही रहेगी। बल्कि जब आपको हद से ज्यादा ईर्ष्या हो, तो एक पल रुकें और अपनी ईर्ष्या से बात करें- 'यह भावना गलत है। मुझे किसी से इतनी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम सभी के पास समान शक्तियां हैं और मैं उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकता हूं, जितना अभी देख रहा हूं और जिसके लिए ईर्ष्या महसूस कर रहा हूं। हे सर्वशक्तिमान, मुझे ऐसा महसूस न करने में मेरी मदद करें।'

समस्या यह है कि लोग उन लोगों से भी जलन महसूस करते हैं, जो उनके प्रतिस्पर्द्धी नहीं हैं। मेरा एक दोस्त कॉल सेंटर में काम करता है, मगर अपनी कमाई की वजह से अपने फैमिली डॉक्टर से जलन महसूस करता है। यह अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करने जैसा है। हम सब पानी के नीचे पत्थर की तरह हैं; अनोखे और खूबसूरत। बस दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो और जो हो, जो तुम्हारे पास है, उसमें खुश रहो।

ऐसे अनगिनत लोग हैं, जो आपके जैसा जीवन, आपकी तरह नौकरी, आप सा परिवार या आपके जैसे बच्चे पाना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ आपके पास है, उसके लिए आभारी होना सीखें।

आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, उसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और जो आपके पास है, उसी से खुशी को सींचें। ऐसे अनगिनत लोग हैं, जो आपके जैसा जीवन, आपकी तरह नौकरी, आप सा परिवार या आपके जैसे बच्चे पाना चाहते हैं। खुद को भाग्यशाली मानें। बस जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आभारी होना सीखें, और भी बहुत कुछ आपके पास आएगा।

चेतन दलवी

नरेंद्र मोदी | प्रधानमंत्री, भारत

स्किल इंडिया से अनगिनत लोगों को नए अवसर मिले हैं। आगे भी हम अपनी युवा शक्ति को वैश्विक श्रेष्ठ व्यवसायों के अनुरूप नए कौशल से सुसज्जित करते रहेंगे, ताकि हम विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकें।

अनुलोम-विलोम

टेस्ला

टेस्ला का आना भारत के लिए लाभकारी

आखिरकार टेस्ला के कदम भारत में पड़ ही गए। आलोचकों की नजर में यह मध्यवर्गीय परिवारों का उपहास है, क्योंकि इस वर्ग की आर्थिक हैसियत इतनी नहीं है कि वह टेस्ला की महंगी गाड़ियों के बारे में सोच भी सके, जबकि भारतीय बाजार इन्हीं लोगों के भरोसे आगे बढ़ रहा है। मगर ऐसे आलोचक शायद भूल जाते हैं कि किसी विदेशी कंपनी के आने से किस-किस तरह के लाभ मिलते हैं। निस्संदेह, एलन मस्क ने महंगी गाड़ी उतारी है, लेकिन इससे भारत को कई तरह से परोक्ष फायदा हो सकता है, खासतौर से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को इससे खूब फायदा मिल सकता है।

मिसाल के तौर पर, टेस्ला के रियर व्यू मिरर, गियर्स, चार्जर, ब्रेक के पार्ट, सेंसर्स आदि तमाम उपकरण दूसरी कंपनियां बनाती हैं। ऐसे में, टेस्ला के आने से इन कंपनियों को फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक फायदा यह भी है कि वे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देती हैं। टेस्ला की बैटरी चार्जिंग पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ती पड़ेगी, जिसके कारण ईंधन की मांग प्रभावित हो सकती हैं। वैसे भी, टेस्ला सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती है, वह सौर ऊर्जा व बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर भी काम करती है। इससे गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप, बैटरी से चलने वाले कृषि यंत्र, घरों की बिजली जैसी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। चूंकि जलवायु परिवर्तन की सर्वाधिक मार किसानों पर पड़ती है, इसलिए ऐसी गाड़ियां आम लोगों के हित में मानी जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ऐसी गाड़ियां फायदेमंद होती हैं। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के विस्तार से चार्जिंग स्टेशन, बैटरी रिपेयरिंग, मेंटनेंस जैसे कामों में ग्रामीण नौजवानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। कुल मिलाकर, टेस्ला जैसी गाड़ियां भारत को कई मायने में लाभ पहुंचा सकती हैं, इसलिए सिर्फ इनकी कीमतों को देखना, इसका एकांगी मूल्यांकन करना होगा।

सच यह भी है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। यहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में, यदि टेस्ला जैसी कंपनियां यहां आती हैं, तो विश्व मंच पर भारत को फायदा मिलेगा। इसके बाद अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारतीय बाजार में उतर सकती हैं, जिससे यहां प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा मुकाबला किस तरह से उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचा सकता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। चूंकि भारत का ईवी बाजार 2030 तक सालाना 25 फीसदी की दर से बढ़ सकता है, इसलिए उम्मीद है, नई गाड़ियों की आवक भारतीय बाजार को आगे बढ़ाएगी।

स्वीकृति कुमारी, टिप्पणीकार

अभी इसे कई चुनौतियों से जूझना होगा

आंकड़े बताते हैं कि भारत में अमीरों की संख्या बढ़ना भले ही बाजारवाद की दृष्टि से गर्व करने वाली बात हो, पर हकीकत यही है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी आज भी सरकार पर निर्भर है। ऐसे में, स्वाभाविक ही टेस्ला को कई चुनौतियों से जूझना होगा। एलन मस्क निस्संदेह दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार हैं और विश्व भर में उनकी कंपनियों के उत्पाद बिकते हैं। मगर भारत के ऑटो बाजार में उनका उतरना शायद ही फायदेमंद हो सकेगा।

असल में, भारतीय बाजार की रीढ़ मध्यमवर्गीय लोग हैं। ये वे लोग हैं, जिनकी सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक है। अधिक कमाने वाले लोग बेशक महंगी गाड़ियों का शौक रखते होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों की पसंद सस्ती और टिकाऊ गाड़ियां होती हैं। इसके विपरीत, एलन मस्क की टेस्ला कार अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है, जिसके कारण इसकी शुरुआती कीमत 60 लाख रुपये रखी गई है। भारतीय सड़कों पर इतनी महंगी गाड़ियां गिनी-चुनी ही दिखती हैं। फिर, यहां तकनीक को कितने लोग आत्मसात कर पाए हैं? कई तो सिर्फ इसलिए किसी नई तकनीक से तौबा कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें उनकी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी। इसी कारण भारत में सस्ती गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं। टाटा ने लखटकिया कार की संकल्पना भी इसी कारण से की थी। बाजार में आमतौर पर पांच से दस लाख तक की गाड़ियां ही ज्यादा दिखती हैं। ऐसे में भला 60-70 लाख रुपये की कितनी गाड़ियां टेस्ला कंपनी बेच सकेगी?

एलन मस्क का भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित टेस्ला कार बेचने का सपना देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पूरा हुआ है। वह लंबे समय से अपनी इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में उतारना चाहते थे, लेकिन ऊंचे सीमा शुल्क के कारण उनकी कार की कीमतें भारत के लिहाज से काफी ज्यादा हो रही थीं, जिसके कारण उनका विचार लगातार टलता गया। चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वह अमेरिकी प्रशासन का हिस्सा थे, इसलिए उनके लिए राहें शायद आसान हो गईं। फिर भी, यदि उनको भारतीय ऑटो क्षेत्र में नेतृत्व करना है, तो मध्यवर्गीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कारें बनानी होंगी। हां, जब यहां प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी या लोग इस लायक बन जाएंगे कि महंगी गाड़ियां आसानी से खरीद सकें, तब शायद टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ जाए। तब तक तो एलन मस्क को भारतीय उपभोक्ताओं की मानसिकता को समझकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

अरविंद रावल, टिप्पणीकार

17 hindi page6-lc_page 02.qxd 16-07-2025 23:21 Page 1

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 17 जुलाई 2025

ममदानी का उदय

ट्रंप को चुनौती

राजनीतिक शतरंज एक अजीब खेल है। कभी-कभी, एक सर्वशक्तिमान राजा को एक अनजान मोहरे द्वारा मात दी जा सकती है, जो कहीं से भी आकर उस शक्तिशाली राजा के प्रभुत्व को चुनौती देता है। यह तुलना शायद डोनाल्ड ट्रंप बनाम मुजम्मिल ममदानी के लिए सबसे उपयुक्त है। हालांकि, अमेरिकी राजनीति में उनका उदय न केवल अप्रत्याशित है, बल्कि यह समय का संकेत है। वह हर उस चीज के पक्ष में खड़े हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी व्यवस्था से उखाड़ फेंकने और दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे युग में जब राजनीतिक निराशा चरम पर है और मतदाताओं का थकना अपरिहार्य लगता है, ममदानी एक उत्साहजनक प्रति-विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आदर्शवाद, कार्रवाई और प्रामाणिकता पर आधारित है। सक्रियतावाद और प्रणालीगत असमानता की गहरी समझ के साथ, उनका संदेश - स्पष्ट, आंकड़ों पर आधारित और भावनात्मक रूप से गूंजने वाला - एक विविध, मोहभंग मतदाता के साथ जुड़ रहा है।

युगांडा में भारतीय माता-पिता के यहां जन्मे और एक राजनीतिक रूप से जागरूक परिवार में पले-बढ़े, ममदानी अमेरिकी राजनीति में एक वैश्विक संवेदनशीलता लेकर आए हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका (डीएसए) के सदस्य, उनके अभियान आवास न्याय, सार्वजनिक परिवहन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और प्रवासी-समर्थक नीतियों पर केंद्रित रहे हैं। लेकिन हाल ही में उनकी राष्ट्रीय स्तर पर हुई लोकप्रियता–खासकर अमेरिकी विदेश नीति की उनकी आलोचना और तानाशाही के प्रति उनके अडिग रुख ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के एक गंभीर वैचारिक प्रतिद्वंदी के रूप में सुर्खियों में ला दिया है।

पारंपरिक डेमोक्रेटिक प्रतिष्ठान, जो अक्सर सतर्क राजनीति करता है, के विपरीत, ममदानी ऐसे व्यक्ति की निर्भीकता से बोलते हैं जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, और अपने समुदाय के लिए पाने को सब कुछ है। उनकी वाणी सिद्धांत-आधारित है, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं। उनकी बहसें नैतिक स्पष्टता से ओतप्रोत हैं, लेकिन आत्म-धार्मिकता से नहीं। और उनके प्रस्ताव–चाहे वह सार्वजनिक आवास के लिए ग्रीन न्यू डील हो या विदेश नीति के फैसलों का लोकतंत्रीकरण–एक युवा, बहुजातीय, मजदूर वर्ग के गठबंधन की ओर इशारा करते हैं जो यथास्थितिवाद से थक चुका है और बदलाव के लिए तरस रहा है। ममदानी को ट्रंप का सच्चा विरोधी सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं–बल्कि दार्शनिक उलटबाँसी है। ट्रंप जहाँ राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, वहीं ममदानी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के हिमायती हैं। जहाँ ट्रंप डर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहीं ममदानी आशा से जुटते हैं।

ट्रंप अमेरिका को उसके मिथकीय अतीत में वापस ले जाने का वादा करते हैं, ममदानी उसके भविष्य की पुनर्कल्पना पर जोर देते हैं। और जैसे-जैसे अमेरिका एक और ध्रुवीकृत चुनावी परिदृश्य की ओर बढ़ रहा है, यह विरोधाभास और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि ममदानी आगे चल रहे हैं, वह अभी भी राष्ट्रीय शक्ति के हाशिये पर खड़े हैं। लेकिन अब वे राष्ट्रीय प्रासंगिकता के हाशिये पर नहीं हैं।

वायरल भाषणों से लेकर बढ़ते सोशल मीडिया समर्थन तक, ममदानी उन अमेरिकियों के बढ़ते समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न केवल ट्रंप विरोधी हैं - बल्कि ट्रंप के बाद के हैं। वे एक ऐसे भविष्य की तलाश में हैं जहाँ न्याय की माँग पर्दे के पीछे बैठकर न की जाए, बल्कि सड़कों पर की जाए। और उनके लिए, ममदानी सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं हैं। जैसे-जैसे राजनीतिक रणभूमि बदल रही है और डेमोक्रेटिक पार्टी पर अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करने का दबाव बढ़ रहा है, ममदानी का उदय एक स्पष्ट संकेत देता है: सुरक्षित मध्यमार्गीवाद का युग शायद समाप्त हो गया है। और यदि सत्ता प्रतिष्ठान उनकी उपेक्षा करता है, तो वे ऐसा अपने लिए जोखिम उठाकर कर रहे हैं - क्योंकि ऐसा लगता है कि ममदानी ने अभी तो शुरुआत ही की है।

नीति आयोग की मानव पूंजी क्रांति

भारत के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में, नीति आयोग ने एक दशक से चल रहे परिवर्तन को गति प्रदान की है और मानव पूंजी को राष्ट्रीय विकास और नीतिगत सुधारों के केंद्र में रखा है। नीति आयोग एक दूरदर्शी उत्प्रेरक के रूप में उभरा है

राव इंदरजीत सिंह
लेखक, केंद्रीय मंत्री हैं।

भारत जैसे विशाल और विविध देश में, प्रगति का असली पैमाना केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों या बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि कोई राष्ट्र अपने लोगों का कितना बेहतर पोषण करता है। मानव पूंजी, हमारी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और उत्पादकता, केवल एक आर्थिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता भी है। पिछले दस वर्षों में, भारत के प्रमुख नीति थिंक टैंक, नीति आयोग के नेतृत्व में एक शांत लेकिन प्रभावशाली क्रांति ने आकार लिया है, जिसने देश के अपने सबसे मूल्यवान संसाधनः अपने नागरिकों में निवेश करने के तरीके को नया रूप दिया है। ऐसे देश में जहां 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जनसांख्यिकीय लाभांश एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर प्रस्तुत करता है। लेकिन इस युवा आबादी का विशाल आकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। चुनौती युवा ऊर्जा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास की शक्ति में बदलने की है।

यहीं पर नीति आयोग एक दूरदर्शी उत्प्रेरक के रूप में उभरा है, न केवल आज की प्रगति के लिए, बल्कि कल की समृद्धि के लिए भी एक रोडमैप तैयार कर रहा है। पिछले एक दशक में, नीति आयोग एक थिंक टैंक से एक सुधारवादी इंजन और क्रियान्वयन भागीदार के रूप में विकसित हुआ है, जो आंकड़ों, सहयोग और मानव-केंद्रित डिजाइन द्वारा समर्थित साहसिक विचारों के लिए जाना जाता है। इसने नीति-निर्माण को एक शीर्ष-स्तरीय प्रक्रिया से राज्यों, निजी खिलाड़ियों, वैश्विक संस्थानों और नागरिक समाज के साथ सह-निर्माण की एक गतिशील प्रक्रिया में बदल दिया है। इसकी शक्ति केवल योजना बनाने में ही नहीं, बल्कि सुनने और उन अंतर्दृष्टियों को कार्य में बदलने में निहित है।

शिक्षा, जो मानव पूंजी का आधार है, इसके मार्गदर्शन में पूरी तरह से पुनर्कल्पित हुई है। यह स्वीकार करते हुए कि केवल पहुंच ही पर्याप्त नहीं है, नीति आयोग ने गुणवत्ता और समानता पर जोर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जहां इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और एक नए युग की शुरुआत की, रटने की शिक्षा से आलोचनात्मक सोच, लचीलेपन और व्यावसायिक एकीकरण की ओर बदलाव को दर्शाया। इसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, मातृभाषा शिक्षण और विषयों के बीच निर्बाध संक्रमण पर जोर दिया।

अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलकदमियों के माध्यम से, इसने जवाबदेही और कल्पनाशीलता दोनों को सुनिश्चित किया है, देश भर में फैली 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स में नवाचार को समाहित किया है। 21वीं सदी के लिए भारत के युवाओं को कुशल बनाना इसके मिशन का एक और आधार रहा है।

स्किल इंडिया मिशन को समर्थन देने से लेकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से वंचित जिलों के केंद्र तक व्यावसायिक कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करने तक, नीति आयोग ने कक्षा और करियर के बीच की खाई को पाटने में मदद की है। स्किल इंडिया मिशन के तहत, 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ऐसी पहलों के जरिए प्रशिक्षित किया गया है जो तकनीक, उद्योग संबंधों और मांग-आधारित पाठ्यक्रमों का मिश्रण हैं। इसने सिर्फ प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया बल्कि इसने क्षेत्रीय जरूरतों का खाका खींचा और ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जिन्होंने भारत के ग्रामीण और शहरी युवाओं, दोनों के लिए वास्तविक आर्थिक द्वार खोले। इसके साथ ही, इसने एक गतिशील, समावेशी श्रम बाजार का भी समर्थन किया। इसने 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार सरल संहिताओं यथा वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा में तर्कसंगत बनाने का समर्थन किया। इन सुधारों ने नियोक्ता के लचीलेपन को श्रमिक सुरक्षा के साथ संतुलित किया, जिससे विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ, जो भारत के कार्यबल का बहुमत बनाते हैं। अनुपालन को सरल बनाकर और औपचारिकता को प्रोत्साहित करके, कार्यस्थल न केवल अधिक उत्पादक बना, बल्कि अधिक मानवीय भी बना। स्वास्थ्य सेवा, जिसे अक्सर एक लागत के रूप में देखा जाता था, को एक निवेश के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया।

नीति आयोग ने प्रतिक्रियात्मक उपचार से सक्रिय कल्याण की ओर बदलाव को मूर्त रूप देने में मदद की। नीति आयोग द्वारा समर्थित और निगरानी वाली प्रमुख आयुष्मान भारत योजना ने 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, जबकि 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने प्राथमिक देखभाल को जमीनी स्तर तक पहुँचाया। कार्यक्रमों ने पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोगों को लक्षित किया ,जिसका उद्देश्य न केवल बीमारों को ठीक करना था, बल्कि लोगों को स्वस्थ रखना भी था। कोविड-19 महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की लचीलेपन की अभूतपूर्व परीक्षा ली। इस संकट में, नीति आयोग ने मजबूती से कदम रखा है – स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के साथ मिलकर संक्रमण के पैटर्न का मॉडल तैयार किया, चिकित्सा संसाधनों का समान आवंटन सुनिश्चित किया और टेलीमेडिसिन के लिए ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म शुरू किए। महामारी के बाद के इसके दृष्टिकोण ने न केवल रिकवरी पर, बल्कि तैयारी पर भी जोर दिया – सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्गों और आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया। इन क्षेत्रों से परे, नीति आयोग उद्यमिता और नवाचार के लिए एक प्रकाश स्तंभ रहा है। स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रमों ने विचारों के फलने-फूलने के लिए एक उपजाऊ पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है।

फिनटेक, एडटेक, एग्रीटेक, हेल्थटेक और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हजारों स्टार्ट-अप आज फल-फूल रहे हैं क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण चरणों में नीतिगत समर्थन, इनक्यूबेशन और मार्गदर्शन मिला। ये केवल व्यवसाय नहीं हैं; ये रोजगार सृजनकर्ता और समस्या समाधानकर्ता हैं, जो एक लचीले और आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे रहे हैं। लेकिन शायद इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की संस्कृति को कैसे संस्थागत रूप दिया है। बड़े डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रीयल-टाइम डैशबोर्ड और कठोर निगरानी ढाँचों का लाभ उठाकर, इसने सुनिश्चित किया कि नीतियाँ अनुकूलनीय, जवाबदेह और जमीनी हकीकत के अनुरूप बनी रहें। चाहे वह भारत का पहला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक शुरू करना हो, राज्यों को प्रदर्शन मानकों पर मार्गदर्शन देना हो, या नीति निर्माण के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करना हो, नीति आयोग ने वैज्ञानिक सोच को शासन के केंद्र में लाया। मंत्रालयों और क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करने की इसकी क्षमता ने इसे एक सलाहकार निकाय से कहीं अधिक बना दिया - यह विकास का विवेकशील रक्षक बन गया। इसने प्रदर्शन-आधारित रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया, हाशिये पर मौजूद आवाजों को बुलंद करने के लिए नागरिक समाज के साथ काम किया और सर्वोत्तम प्रथाओं को घर तक पहुँचाने के लिए वैश्विक साझेदारों को शामिल किया।

वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का बढ़ता हुआ स्थान और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूनेस्को जैसी संस्थाओं से मिली प्रशंसा इस प्रयास की विश्वव्यापी मान्यता को दर्शाती है। केवल लक्ष्य प्राप्त करने से कहीं अधिक, नीति आयोग ने ऐसी प्रणालियाँ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है जो टिकाऊ, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हों।

सतत विकास लक्ष्यों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता हर पहल में स्पष्ट दिखाई देती है - स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से लेकर हरित गतिशीलता तक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से लेकर कार्यस्थलों में लैंगिक समानता तक। एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उदय अब कोई दूर का सपना नहीं है - यह एक प्रगतिशील कार्य है, जो उन नीतियों द्वारा संचालित है जो लोगों को राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति मानती हैं।

नीति आयोग ने विकास के इर्द-गिर्द चर्चा को ऊँचा उठाया है, हमें याद दिलाया है कि सच्ची प्रगति सबसे ऊँची इमारतों या सबसे बड़े कारखानों से नहीं, बल्कि अपने लोगों की ताकत, स्वास्थ्य और गरिमा से मापी जाती है। ऐसा करके, यह एक थिंक टैंक से कहीं बढ़कर बन गया है।

यह एक युवा, महत्वाकांक्षी भारत की धड़कन बन गया है–एक ऐसा भारत जो सपने देखता है, हिम्मत करता है और करता है। और इस कहानी के मूल में यह शांत विश्वास है कि जब आप लोगों में निवेश करते हैं, तो आप न केवल एक बेहतर अर्थव्यवस्था, बल्कि एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करते हैं।

भारत में तंबाकू विरोधी अभियान

हालांकि तंबाकू से संबंधित बीमारियां सभी आय वर्गों को प्रभावित करती हैं, लेकिन भारत के ग्रामीण गरीब लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उन्हें ज्यादा जोखिम, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पहुंच और धूम्रपान छोड़ने के लिए अपर्याप्त सहायता का सामना करना पड़ता है।

विनायक सोनावने
लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

ग्रामीण भारत में तंबाकू का सेवन केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है - यह रोजमर्रा की जिंदगी में रचा-बसा एक सामाजिक मानदंड है। गुटखा और खैनी चबाने से लेकर बीड़ी पीने और आधुनिक निकोटीन उत्पादों को अपनाने तक, यह आदत बचपन में ही शुरू हो जाती है और अक्सर बिना किसी चुनौती के जारी रहती है। सांस्कृतिक स्वीकृति, जागरूकता की कमी और गहरी जड़ें जमाए परंपराओं ने देश भर के गांवों में तंबाकू के सेवन को एक सामान्य व्यवहार बना दिया है।

हालांकि तंबाकू से संबंधित बीमारियां सभी आय वर्गों को प्रभावित करती हैं, लेकिन भारत के ग्रामीण गरीब लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उन्हें ज्यादा जोखिम, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पहुंच और धूम्रपान छोड़ने के लिए अपर्याप्त सहायता का सामना करना पड़ता है। शहरों पर केंद्रित जागरूकता अभियान अक्सर उस जगह को नजरअंदाज कर देते हैं जहाँ यह संकट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है: ग्रामीण भारत, जहाँ 65 प्रतिशत से ज्यादा आबादी रहती है। कई परिवारों के लिए, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए खतरा से कहीं ज्यादा है - यह एक आर्थिक बोझ है।

जब परिवार का कोई सदस्य तंबाकू के सेवन के कारण बीमार पड़ता है, तो इलाज का खर्च, वेतन का नुकसान और अकाल मृत्यु परिवारों को गरीबी के चक्र में धकेल सकती है। फिर भी, कई लोग असली खतरों से अनजान हैं, क्योंकि तंबाकू उद्योग ग्रामीण समुदायों में बेरोकटोक फैलती गलत सूचनाओं पर फलता-फूलता है। फिर भी, ग्रामीण भारत शक्तिहीन नहीं है - यह लचीला है। सशक्त होने पर, यह बदलाव की प्रेरक शक्ति बन जाता है। इसका समाधान ऊपर से नीचे तक लागू करने में नहीं, बल्कि स्थानीय नेतृत्व, शिक्षा और सामुदायिक सहयोग में निहित है।

बदलाव के सबसे शक्तिशाली शुरूआती बिंदुओं में से एक स्कूल प्रणाली के भीतर है। एक सच्चा तंबाकू-मुक्त स्कूल केवल साइनेज तक सीमित नहीं है - यह एक संस्कृति का विकास करता है। जब स्कूल प्रबंधन समितियाँ (एसएमसी), शिक्षक,

छात्र और अभिभावक मिलकर काम करते हैं, तो वे तंबाकू के उपयोग के खिलाफ एकजुट आवाज उठाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एसएमसी का अक्सर महत्वपूर्ण अधिकार और विश्वास होता है। जब वे शिक्षकों के साथ मिलकर कक्षा में चर्चाओं का नेतृत्व करते हैं, जागरूकता रैलियाँ आयोजित करते हैं, और अभिभावकों को आउटरीच में शामिल करते हैं, तो वे बच्चों में दीर्घकालिक व्यवहारिक बदलाव लाते हैं।

संदेश स्पष्ट है: तंबाकू कोई संस्कार नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और अवसर के लिए एक बाधा है। ये समितियाँ स्कूल के गेट के बाहर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि विक्रेता शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू न बेचें। उनकी सतर्कता नीति को व्यवहार में लाती है और भावी पीढ़ियों की रक्षा करने वाले सामुदायिक मानक निर्धारित करती है। आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सखियाँ ग्रामीण भारत में विश्वसनीय स्वास्थ्य दूतों का एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं।

बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होने के नाते, उनका प्रभाव गहरा है। ये महिलाएं स्थानीय भाषा बोलती हैं - शाब्दिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से - और अपनी निकटता का उपयोग परिवारों, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को तंबाकू के संपर्क के खतरों के बारे में सलाह देने के लिए करती हैं। गर्भावस्था के दौरान तंबाकू के सेवन से गर्भपात, जन्म के समय कम वजन और दीर्घकालिक विकास संबंधी चुनौतियों का खतरा बढ़ जाता है। नियमित घरेलू दौरों और धैर्यपूर्वक, सहानुभूतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से, ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिथकों का मुकाबला करते हैं, व्यवहार बदलते हैं और नशे के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले चक्र को तोड़ते हैं। वे गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भारत में 63 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार हैं।

तंबाकू इन बीमारियों का एक प्रमुख कारण है, फिर भी ग्रामीण जागरूकता कम है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता बदलाव की अग्रिम पंक्ति में हैं - जाँच करते हैं, रेफरल करते हैं, और भाग्यवादी दृष्टिकोण को आशावादी, निवारक मानसिकता में बदलते हैं। ग्रामीण भारत का सामाजिक ताना-बाना बहुत मजबूती से बुना गया है – और इसी में इसकी ताकत निहित है। स्वयं सहायता समूह, पंचायतें, महिला संघ, शिक्षक और युवा नेता सामूहिक रूप से लोगों के नजरिए में बदलाव ला सकते हैं। नुक्कड़ नाटक, घर-घर जाकर बैठकें और गाँव-व्यापी जागरूकता अभियान तंबाकू के नुकसानों को उजागर करने और उसके सांस्कृतिक गढ़ को ध्वस्त करने में मदद करते हैं।

जब गाँव खुद को सीओटीपीए के तहत "तंबाकू मुक्त" घोषित करते हैं, तो यह एक शक्तिशाली संदेश देता है: बदलाव सिर्फ सरकारी अमल से नहीं, बल्कि सामुदायिक विश्वास से संभव है। ग्रामीण भारत में तंबाकू को हराना स्वास्थ्य, सम्मान और अवसर बहाल करना है। आगे का रास्ता स्कूलों को समर्थन देने, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने और समुदायों को गहराई से जड़ जमाए मानदंडों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करने में निहित है।

गैर-सरकारी संगठन, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल और स्थानीय सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन असली ताकत तो जनता के पास है। क्योंकि तंबाकू मुक्त भारत का भविष्य नीतिगत दस्तावेजों या शहरी बोर्डरूम में नहीं बनेगा। यह ग्रामीण भारत की कक्षाओं, क्लीनिकों और आंगन से उभरेगा, एक बातचीत, एक समुदाय, एक-एक साहसी कदम के रूप में।

आप की बात

भाषा पर राजनीति न हो

उत्तर-पश्चिम में हिंदी अधिकांशतः बोली जाती है, जबकि दक्षिण-पूर्व में क्षेत्रीय भाषाएँ, कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ही हिंदी भाषा का भी काफी उपयोग भी होता है। यूं तो हमारा देश धर्म,जाति,सम्प्रदाय, पंथ, रीति-रिवाज, खान-पान वेश-भूषा आदि अनेक संस्कार-संस्कृति से सुसज्जित है। इसलिए केंद्र/राज्य सरकारें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बजाय राजनीति करने के बहुत ही सोच-समझकर निर्णय लें ताकि किसी भी तरह का इन विषयों पर विवाद उत्पन्न न होने पाए। कोई भी राज्य सरकार या उसके मुखिया/राजनेता किसी भाषा के बोलने या अध्ययन करने पर दबाव न बनाये और न ही बेवजह के अपनी स्वार्थपूर्ण राजनीति के लिए विवादित बयान दे, जिससे व्यर्थ के विवाद पैदा हों और आपस में वैमनस्यता उत्पन्न हो. हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र के त्रिभाषी फार्मूले पर दक्षिण में विरोध हुआ और महाराष्ट्र में भी सवाल उठे। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि वह बंगाली बोलने पर बेवजह एक विपक्षी राजनीतिक पार्टी विवाद पैदा कर रही है। ममता जी को तुच्छ व बिना सिर-पैर की बातों व बयानों से दूर रहना चाहिए। उन्हें भाषा को लेकर स्वार्थ की राजनीति नहीं करनी चाहिए, कहीं भी भाषा/सम्प्रदाय में कोई विवादित बात होती है तो उसे अपनी बातचीत/सशक्त कानून-व्यवस्था से सुलझाएं।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

सटीक समीक्षा

हर्षवर्धन व शिवम शेखावत ने भारत की विदेश नीति पर युवाओं में किए गए सर्वेक्षण की सटीक समीक्षा की है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण ने भारत के युवाओं की विदेश नीति को लेकर समझ और चिंताओं को उजागर किया है। देश के 19 शहरों के 5,000 से अधिक युवाओं से संवाद के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आज का युवा वैश्विक मुद्दों पर गंभीर दृष्टिकोण रखता है। सर्वे में शामिल 88 प्रतिशत युवाओं ने भारत की वर्तमान विदेश नीति का समर्थन किया, जो यह दर्शाता है कि सरकार की वैश्विक रणनीति पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। चीन को लेकर युवाओं की चिंता सबसे अधिक दिखी, जहां 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चीन के साथ सीमा विवाद को सबसे बड़ी चुनौती माना। इसके बाद 86 प्रतिशत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और 85 प्रतिशत ने भारत-पाक सीमा विवाद को अहम बताया। यह युवा वर्ग की रणनीतिक जागरूकता और देश की सुरक्षा को लेकर उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। सर्वे में यह भी सामने आया कि 54 प्रतिशत युवा चीन की चुनौती का जवाब अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाकर देने के पक्षधर हैं। क्वाड जैसे मंचों के प्रति युवाओं में उत्साह है, जबकि शंघाई सहयोग संगठन को लेकर संदेह, क्योंकि उसमें चीन का वर्चस्व है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति अब केवल उच्च स्तर पर लिए निर्णयों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

- विभुक्ति पुनवया, खाचरोद, उज्जैन

दुःखद वास्तविकता

ओडिशा के बालासोर में कॉलेज फैकल्टी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा की आत्महत्या न सिर्फ एक जीवन की क्षति है, बल्कि पूरे शैक्षणिक और प्रशासनिक तंत्र की विफलता को उजागर करती है। यह एक भयावह उदाहरण है कि जब किसी संस्थान की 'इमेज' को एक छात्रा की अस्मिता और न्याय से ऊपर रखा जाता है, तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने पीड़िता पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला, ताकि संस्थान की साख को नुकसान न पहुंचे। यह सोच ही अपराध को पनपाने का सबसे बड़ा कारण है। क्या एक संस्थान की छवि किसी छात्रा के जीवन और आत्मसम्मान से अधिक मूल्यवान हो सकती है? क्या इमेज बचाने के नाम पर सच्चाई को दबाना उचित है? यह घटना दर्शाती है कि जिन लोगों पर छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा है, वही जब शोषण में लिप्त पाए जाते हैं, तो यह शिक्षा जगत की गंभीर गिरावट का संकेत है। दुर्भाग्यवश, ऐसे मामले केवल ओडिशा तक सीमित नहीं हैं; देशभर में यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह एक सामाजिक और नैतिक पतन की तस्वीर पेश करता है, जिसमें पूरा सिस्टम कहीं न कहीं दोषी है। अब समय आ गया है कि सरकारें और प्रशासनिक इकाइयां केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई करें।

- मधु सुभाष पुखावनवाला, रतलाम

संयम रखें शिव भक्त

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में कावड़ यात्रा का धार्मिक महत्व है कांवड़ यात्री पैदल चलकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर आते हैं। यह शिव भक्तों की ऐतिहासिक परंपरा है, जिसके माध्यम से देश के करोड़ कांवड़ यात्री अपनी आस्था दर्शाते है। कांवड़ यात्री इस कठिन यात्रा में अपने पूरे मनोबल, विश्वास और आस्था के साथ हंसते गाते कठिन परिस्थितियों में बम बम भोले का उद्घोष करते अपनी धार्मिक यात्रा को संपन्न करते हैं। सरकार भी इस यात्रा के लिए सफलता के लिए हर संभव प्रयास करती है। यूपी में ही करीब 70000 पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है और बड़े पैमाने में शासन व्यवस्था लगी हुई है ताकि इस यात्रा में कोई विघ्न न पड़े। लेकिन देखने में यह आया है कि इस यात्रा के दौरान उत्तेजना को आक्रोश के कारण अप्रिय घटना हो रही है जो दुखदाई है। कांवड़ियों की नाराजगी का टकराव भी देखने को मिल रहे हैं जोकि हम सबके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। इसमें कुछ शक नहीं की लाखों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार जाते हैं लेकिन यदि इस यात्रा में कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ियों के भेष में उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं तो इससे पूरे कावड़ यात्रा को बदनामी मिलती है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि उत्तेजना पूर्ण घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सरकार, समाज और भोले बाबा के भक्तों की भी है।

- वी के जाटव, नई दिल्ली

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 129

बुनियादी बातों पर हो ध्यान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि सरकार वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी जीसीसी को एक 'बड़े अवसर' के रूप में देख रही है। इससे पहले इस वर्ष के आरंभ में केंद्रीय बजट में उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि जीसीसी को छोटे शहरों की ओर ले जाने के काम को प्रोत्साहित किया जा सके। यह सही है कि एक मरणासन्न उद्योग के लिए जीसीसी एक नया और उत्साहवर्धक घटनाक्रम है। भारत के लिए यह अहम है कि सेवाओं के निर्यात में उसकी ताकत तकनीकी प्रगति से पीछे न छूट जाए, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। कारोबारी प्रक्रियाओं में बदलाव और अंदरूनी स्तर पर क्षमता का विकास जो जीसीसी की वृद्धि से संबंधित हो, भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। सीतारमण ने ऐसे केंद्रों की वृद्धि से संबद्ध वैश्विक भूमिकाओं को लेकर कुछ आशावादी अनुमान पेश किए। मसलन अगर सही कदम उठाए गए और स्वदेशी प्रतिभाएं तैयार की गईं तो उनकी तादाद मौजूदा 6,500 से बढ़कर वर्ष 2030 तक 30,000 हो जाएगी।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अन्य तरीकों के अलावा कराधान और विधायी समर्थन की मदद से जीसीसी की सहायता करेगी। यह बात हमेशा महत्त्वपूर्ण है कि हम कर संबंधी आवश्यकताओं में स्पष्टता और पारदर्शिता रखें। इसमें अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों का उपयोग भी शामिल है। कर कानून जीसीसी की प्राथमिक बाधा नहीं हैं। व्यापक प्रशासनिक, न्यायिक और शासन सुधार भी आवश्यक हैं। यह सही है कि जीसीसी के सामने वही बाधाएं हैं जो देश भर में विनिर्माण सहित कई उद्यमों के सामने हैं। करों को लेकर निश्चितता एक पहलू है लेकिन नियामकीय आवश्यकताओं और अधोसंरचना की उपलब्धता की सुनिश्चितता शायद और अधिक महत्त्वपूर्ण है। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो जैसा कि नए और उभरते क्षेत्रों के साथ है, सरकार को यह समझना होगा कि उसकी भूमिका विकास में बाधा डालने वाली चीजों को ठीक करना और फिर रास्ते से हट जाना है। सरकार को बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भवन निर्माण की मंजूरी समय पर मिल जाए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजली की अबाध आपूर्ति हो। जो बातें विनिर्माण और खुदरा क्षेत्र के लिए सही होंगी वही जीसीसी के लिए भी उपयुक्त होंगी। व्यापक कारोबारी माहौल में सुधार होना चाहिए ताकि भारत जीसीसी का लाभ ले सके। जैसा कि इतिहास ने हमें दिखाया है, अगर व्यापक माहौल प्रतिकूल हो तो किसी एक क्षेत्र पर या किसी एक बाधा पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ खास नहीं हासिल होने वाला है।

गहन सवाल यह है कि क्या भारत का मानव संसाधन मूल्य श्रृंखला में परिवर्तन के लिए तैयार है। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के निर्यात के पिछले संस्करण आवश्यक तौर पर उच्च कौशल वाले कर्मियों की नियुक्ति पर निर्भर नहीं थे। बहरहाल अगर जीसीसी के भीतर वैश्विक भूमिकाएं ही अंतिम लक्ष्य हैं तो बात अलग है। मानव संसाधन में निवेश भारत के लिए हमेशा से समस्या रही है और अतीत की कौशल संबंधी पहलें या तो पूर्व अर्हता पर बहुत अधिक निर्भर रहीं या फिर वे उन कौशलों के साथ सुसंगत नहीं थीं जो निजी क्षेत्र के संभावित नियोक्ताओं के लिए जरूरी थे। अगर जीसीसी को उच्च उत्पादकता वाले कर्मचारी चुनने हैं तो इन हालात को बदलना होगा। आखिर में, जीसीसी के समग्र पारिस्थितिक प्रभाव पर गहराई से चर्चा करने की आवश्यकता है।

भारत के अंदर अधिक मूल्यवर्धन अपने आप में एक ऐसा लक्ष्य है जिसका अनुसरण करना आवश्यक है, लेकिन जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र के नवाचार और उद्यमिता पर इसका क्या असर होगा? पारंपरिक शोध नेटवर्क अक्सर सकारात्मक प्रभावों से इस प्रकार लाभान्वित होते हैं कि घरेलू कंपनियां चाहे पुरानी हों या नई, नई तकनीक और अवसर पा सकें। जीसीसी में चुनिंदा और सीमित अनुसंधान कार्यक्रमों का शायद उतना असर न पड़े।

ऐप्स को स्पष्ट सहमति की ओर बढ़ना होगा

ऑनलाइन दुनिया में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि शक्ति संतुलन ऐप्स के बजाय उपयोगकर्ताओं की ओर स्थानांतरित हो। बता रहे हैं अजित बालकृष्णन

रोज शाम मुंबई के कोलाबा में शाम की सैर के समय जब मैं सॉसन डॉक के निकट मछुआरों को अपना मोबाइल फोन निकालकर फलों की दुकान में क्यूआर कोड से भुगतान करते देखता हूं तो मैं ऊर्जा से भर जाता हूं। मुझे देश की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और आधार कार्ड व्यवस्था पर बहुत गर्व होता है क्योंकि ये भारतीय समाज को हर स्तर पर फायदा पहुंचा रही हैं।

हालांकि, देश के डिजिटलीकरण को लेकर मेरे राष्ट्रवादी गौरव को पिछले सप्ताह उस समय झटका लगा जब मैंने राहुल भाटिया की सुलिखित पुस्तक 'द आइडेंटिटी प्रोजेक्ट: द अनमेकिंग ऑफ द डेमोक्रेसी' को पढ़ना शुरू किया।

पुस्तक में कहा गया है कि 'आधार' जिसे (मुझ समेत) अधिकांश भारतीय तकनीकी उन्नति का प्रतीक मानते हैं, उसने राज्य की निगरानी का असाधारण ढांचा खड़ा कर दिया है। वह बताते हैं कि कैसे लोगों के व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा का इतना व्यापक और केंद्रीकृत संग्रहण जोखिम भरा हो सकता है। जब मैंने यह खंगालना शुरू किया कि क्या किसी अन्य लेखक या विचारक ने भी आधार को लेकर ऐसी ही राय प्रकट की है तो मेरी नजर में कई लेखक आए। रितिका खेड़ा की पुस्तक 'डिसेंट ऑन आधार: बिग डेटा मीट्स बिग ब्रदर' में अर्थशास्त्रियों, अधिवक्ता, तकनीकविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे तमाम विशेषज्ञों के आलेख शामिल हैं। यह पुस्तक अलग-अलग कोणों से आधार परियोजना की व्यापक आलोचना प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। उसके बाद बेल्जियम में जन्मे भारतीय विकास अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज कहते हैं कि देश की वंचित और कमजोर आबादी पर इंटरनेट निर्भर एक ऐसी तकनीक थोपना बर्बरता की ओर उठाया गया कदम है और यह लोगों के समावेशन के बजाय बहिष्कार का कदम है। इन आलोचनाओं के जवाब में केंद्र ने सही बिंदु उठाया कि आधार पहचान का उपाय है और उसका लक्ष्य प्रोफाइलिंग करना नहीं है।

यह भी कहा गया कि आधार संवेदनशील जानकारी मसलन जाति, धर्म, स्वास्थ्य रिकॉर्ड या वित्तीय ब्योरे आदि नहीं एकत्रित करता। यह भी कहा गया कि वह बेहतरीन इनक्रिप्शन और सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल करता है ताकि डेटा का संरक्षण किया जा सके। हमने एक अहम सबक भी सीखा: आधार/यूपीआई की सफलता का 'राजनीतिक अर्थशास्त्र' विशुद्ध रूप से मुक्त बाजार की घटना नहीं थी। इसके लिए राज्य को पहल करके एक पारिस्थितिकी तैयार करनी पड़ी जहां लाखों लोग तत्काल इसका लाभ उठा सकें। केंद्र ने यह व्यवस्था बनाने के लिए निजी कंपनियों का इंतजार नहीं किया। उसने एक बुनियादी डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना तैयार की: पहचान के लिए आधार और एक मुक्त पारस्परिक संचालन वाले प्लेटफॉर्म के रूप में यूपीआई। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी पहलों ने यह सुनिश्चित किया कि लाखों लोगों के पास बैंक खाते हों जिन्हें इन व्यवस्थाओं से जोड़ा जा सके।

इसके बाद गत सप्ताह यह खबर आई, 'सैन जोस, कैलिफोर्निया की एक जूरी ने मंगलवार को कहा कि गूगल ने ग्राहकों के सेलफोन डेटा का दुरुपयोग किया और ग्राहकों के अधिवक्ताओं के मुताबिक उसे प्रांत के एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को 31.46 करोड़ डॉलर का भुगतान करना होगा।' रिपोर्ट आगे कहती है कि जूरी इस बात से सहमत है कि गूगल ने बिना उपयोगकर्ताओं की जानकारी के उनके उपकरणों से सूचनाएं भेजीं और प्राप्त कीं। यह उस समय किया गया जब उपकरण इस्तेमाल भी नहीं हो रहे थे। ऐसा करके कंपनी ने उपभोक्ताओं की कीमत पर लाभ अर्जित किया।

वर्षों से टेक उद्योग 'निहित सहमति' पर काम कर रहा है। एक सेवा का इस्तेमाल करके हम लंबी और जटिल सेवा शर्तों को मंजूरी दे देते हैं। ये अक्सर डेटा संग्रह की अनेक मंजूरियां चाहते हैं। ऊपर जो ब्योरा दिया गया है वैसे निर्णय स्पष्ट और सूचित सहमति के मॉडल की ओर बदलाव को गति प्रदान करेंगे। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि 'इजाजत' स्थायी नहीं है? एक उपयोगकर्ता कोई ऐप इंस्टॉल करते समय इजाजत देता है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐप को उसके डेटा को अंतहीन ढंग से स्थानांतरित करने की इजाजत मिल जाए। क्या इससे गूगल जैसी कंपनियां अधिक पारदर्शी नियम बनाने पर विवश होंगी ताकि बैकग्राउंड में होने वाले हर डेटा स्थानांतरण को उचित ठहराया जा सके। हालांकि, अगर हर तरह के डेटा स्थानांतरण के लिए स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता होगी और कई उपयोगकर्ता मना कर देंगे तो इससे इनके कारोबारी मॉडल पर बुरा असर होगा। तब कंपनियों को अपनी सेवाओं के मुद्रीकरण के नए तरीके तलाश करने होंगे या फिर उदाहरण के लिए ऐप्स की ओर से नया संदेश यह मिल सकता है, 'हमें सेवा को निःशुल्क रखने के लिए यह डेटा संग्रहीत करने दीजिए या फिर निजी संस्करण के लिए सबस्क्रिप्शन शुल्क चुकाइए।'

जब मैंने एक जानकार यूरोपीय मित्र से पूछा कि आखिर क्यों यूरोप ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन यानी जीडीपीआर में 'स्पष्ट सहमति' को तेजी से अपनाया तो उनका जवाब था, 'यूरोप के 20वीं सदी के इतिहास पर नजर डालिए। नाजी शासन ने जनगणना और व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल दमन के लिए किया। सोवियत धड़े की निगरानी प्रणाली ने नागरिकों को ट्रैक किया तथा फासीवादी व कम्युनिस्ट सरकारों ने अलग-अलग तरह से इनका इस्तेमाल किया। इन सब बातों ने यूरोप के भीतर व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की भारी आशंका पैदा कर दी।' मैंने उनसे पूछा कि क्या यही वजह है कि अमेरिका के उलट यूरोप में डेटा आधारित कारोबारी मॉडल वाली बड़ी टेक कंपनियां नहीं हैं तो उन्होंने इसका उत्तर भी हां में दिया।

स्पष्ट इजाजत की बात शक्ति संतुलन में भी परिवर्तन ला सकती है। यह उस विचार पर बल देगी कि उपयोगकर्ता ही अपने डेटा का वास्तविक स्वामी है और उसके पास उसके उपयोग का स्पष्ट और निरंतर नियंत्रण होना चाहिए। प्रमाणित करने का बोझ उपयोगकर्ता पर यह पता लगाने से हट जाएगा कि बाहर कैसे निकला जाए, तथा कंपनी पर यह तर्क देने का भार आ जाएगा कि उसे उपयोगकर्ता को बाहर निकलने की आवश्यकता क्यों है।

क्या इसका अर्थ अपारदर्शी, निहित सहमति से एक अहम बदलाव और ऐसे भविष्य की ओर बढ़ना है जहां उपयोगकर्ता की अनुमति स्पष्ट, विस्तृत और प्रासंगिक हो? क्या इसका अर्थ यह है कि भारत को जल्दी ही उपयोगकर्ता अनुमति के संबंध में इस क्षेत्र में नए कानून की जरूरत होगी। यहां तक कि आधार और यूपीआई जैसे सार्वजनिक संस्थानों द्वारा एकत्रित डेटा के लिए भी?

समुद्री क्षेत्र में डिजिटल जीवनरेखाओं की सुरक्षा अहम

समुद्र के भीतर बिछी केबल (सबमरीन केबल) डिजिटल दौर की मूक जीवनरेखाएं हैं, जो वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक के 99फीसदी का संचालन करने में अहम भूमिका निभाती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास को गति देती हैं। इन केबल की क्षमता हर दो से ढाई साल में दोगुनी हो जाती है। हर साल इनमें 70,000 से एक लाख किलोमीटर का इजाफा होता है और इन पर 10 अरब डॉलर का निवेश होता है।

वर्ष 2024 तक, दुनिया भर में 550 से ज्यादा केबल सिस्टम बिछे हुए थे जिनकी कुल लंबाई 14 लाख किलोमीटर है यानी ये इतनी लंबी हैं कि इनसे पृथ्वी को 35 बार घेरा जा सकता है। भारत में डेटा इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में उसके लिए भी समुद्र के भीतर केबल नेटवर्क का बढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तक, निजी कंपनियों के बदौलत इस उद्योग में तेज वृद्धि हुई है लेकिन यह काम थोड़ा बेतरतीब रहा है। लूजोन स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट जैसे कुछ खास जगहों पर इन केबलों का बेहद घना क्लस्टर है, जिससे उनके टूटने का खतरा बना हुआ है। इन सबमरीन केबल के बेहतर प्रबंधन के लिए कोई औपचारिक नियम-कानून नहीं है, जिससे सुरक्षा संबंधी दिक्कतें पैदा होने पर भविष्य में गंभीर रणनीतिक परिणाम हो सकते हैं।

एक रणनीतिक बदलाव यह परिभाषित कर रहा है कि देश समुद्र के नीचे केबलों को किस प्रकार अहमियत दे रहे हैं। दरअसल, अब इन्हें सिर्फ वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा ही नहीं बल्कि देश की संप्रभुता और वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने वाली चीज मानी जा रही है। अमेरिका का लंबे समय से इस क्षेत्र में दबदबा रहा है, लेकिन चीन अपनी 'बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव' योजना का इस्तेमाल कर, प्रमुख संचार मार्गों पर अपना नियंत्रण करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर, चीन के साथ मिलकर 'डिजिटल सिल्क रोड' में अपनी भूमिका तैयार कर रहा है। चीन द्वारा बनाई गई केबल को लेकर बढ़ती चिंता के कारण, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान 'स्वच्छ केबल' समूह बनाने पर जोर दे रहे हैं। भू राजनीतिक दबाव के कारण, दक्षिण पूर्व एशिया-पश्चिम एशिया-पश्चिमी यूरोप 6 केबल परियोजना से चीन की कंपनियों के हटने के बाद, उन्होंने यूरोप-पश्चिम एशिया-एशिया परियोजना के तहत फिर से मिलकर काम शुरू किया। चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉम के नेतृत्व में, चीन अब हॉन्गकॉन्ग, हेन्नान, सिंगापुर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और फ्रांस को जोड़ रहा है जिसके लिए हुआवे मरीन टेक्नॉलजीज भी मुख्य ठेकेदार कंपनी के रूप में मौजूद है।

अजय कुमार

दुर्घटना से होने वाले नुकसान के अलावा, सबमरीन केबलों को क्षतिग्रस्त करने का एक बड़ा खतरा है, क्योंकि इसे आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। हाल ही में, चीन के एक जहाज शुनशिंग-39 ने ताइवान के कीलुंग हार्बर के पास समुद्र के नीचे की केबलों को काट दिया जो चीन की सीधे-सीधे युद्ध घोषित किए बिना किसी को परेशान करने की नीति के तहत ही केबल हमलों के इस्तेमाल का संकेत है। स्नोडेन लीक से पता चला कि दुश्मनों द्वारा स्प्लाइस चैंबर (जोड़ने वाले हिस्से) और ऑप्टिकल स्प्लिटर का उपयोग करके केबल को टैप किया जा रहा है। लूजोन स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन के खोजी जहाजों की बढ़ती गतिविधि, वास्तव में केबलों का नक्शा बनाने और जासूसी उपकरण लगाने के संकेत देती है ताकि जरूरत पड़ने पर संभावित सामरिक बाधा के लिए तैयारी की जाए।

चीन केबल बिछाने, केबल शिप बनाने और दोहरे उपयोग वाले समुद्री बुनियादी ढांचा तैयार करने में अपनी भूमिका तेजी से बढ़ा रहा है। पश्चिमी देशों और जापान की कंपनियां अब भी केबल मरम्मत में आगे हैं, लेकिन चीन अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है और चार से छह मरम्मत करने वाले जहाजों का संचालन कर रहा है, जिनमें से कम से कम एक का संबंध, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना से बताया जाता है। इसके विपरीत, भारत के पास ऐसा केवल एक निजी जहाज है और यह बड़े पैमाने पर विदेशी जहाजों पर निर्भर है। यह निश्चित रूप से कमजोर स्थिति को दर्शाता है खासतौर पर संकट के दौरान, क्योंकि इससे देरी का खतरा बना रहता है। भारत को अपनी केबल मरम्मत क्षमता बढ़ाने पर विचार करना चाहिए और यह संभवतः किसी सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड के माध्यम से होना चाहिए। इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि चीन के जहाजों से सावधान रहने वाले क्षेत्रीय भागीदारों को भी सहयोग मिलेगा।

सबमरीन केबल से जानकारी चुराने के खतरे से निपटने के लिए, महत्त्वपूर्ण रास्तों की लगातार निगरानी करने के साथ ही समुद्र तल के नीचे आधुनिक क्षमताएं विकसित करना जरूरी है, जिनमें सेंसर और मानवरहित जहाज शामिल हैं। आईडेक्स पहल के तहत एक दर्जन से अधिक ऐसी तकनीकें खरीदी जा रही हैं और इन्हें तेजी से पूरा किया जाना चाहिए।

कई देशों ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) और महाद्वीपीय क्षेत्र के दायरे के भीतर सबमरीन केबलों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। अमेरिका में, कानूनों के तहत संस्थाओं को सबमरीन केबल बिछाने के लिए औपचारिक अनुमति लेनी होती है और साथ ही कोई भी गतिविधि न करने वाले सुरक्षित क्षेत्र बनाने होते हैं। इसके अलावा ईईजेड और महाद्वीपीय क्षेत्र के भीतर उल्लंघन करने पर जुर्माना लगता है। इसके विपरीत, भारतीय कानून समुद्री तल के संसाधनों और प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए अधिकार तो देता है, लेकिन नियम तभी लागू करने की अनुमति देता है जब किन्हीं गतिविधियों के कारण सीधे इन अधिकारों में हस्तक्षेप होता है। यह एक बड़ी कमी है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में सबमरीन केबलों की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां कानून को ठीक से लागू करने की स्थिति कमजोर है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय कानून में भी कमियां हैं।

समुद्री क्षेत्र से जुड़े कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौता सभी देशों को खुले समुद्र में केबल बिछाने की अनुमति देता है और उनसे यह भी कहता है कि वे अपने नागरिकों या अपने देश के झंडे वाले जहाजों द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से हुए नुकसान को अपराध मानें और इसे लागू करने में सहयोग करें। लेकिन, जब कानून को लागू करने का काम उन जहाजों वाले देश पर छोड़ दिया जाता है तब किसी देश के सरकार समर्थित नुकसान से निपटना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चोर को घर की चाबियां सौंपकर घर के सुरक्षित रहने की उम्मीद करना। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) केबल बिछाने और सुरक्षित क्षेत्रों के लिए तकनीकी मानकों और दिशानिर्देशों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन नियमन पर नहीं। आईटीयू के तहत अंतरराष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (आईसीपीसी), केबल संरक्षण क्षेत्रों के लिए बेहतर कदम और मानदंड की बात करती है। आईसीपीसी के तहत हाल ही में एक और अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय स्थापित किया गया है, लेकिन यह भी केवल सलाहकार की भूमिका तक ही सीमित है।

कोई अंतरराष्ट्रीय समुद्री निगरानी व्यवस्था न होने के कारण, भारत को खुले समुद्र में सबमरीन केबलों की सुरक्षा के लिए अपने साधन विकसित करने होंगे। इसमें अंतरिक्ष और नौसेना के संसाधनों का उपयोग करके संदिग्ध जहाजों, खासतौर पर चीन के सर्वेक्षण जहाजों की निगरानी करना और हिंद महासागर के प्रमुख गलियारों के पास नौसेना की मौजूदगी बनाए रखना शामिल है।

भारत को निजी परिचालकों के साथ मिलकर छेड़छाड़ रोधी केबल डिजाइन करने, उन्हें समुद्र तल की अधिक गहराई में दबाने और मजबूत इन्क्रिप्शन (गोपनीयता) सुनिश्चित करने के लिए भी काम करना चाहिए। इसके लिए क्वाड सहित मित्र देशों के साथ गंभीर सहयोग आवश्यक है।

केबल को इरादतन क्षतिग्रस्त किए जाने के लिए तैयार रहने के लिए, भारत को अतिरिक्त व्यवस्था करने के साथ ही, वैकल्पिक सबमरीन केबल मार्ग तैयार करने होंगे। केबल को राष्ट्रीय स्तर के महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के तहत औपचारिक रूप से महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' घोषित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एक राष्ट्रीय सबमरीन केबल सुरक्षा ढांचा बनाने का नेतृत्व कर सकता है, जिसमें सरकार, भारतीय नौसेना, तटरक्षक और निजी केबल ऑपरेटरों जैसे प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया जा सकता है।

आज की दुनिया में, सबमरीन केबलों की सुरक्षा सिर्फ इंटरनेट परिचालन से ही नहीं बल्कि यह देश को सक्षम करने से जुड़ी है। इनकी रखवाली करना केवल अच्छी नीति नहीं है बल्कि यह परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में राष्ट्र की संप्रभुता और रणनीति के प्रमुख आधार की रक्षा करना है।

(लेखक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा सचिव हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

आपका पक्ष

ओडिशा की छात्रा की मौत की हो गंभीरता से जांच

ओडिशा के बालासोर जिले में कॉलेज छात्रा की मौत का मामला काफी गंभीर है। बताया जा रहा है कि फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज की बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा ने यौन उत्पीड़न के आरोपी एक प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कॉलेज परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश की थी। तीन दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद सोमवार की देर रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद राज्य के लोगों में आक्रोश है। हालांकि, कॉलेज की एक छात्रा ने बताया कि उसकी सहपाठी कॉलेज की राजनीति का शिकार हो गई। उस छात्रा का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को बचाने के वास्ते संस्थान के ही सैकड़ों छात्रों से छात्रा का चरित्रहनन कराया था। इससे भी आहत होकर उसने आत्मदाह करने जैसा गंभीर कदम उठाया। हादसे के बाद से घटना को लेकर राजनीति की जा रही है। एक ओर जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की भर्त्सना कर रही है। वहीं, बीजू जनता दल और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को ओडिशा में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन कर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के इस्तीफे की भी मांग की। हालांकि, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य और आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन राजनीतिक दल न्यायिक जांच का आदेश देने की मांग कर रहे हैं। सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थान में अगर छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं तो यह गंभीर मसला है।

कुमार रामपाल, भोपाल

बालासोर में छात्रा की मौत के मामले में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाकर बुधवार को बीजू जनता दल के नेताओं ने प्रदर्शन किया

वनों के संरक्षण के लिए सघन व सतत प्रयास जरूरी हैं

भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी आईएसएफआर ने देश के लिए चिंताजनक रुझान प्रकट किए हैं। वन क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट ने सभी को हैरान कर दिया है। हालांकि देश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए, सरकार कई उपाय कर रही है, जिनमें गैर-कृषि योग्य भूमि पर पौधरोपण को बढ़ावा देना, वन अपराधों को नियंत्रित करना और स्थानीय समुदायों को शामिल करके संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना शामिल है। परंतु इसके अलावा, गैर-इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा देना और इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, बांस, चारा और लघु वन उपज का इष्टतम उपयोग करना भी आवश्यक है। साथ ही, इकोटूरिज्म और हर्बल हेल्थ टूरिस्ट के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें और वनों के संरक्षण में मदद मिल सके। मानव-वन्यजीव संघर्ष से बचाने के लिए वन्यजीवों को संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थानांतरित करके और वन्यजीवों के संरक्षण/प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करके, देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने और वनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, जैव विविधता बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने, और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए देश में वनों का संरक्षण आवश्यक है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

जयपुर के सैन्य अड्डे में बुधवार को 'सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स' द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। वहां आयोजित 'नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट: शेपिंग टुमॉरोज मिलिट्री टुडे' संगोष्ठी में दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने भारतीय सेना को आधुनिक और भविष्य के युद्धों की बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए तेजी से नवाचार अपनाने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • बृहस्पतिवार • 17 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

निशाना आतंकवाद पर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद व उग्रवाद की चुनौती से सख्ती से निपटने के उद्देश्यों पर अडिग रहने का आह्वान करते हुए कहा, भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वह बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में नृशंस आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने इन तीनों चुनौतियों के अक्सर साथ आने की बात भी की। आतंकियों, प्रायोजकों, आयोजकों व वित्त पोषकों को जवाबदेह बनाने तथा न्याय के कठघरे में लाने की जरूरत पर भी बल दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बल दिया कि अशांत और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के मद्देनजर संगठन को कुशलतापूर्वक कार्य करना होगा। शी ने क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता की रक्षा व सदस्य देशों के

विकास की बात भी की। इस सम्मेलन में दस अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के अतिरिक्त बीस से ज्यादा देशों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के भाग लेने की भी चर्चा थी। मोदी इसमें शामिल होते हैं तो इसे गलवान गतिरोध के बाद भारत-चीन संबंधों में संभावित परस्परता, संबंधों में सुधार व कूटनीतिक नरमी के संकेत के रूप में लिया जा सकता है। 2023 में मोदी ने इस सम्मेलन में वर्चुली शिरकत की थी जबकि बीते वर्ष उनकी अनुपस्थिति को घटते सामरिक महत्व से जोड़ कर देखा गया। हालांकि रूस कभी नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी संगठन चीन के प्रभुत्व वाला मंच बन जाए। इसमें पाकिस्तानी, रूसी व ईरानी विदेश मंत्री के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। यह भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान व बेलारूस का प्रभावशाली आर्थिक व सुरक्षा समूह है। अमेरिका से सीधा दो-दो हाथ करने वाले शी ने परोक्ष रूप से उस पर कटाक्ष करते हुए बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देने व उसकी धौंस का विरोध करने के लिए संयुक्त प्रयासों का भी आह्वान किया। बेशक, भू-राजनीतिक परिदृश्य में आ रहे बदलावों को देखते हुए रूस व चीन दुनिया के समक्ष अपनी ताकत का मुजाहिरा करने को बेताब हैं। एशिया के सभी प्रमुख देशों को अपनी प्राथमिकताओं का ख्याल रखते हुए आतंकवाद से जूझना है। अमेरिका विरोधी रुखखासकर पश्चिमी देशों को सीधा टक्कर देने वाला रुख भारत का कभी नहीं रहा है। भारत आतंकवाद से निपटने को चुनौती के तौर पर देख रहा है, मगर वह अपनी वैश्विक छवि व कूटनीतिक चुनौतियों पर आंच नहीं आने देना चाहेगा।

टेस्ला का हल्ला

जिस दिन देश में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में कमी आने की रिपोर्ट आई ठीक उसी दिन अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने धूमधाम से भारत में प्रवेश कर लिया। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला 'एक्सपीरियंस सेंटर' खोला है। खेद की बात यह कि कंपनी भारत में कार बनाने नहीं, बल्कि आयातित कारें बेचने आई है। मस्क ने इससे पहले उच्च आयात शुल्क को कंपनी के भारत में नहीं आने की वजह बताया था। कंपनी चीन स्थित शंघाई विनिर्माण संयंत्र में बने मॉडल 'वाई' को आयात करके भारत में बेचेगी जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है। मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक एसयूवी 'वाई' कभी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार थी। यह भारत में दो संस्करणों में उपलब्ध होगी। दोनों कारें एक बार की चार्जिंग में क्रमशः 500 और 622 किमी. का सफर तय कर सकती हैं। मस्क की कंपनी टेस्ला कुछ समय से बिक्री में

गिरावट से जूझ रही है। मस्क लंबे समय से भारत में टेस्ला को लाने की प्लानिंग कर रहे थे। उनकी योजना भारत में टेस्ला का कारखाना लगाने की भी थी। भारत में जिस मॉडल की कीमत लगभग 60 लाख रुपये है, उसी मॉडल की कीमत अमेरिका में 44,990 डॉलर यानी लगभग 39 लाख रुपये है, चीन में 36,700 डॉलर यानी 32 लाख रुपये और जर्मनी में 45,970 डॉलर यानी करीब 39 लाख 50 हजार रुपये है। टेस्ला भारत में जिन कारों को ग्राहकों के लिए लेकर आएगी उन पर करीब 100 फीसद टैरिफ लगेगा। टेस्ला के भारत में आने से हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जब तक यह भारत में विनिर्माण संयंत्र नहीं लगाती तब तक भारतीयों को अपने बीच के ही चंद अरबपतियों की कारें देख कर खुश होना पड़ेगा। वैसे भी टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कारों के प्रीमियम ग्रुप को ही लक्ष्य बना रही है। ये भारत के कुल ऑटोमोबाइल मार्केट का 4 फीसद है। टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली घरेलू कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। उसका मुकाबला होगा बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज से। सरकार कहती है कि देश में लोग तेजी से गरीबी की रेखा से ऊपर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की राय इसके उलट है। आप भी टेस्ला की कार चलाना चाहते हैं तो अमेरिका से ट्रेड डील या भारत के टैरिफ घटाने का इंतजार करें।

कटाक्ष/ सहीराम

पुरस्कार इनके, पुरस्कार उनके

इधर मोदी जी पर तो पुरस्कार ऐसे बरस रहे हैं, जैसे चिरापूंजी में मेंह बरसता है और ट्रंप साहब नोबल के लिए ऐसे टकटकी लगाए बैठे हैं जैसे मरुभूमि का किसान बादलों पर टकटकी लगाए बैठा रहता है। बताते हैं कि मोदी जी ने अब तक छब्बीस पुरस्कार जीत लिए। जल्द ही वे छप्पन तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रंप साहब एक के लिए भी तरसे जा रहे हैं। अलबत्ता, उनके लिए भी सिफारिशें होने लगी हैं। पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने तो यह सिफारिश व्हाइट हाउस में दावत उड़ाने के बाद की। वैसे भी अंग्रेजी की कहावत है न कि-देयर इज नो फ्री लंच।

खैर, पुरस्कार तो जनरल साहब भी ले उड़े। ऑपरेशन सिंदूर से और किसी को कुछ मिला हो या न मिला हो, उन्हें पदोन्नति जरूर मिल गई-जनरल से फील्ड मार्शल हो गए। पर ट्रंप साहब को भारत के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं, हम जंजीरों में बांध कर भारतीयों को वापस भेजे जाने की बात नहीं कर रहे। न ही हम उस पीड़ा को बयान कर रहे हैं, जब उन्होंने हमारे मोदी जी को शपथ ग्रहण पर न्योता तक नहीं दिया था। लेकिन जब जनरल मुनीर व्हाइट हाउस में दावत उड़ा रहे थे, तभी बताते हैं कि हमारे एक युवा और सूर्य समान तेजस्वी सांसद को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से इतनी बुरी तरह से खदेड़ा कि भारत से बांग्लादेशियों को भी क्या खदेड़ा जाता होगा। खैर, कुछ लोग तो यहां तक अंदेशा जता रहे हैं कि कहीं मोदी जी पुरस्कार पाने के लिए ही तो विदेश यात्रा नहीं करते। लेकिन फिर दूसरे इसका खंडन कर देते हैं कि नहीं वे तो अडानी को धंधा दिलाने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। पुरस्कार तो बोनस है। लेकिन विघ्नसंतोषी कहते हैं कि विदेश मंत्रालय पहले ही जुगाड़ बिठा लेता है। पूछ लेता है अगर कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दो तो मोदी जी आएंगे नहीं तो नहीं। इस चक्कर में बताते हैं कि एकाध ने तो सर्वोच्च की बजाय सर्वोच्च के नाम पर दूसरे दर्जे का पुरस्कार भी उन्हें टिका दिया। खैर जो भी हो, अच्छा किया जो मोदी जी नोबल के चक्कर में नहीं पड़े। वैसे शुरू में भक्त लोग जिस तरह से वार रुकवाने का प्रचार कर रहे थे, उससे लगा था कि नोबल की चाह तो होगी। लेकिन फिर ट्रंप ने वार रुकवाने का ठेका ले लिया, तो मोदी जी पीछे हट गए। अब ट्रंप साहब करते रहें नोबल का इंतजार, मोदी जी ने तो छब्बीस बटोर लिए।

अनमोल वचन

जैसे-जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, उसके खिलौने और भी महंगे होते जाते हैं।

-मार्विन डेविस

आर्थिक-सामरिक मजबूती जरूरी

सामयिक

जयंतीलाल भंडारी

यकीनन इस समय भारत के समक्ष जो आर्थिक और सैन्य चुनौतियां हैं, उनके मद्देनजर भारत को दुनिया की नई वैश्विक आर्थिक शक्ति और उन्नत परमाणु शक्ति बनना जरूरी है। चार जुलाई को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया, बल्कि पाकिस्तान को परोक्ष रूप से हरसंभव सहायता देने वाले चीन और तुर्किए को भी हराया है।

यद्यपि एक जुलाई से 31 जुलाई तक एक माह के लिए पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद वह अध्यक्ष के रूप में कोई विशेष शक्ति नहीं रखता, फिर भी उसने भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं हुई है। पाकिस्तान की सरकार और उसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत को बार-बार गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। 30 जून को मुनीर ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को वैध संघर्ष बताते हुए कहा कि उनका देश कश्मीर के लोगों के संघर्ष में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। भारत को मात देने के लिए चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल कर नया सार्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

इस नये सार्क में दक्षिण एशिया के अन्य देशों को भी शामिल करने की तैयारी है। ऐसे में देश के पड़ोसी दुश्मन देशों पाकिस्तान और चीन के बढ़ते नापाक गठबंधन और उनके द्वारा लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के परिदृश्य के मद्देनजर भारत को नई आर्थिक शक्ति और नये दौर के उन्नत परमाणु हथियारों की क्षमताओं से सुसज्जित होना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि इस्राइल-ईरान युद्ध और आपरेशन सिंदूर के तहत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के परिणामों का विश्लेषण बताता है कि युद्ध में नई एआई तकनीक और आर्थिक ताकत की अहमियत दिखाई दी है, और परमाणु हमले की धमकी बेअसर साबित हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान द्वारा चीन के सहयोग से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियार विकसित किए जाने के मद्देनजर भारत के लिए उन्नत परमाणु शक्ति-संपन्न देश बनना भी जरूरी है। चूंकि शक्ति के माध्यम से ही शांति आती है, और शक्ति से ही भविष्य के युद्ध भी रोके जा सकते हैं, अतएव भारत को हर मोर्चे पर शक्तिशाली बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश के आसमान छूते वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्यमी-कारोबारी और पूरे देश का जन-बल एकजुटता से कदम बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछली 24 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने आर्थिक-सामरिक क्षेत्र को मजबूत बनाया है। आतंकवाद के प्रति कठोर नीति अपनाई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने महज 22 मिनट में स्वदेशी हथियारों से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।

वस्तुतः ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एआई के उपयोग से पाकिस्तान के लक्षित आतंकी ठिकानों को बर्बाद करके अभूतपूर्व मिसाल पेश की। ऐसे में भारत, दुनिया की आर्थिक शक्ति बनने, पाकिस्तान और चीन की सैन्य चुनौतियों से मुकाबले के लिए एआई तकनीकों और उन्नत परमाणु हथियारों से शक्ति-संपन्न देश बनने की संभावनाओं को साकार कर सकता है। निस्संदेह भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इसे वैश्विक आर्थिक शक्ति बना सकती है। यह छोटी बात नहीं है कि पिछले दिनों दुनिया को हिला देने वाले इस्राइल और ईरान के बीच भारत अपने बहुआयामी आर्थिक आधारों से युद्ध की आर्थिक चुनौतियों के बीच सक्षम बन कर मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जहां इस युद्ध से कई देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम में वृद्धि, व्यापार में कमी, खाद्यान्न सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कमी और शेयर बाजार में गिरावट का परिदृश्य उभर कर दिखाई दिया, वहीं भारत इन सब मुश्किलों के मद्देनजर बेहतर स्थिति में बना रहा है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ संघर्ष का भी भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। भारत का बड़ा घरेलू बाजार, कम निर्यात निर्भरता, सरकार के भारी पूंजीगत व्यय, बढ़ती क्रय शक्ति, मेक इन इंडिया और कृषि क्षेत्र में ऊंची सफलता ने देश को बाहरी आर्थिक झटकों को झेलने के लिए मजबूत स्थिति में रखा है।

युद्ध के दौर में भी भारत के निर्यात बढ़े हैं, और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि हुई है। भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 फीसद रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की विश्व आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते दिखाई देगा। निश्चित ही इस्राइल-ईरान युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर का यह भी सबक है कि युद्ध सिर्फ आर्थिक ताकत और अत्याधुनिक एआई तकनीक के दम पर ही लड़े जाते हैं तथा केवल परमाणु हमले की धमकी से युद्ध नहीं जीते जाते। किंतु इस समय पाकिस्तान और चीन की युद्ध चुनौतियों के मद्देनजर भारत को परमाणु हथियारों को उन्नत होना भी जरूरी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या में कमी का युग खत्म हो रहा है।

अब परमाणु हथियारों में वृद्धि और हथियार नियंत्रण समझौतों को छोड़ने की प्रवृत्ति दिख रही है। दुनिया के नौ परमाणु शक्ति-संपन्न देश-अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इस्राइल-सभी अपने परमाणु हथियारों को और उन्नत करने में जुटे हैं। भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह पराजित होकर चीन की मदद से अपने परमाणु हथियारों को उन्नत करने की कोशिश में जुट गया है, ऐसे में भारत का उच्च परमाणु शक्ति बनना जरूरी है। उम्मीद करें कि सरकार इस्राइल-ईरान युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर से निकले उम्मीदों भरे आर्थिक-सामरिक सबक के मद्देनजर भारत को आर्थिक शक्ति, एआई की नई तकनीकों और उन्नत परमाणु शक्ति-संपन्न देश बनाने के लिए रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ेगी।

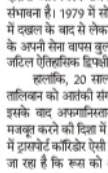

(लेख में विचार निजी हैं)

> इस्राइल-ईरान युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर का यह भी सबक है कि युद्ध सिर्फ आर्थिक ताकत और अत्याधुनिक एआई तकनीक के दम पर ही लड़े जाते हैं तथा परमाणु हमले की धमकी से युद्ध नहीं जीते जाते। किंतु इस समय पाकिस्तान और चीन की युद्ध चुनौतियों के मद्देनजर भारत द्वारा परमाणु हथियारों को उन्नत किया जाना भी जरूरी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या में कमी का युग खत्म हो रहा है

औषधीय गुणों से भरपूर 'बिटर एप्पल'

त्वचा का रखता है खास ख्याल

- इंद्रायण पौधे के न सिर्फ फल, बल्कि बीज, पत्ता और जड़ भी कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। इसका फल छोटे तरबूज जैसा लगता है, ऊपर सफेद धारियां होती हैं, जो पकने पर पीले रंग की हो जाती हैं। हालांकि इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इसके गुण शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाते हैं

- अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इंद्रायण को अंग्रेजी में बिटर एप्पल या सिट्रुलस कोलोसिंथिस भी कहा जाता है। रिसर्च से पता चला है कि यह इंसानों और जानवरों, दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है
- यह पौधा सिर्फ बीमारी में ही नहीं, सौंदर्य से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में भी 'उस्ताद' है। हालांकि इसका कितनी मात्रा या कब प्रयोग करना है इसे लेकर चिकित्सीय परामर्श जरूरी है

(मीडिया इनपुट्स)

समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार ने चीन द्वारा भारत पर व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध, जिनमें महत्त्वपूर्ण उत्पादों के निर्यात पर रोक भी शामिल है, थोपे जाने के बावजूद टेस्ला को चीन-निर्मित मॉडल वाई कार भारत में लॉन्च करने की अनुमति कैसे दे दी। वो भी तब जब टेस्ला ने साफ कर दिया है कि भारत में इस मॉडल के विनिर्माण का अभी उसका कोई इरादा नहीं है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

रूस का बड़ा दांव और भारत

अफगान मोर्चा **गिरीश पांडे**

हाल में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को रूस की ओर से आधिकारिक मान्यता मिल गई है। चीन, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे कई देशों की राजनयिक इंगेजमेंट के बावजूद रूस दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने अफगानिस्तान को राजनयिक मान्यता प्रदान कर दी है। इसे हम रूस का वैश्विक मंच पर अप्रत्याशित और निर्णायक कदम कह सकते हैं।

यह कदम ऐसे समय उठा है जब अमेरिका, भारत और यूरोप जैसे प्रमुख देश अब भी तालिबान शासन को मान्यता देने से परहेज कर रहे हैं। रूस के इस कदम के पीछे कई रणनीतिक कारण निहित हैं। मसलन, रूस, पश्चिमी दबावों से मुक्त होकर स्वतंत्र शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। अफगानिस्तान, मध्य एशियाई गणराज्यों की सीमा पर स्थित है, जहां रूस की पारंपरिक पकड़ रही है। तालिबान से संपर्क इसी विस्तार का हिस्सा है। रूस के निर्णय का असर अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और विश्व राजनीति पर इसका असर पड़ने की संभावना है। 1979 में सोवियत सैनिकों के अफगानिस्तान में दखल के बाद से लेकर 1989 तक मिखाइल गोर्बाचोव के अपनी सेना वापस बुलाने तक अफगानिस्तान और रूस जटिल ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों में उलझे रहे।

हालांकि, 20 साल बाद अप्रैल, 2025 में रूस ने तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाया था और इसके बाद अफगानिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा था। अफगानी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऐसी ही एक संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत (आईएसकेपी) के मद्देनजर तालिबान से सुरक्षा सहयोग की दरकार है। इस समूह ने रूस में पिछले साल आतंकी हमले को अंजाम दिया था और जिसमें 130 लोग मारे गए थे। इसलिए रूस ने इस बार यह महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

ध्यान देने की बात है कि अगस्त, 2021 में अमेरिका और नाटो के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तब तालिबान ने कहा था कि वह अफगानिस्तान में लिबरल शासन चलाएगा,

लेकिन उसके बाद उन्होंने कड़े शिया कानून लागू कर दिए। महिलाओं के प्रति कड़ी भेदभाव वाली नीतियों की वजह से पश्चिम के देशों ने तालिबान को राजनयिक तौर पर अलग-थलग रखा है। जानकार कहते हैं कि अब चीन भी रूस के नक्शेकदम पर चलेगा और अफगानिस्तान को मान्यता देने के बारे में सोचेगा। वैसे भी अभी रूस और चीन की 'अनलिमिटेड दोस्ती' चल रही है।

जहां तक भारत का संबंध है, रूस के इस निर्णय से भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां और विकल्प उभरते हैं। पहला तो यही है कि रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। रूस द्वारा तालिबान को मान्यता देना भारत के हितों के विपरीत प्रतीत हो सकता है, विशेषकर जब अफगानिस्तान से आतंकवाद की आशंका बनी हुई हो। इसके अलावा, रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान का तालिबान से व्यवहार भारत के लिए अलग-थलग पड़ने की स्थिति पैदा कर सकता है, और तालिबान की सत्ता में मजबूती, जम्मू-कश्मीर में कट्टरपंथी ताकतों को परोक्ष समर्थन दे सकती है। इसलिए अभी भारत का तालिबान के साथ सॉफ्ट एंगेजमेंट चल रहा है, और तालिबान के साथ बिना उसे औपचारिक मान्यता दिए सीमित और नियंत्रित संवाद जारी हैं।

भारत, अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति की भी बराबर निगरानी कर रहा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत का दृष्टिकोण हमेशा ही अफगान के लोगों के साथ दीर्घकालिक और विशेष मित्रता से प्रेरित रहा है, और साथ ही एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत का हित सीधे जुड़ा है। अफगानिस्तान के साथ अपने पुराने संबंधों पर जोर देते हुए भारत ने युद्धग्रस्त देश की मानवीय और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की सदैव ही प्रतिबद्धता जताई है। यह तब खास हो जाता है, जब चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में सक्रिय हैं। अफगान जनता के बीच विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी भारत की साख यथावत बनी रहनी चाहिए। सरकार को जहां आतंकवाद-निरोधक तंत्र और खुफिया संपर्कों को मजबूत करना होगा, वहीं रूस, ईरान और मध्य एशिया के साथ संवाद तेज कर एक संतुलित कूटनीति भी अपनानी होगी। यहां यह भी ध्यान में रखना जरूरी होगा कि रूस द्वारा तालिबान को मान्यता देना केवल कूटनीतिक घटना नहीं है, यह संकेत है इस बात का कि विश्व व्यवस्था पुनः आकार ले रही है। भारत को नये परिदृश्य में सजग, सक्रिय और संतुलित रह कर अपना मार्ग चुनना होगा ताकि अपने हितों की रक्षा करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता में भी योगदान दे सके।

जन्म-मरण **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

हम मनुष्य संसार में केवल एक सीमित जीवन जीने नहीं आते, बल्कि यह जीवन तो हमारे अनगिनत जन्मों की एक कड़ी भर है।

आत्मा अमर है, शाश्वत है, और यह शरीर बदलना तो जैसे वस्त्र बदलने के समान है। परंतु हम मनुष्य इस सत्य को विस्मृत कर देते हैं। हमें लगता है कि यह एक ही जीवन है, और इसके पूर्व भी कुछ नहीं था और इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। श्रीमद्भागवत में बड़ा प्रेरक प्रसंग है। एक बार राजा यदु ने देखा कि एक साधारण व्यक्ति, जिसका शरीर वृद्ध हो गया था, अत्यंत शांत और आनंदपूर्ण था। राजा को आश्चर्य हुआ कि जीवन की संध्या में, जब शरीर जर्जर हो चुका है, यह व्यक्ति इतना संतुलित और प्रसन्न कैसे है? राजा यदु ने उससे पूछा, 'हे सज्जन! आप किस आधार पर इतने आनंद में हैं? न आपके पास धन है, न बल है, न ही कोई सांसारिक सुख।' उसने उत्तर दिया, 'मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं-प्रकृति, पशु, पक्षी, जल, अग्नि आदि-और इन सबसे मैंने सीखा कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। शरीर की अवस्था बदलती है, लेकिन आत्मा नित्य है। इस सत्य को जानने वाला जीवन में किसी भी अवस्था में शांति प्राप्त कर सकता है। इस तथ्य को न जानने वाला ही सबसे बड़ा अज्ञानी है।' महंत स्वामी महाराज समझाते हैं, 'यह अज्ञान ही हमें बार-बार जन्म लेने को बाध्य करता है। इसके कारण आत्मा अपने परम लक्ष्य-की ओर अग्रसर नहीं होती और संसार-चक्र में घूमती रहती है। जैसे चक्र लगातार घूमता है और रुकता नहीं, वैसे ही आत्मा भी बार-बार जन्म लेकर संसार में फंसती जाती है। हम सोचते हैं कि जीवन ही सब कुछ है, इसलिए सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, परंतु इस चक्र से अनभिज्ञ रहते हैं। किंतु भगवान इससे अभिज्ञ हैं।' उन्होंने कहा, 'हे अर्जुन! मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तू नहीं जानता।' भगवान, जो सर्वज्ञ हैं, हमारे हर जन्म, हर कर्म और हर विचार को जानते हैं। वे हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए जीवन को केवल सांसारिक सीमित दृष्टि से देखना भारी भूल है। यह तो एक यात्रा है-आत्मा की परमात्मा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर।

रीडर्स मेल

स्कूल विलयन की जमीनी सच्चाई

उत्तर प्रदेश सरकार 50 बच्चों से कम वाले प्राइमरी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय के निर्देश की वजह से चर्चा में है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां जहां इसका जम कर विरोध कर रही हैं तो दूसरी तरफ आम जनता को समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर, हो क्या रहा है जबकि जमीनी सच्चाई कहीं अलग है, जिसे समझने के लिए आंकड़ों पर भरोसा करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय के विरोध में उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका भी खारिज हो गई है। सरकार के इस निर्णय का विरोध प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी किया है। स्कूल के भवनों का बुरा हाल है। अकेले प्रयागराज में 633 स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हैं। स्कूलों को बंद न करने के लिए आर्टिकल 21ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि यह विवाद सुनवाई के लिए अब उच्चतम न्यायालय में है।

डॉ. अजय कुमार मिश्रा, ई मेल से

कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कुछ दिन पहले कुदरत का कहर बरपा जहां बादल फटने से जान-माल की भारी हानि हुई। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि बादल फटने का कारण ग्लोबल वार्मिंग या कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा तो नहीं? इंसान स्वार्थी हो गया है जो प्रेम भी स्वार्थ के लिए करता है। लेकिन प्रकृति से प्रेम के बदले प्रेम ही मिलेगा यह शत-प्रतिशत सत्य है, क्योंकि यह निस्वार्थ भाव से हमें वो सब कुछ देती है, जो हमें जीवन जीने के लिए जरूरी है। लेकिन इंसान ने अपनी सुविधाओं के लिए पहाड़ों का सीना छलनी कर दिया है। कुछ समय पहले उत्तराखंड में ग्लेशियर ने जो तबाही मचाई थी, उसके लिए अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों टन वजनी चट्टानों व लाखों टन बर्फ के सीधे दो किमी. तक लगातार नीचे गिरने की वजह से इलाके में तापमान तेजी से बहुत अधिक बढ़ गया और इसके चलते बर्फ तेजी से पिघल गई। इस पर भी पर्यावरणविद् और वैज्ञानिकों को अध्ययन करना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बारिश का कहर

देश में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शहरों में पानी की निकासी नहीं होने से बारिश का पानी भरा रहता है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। पानी के बहाव में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में पानी के बहाव ने तीन जिंदगियां लील दीं। सड़कें धंसने और भूस्खलन की घटनाओं में प्रशासन की पोल खोल दी। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में बारिश के कारण कई दिनों तक जल-जमाव की वजह से जनजीवन पर प्रभाव देखा गया है। गुजरात में कई दिनों तक भरे पानी की निकासी नहीं हुई जिसके कारण घरों में पानी घुस गया। गटर और पानी की निकासी के लिए सरकार का बंदोबस्त जीरो दिखाई दिया। देश का विकास भी इन्हीं बिंदुओं पर निर्भर है। मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए।

कांतिलाल मांडोत, सूरत

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष - 19, अंक 6718
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बेरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

आप जो सिखाते हैं वह नहीं, बल्कि आप जो करते हैं, वह बच्चों को ज्यादा याद रहता है। -जिम हेंसन

अमेरिकी सीनेटरों और नाटो की भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के रूस के साथ व्यापार करने पर भारी टैरिफ लगाए जाने की चेतावनी के पीछे आर्थिक युद्ध की आहट सुनाई देती है। यह आर्थिक-कूटनीतिक तनाव वैश्विक व्यवस्था को किस ओर ले जाएगा, यह तो समय ही बताएगा।

आर्थिक युद्ध की आहट

ऐसे समय में, जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्धों, क्षेत्रीय संघर्षों और ट्रंप के टैरिफ की आशंकाओं के चलते शक्तियों के बीच टकराव पहले ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, तब अमेरिकी सीनेटरों और नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) की भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों के रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखने पर भारी टैरिफ लगाए जाने की चेतावनी देने से सवाल उठता है कि कहीं दुनिया आर्थिक युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रही। ध्यान रहे कि यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पचास दिन के भीतर यूक्रेन से युद्ध खत्म न करने पर सौ फीसदी द्वितीयक टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि द्वितीयक टैरिफ उन देशों या कंपनियों पर लगता है, जिन पर सीधे कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन उनके साथ व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। चूंकि भारत और चीन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक हैं, यह स्थिति दोनों के लिए चिंताएं बढ़ाने वाली है। भारत अपनी तकरीबन 88 फीसदी कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, और पिछले करीब तीन वर्षों से रूस भारत के तेल आयात का आधार रहा है। अगर इन टैरिफ के चलते रूस से तेल की आपूर्ति रुकती है, तो भारत को सऊदी अरब और इराक जैसे वैकल्पिक स्रोतों को देखना होगा, जिससे स्वाभाविक ही तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी अपनी चिंताओं को लेकर अमेरिकी सांसदों और ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है। दरअसल, इस सवाल का जवाब कि-क्या टैरिफ की धमकियां इन देशों को अपनी व्यापारिक नीतियों में बदलाव लाने पर मजबूर करेंगी-इतना आसान नहीं है। इसकी पहली वजह तो यह कि तीनों ही मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं और दूसरी यह कि इन देशों के साथ पश्चिमी देशों के भी गहरे हित जुड़े

हुए हैं। नाटो में शामिल पश्चिमी देशों का तर्क है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देश अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि, भारत ने हमेशा से ही इस मामले में तटस्थ रुख अपनाते हुए बार-बार कहा है कि वह संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांति की वकालत करता है, और उसका रूस के साथ व्यापार राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। बहरहाल, भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को टैरिफ की चेतावनी ने कूटनीति के मोर्चे पर नया तनाव तो पैदा किया ही है। अब यह तनाव वैश्विक व्यवस्था को किस दिशा में ले जाता है, यह तो समय ही बताएगा।

युद्धों के दौर में बच्चे

जब रूस-यूक्रेन का अंतहीन युद्ध जारी हो, इस्राइल-ईरान तनाव कायम हो, पाकिस्तान व बांग्लादेश की स्थितियों का भारत पर प्रभाव पड़ रहा हो, आतंकी हमलों, पुल ढहने और विमान दुर्घटना की खबरें चौबीसों घंटे टीवी पर उमड़ रही हों, तब ये माहौल बच्चों के मनोविज्ञान पर असर न डालें, सबसे बड़ी चुनौती यही है।

क्या हम एक असुरक्षित दुनिया में जी रहे हैं? मृत्यु तो जीवन का सत्य है, लेकिन क्या हमें इस असुरक्षा के साथ लगातार जीना होगा कि जीवन और मृत्यु में, मृत्यु ही ज्यादा निश्चित होती जा रही है? नहीं तो, किसने सोचा था कि श्रीनगर के एयर टर्बुलेंस के भयावह अनुभव के बाद एक इतना बड़ा एयर क्रैश हो जाएगा और देखते ही देखते एक को छोड़ सभी यात्री मौन हो जाएंगे। आखिर यह दुनिया क्यों इतनी असुरक्षित होती जा रही है? हर दूसरे दिन एक पुल गिर जाता है या बरसात में कूलर से भी करंट लग जाता है। ऐसे में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी मनोस्थिति का क्या? क्या वे ऐसी अनिश्चितता से कुछ ज्यादा भयभीत नहीं महसूस करेंगे? और उनके माता-पिता इस असुरक्षित होती हुई दुनिया को लेकर उन्हें आखिर क्या सीख देंगे?

नंदितेश निलय
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

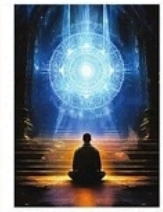

यह कि उन्हें हवाई यात्रा से बचना चाहिए या कहीं घूमने से। नहीं तो कोई पहलगाम जैसी घटना हो सकती है। और यह सिखाते-सिखाते युद्ध का सायरन बज जाए, तो फिर वे माता-पिता और बच्चे क्या करें? भूख से बिलखते बच्चे, रूस-यूक्रेन का युद्ध, बांग्लादेश-पाकिस्तान की उथल-पुथल में फंसा भारत और फिर तमाम असुरक्षा के बीच माता-पिता अपने बच्चों को जीने का हौसला कैसे दें? यह कठिन घड़ी है, क्योंकि जीवन कुछ ज्यादा अनिश्चित हो गया है। और यह उन तमाम माता-पिता के लिए एक चुनौती है, जहां उन्हें बच्चों को सतर्क भी करना है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी।

बच्चों की यह एक पीढ़ी पहले ही कोविड की भयावहता और असुरक्षा से रूबरू हो चुकी है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से चल रहा तनाव एक बहुत मुश्किल पाठ बन चुका है। उस हर छात्र के मन में डर का माहौल है, जब वह कोई सायरन बजते सुनता है या कोई मॉक ड्रिल की खबर आ जाती है। उन बच्चों की आंखों में स्कूल के मॉक ड्रिल के बाद का खामोश डर है। और उन बालकों की पीड़ा का

क्या, जिनके माता-पिता को देश की रक्षा के लिए सीमा पर बुलाया जाता है। वे तो कभी नहीं समझ पाते कि दो देश वर्षों से लड़ क्यों रहे हैं और समझें भी कैसे? आखिर दो देशों के बीच उलझे हुए इतिहास और संघर्ष के परिणामों को समझने के लिए वे अभी बहुत कोमल भी तो हैं।

लेकिन युद्ध और तमाम मृत्यु की घटनाएं उनके बचपन को बाधित कर रही हैं-उस डर से, अनिश्चितता से, एक ऐसी दुनिया से, जो अचानक कम सुरक्षित महसूस मालूम होती नजर आ रही है। और यह चिंता और घनी होती जा रही है। जब उनके माता-पिता खुद को असहाय महसूस कर रहे होते हैं।

अपने जीवन से ज्यादा दूसरे के जीवन का महत्व कोविड ने समझाया। आखिर दुनिया ने उस अकेलेपन और उपेक्षा को भी कोविड के दौर में झेला है। अपने शोध अध्ययन 'कोविड-19 : पोस्ट-ट्रॉमैटिक ग्रोथ और तनाव के अनुभव पर सामाजिक संबंध की भूमिका' में मार्सेला माटोस, कर्स्टन मैकइवान, मार्टिन कानोवस्की आदि यह मानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो एक प्रमुख तनाव समझा गया वह था सामाजिक वियोग और अकेलेपन की भावना। उनका अध्ययन इस बात की भी पड़ताल करता है कि अकेलेपन और करुणा के अभाव ने किस तरह से लोगों के पोस्ट-ट्रॉमैटिक ग्रोथ और पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस को प्रभावित किया है।

'कोविड 19 समुदाय, संचार और करुणा', यही फियोना लॉन्गमुइर का शोध पेपर था और यह पेपर उन तरीकों की जांच करता है, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई स्कूल के लीडर्स ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न संकट और अनिश्चितता की स्थितियों को समझा और उनका सामना किया। उनके निष्कर्षों से यह पता चला कि इन तमाम विद्यालयों का मुख्य फोकस संवेदना निर्माण और अपने समुदायों की भलाई करना था। पवित्रा डी जुलुएटा ने अपने अध्ययन में लिखा, 'करुणा मानव कल्याण के लिए केंद्रीय है, जो इसे देते हैं और जो इसे प्राप्त करते हैं, दोनों को ही लाभ होता है।'

तो यह जरूरी है कि माता-पिता इस असुरक्षित माहौल में अपने बच्चों को और करुणा और संवेदनशीलता से समझें। उन्हें सुनने की कोशिश करें। अगर वे भयभीत नजर आएं या डर को व्यक्त करें, तो उन्हें डरपोक की संज्ञा न दें। आशा तभी संजोई जा सकती है, जब स्कूल से पास होते ही उन्हें सिर्फ यह न बताया जाए कि कुछेक लोगों से ही यह दुनिया चलती है और वे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। बारहवीं के बाद कोई भी सपना इन ग्रहों के इतर नहीं होता। कोई उनसे नहीं पूछता कि तुम क्या बनना चाहते हो?

सभी गूगल से पूछकर उसे यह बताने में लगे रहते हैं कि स्कूल की आजाद दुनिया कुछ नहीं होती और न होती है कुछ उसकी वह अटेंडेंस वाली पढ़ाई। दुनिया तो नौकरी से शुरू होकर वहीं समाप्त भी हो जाती है। लेकिन एक दुनिया स्वस्थ रूप से खुश होकर जिंदा रहने की भी होती है और उन दुखों को महसूस करने के कवच-कुंडल के साथ। अगर स्कूल संग माता-पिता इस बात को समझेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को वे उस करुणा और संवेदना से जोड़ पाएंगे, जो कहीं न कहीं से उनको जीवन की आशा देगी। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी।

अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कल कोई बच्चा हवाई जहाज पर बैठने से डरेगा, और डरेगा उड़ते ड्रोन को देखकर, कहीं पहाड़ों पर घूमने जाने से भी डरेगा और ठिठक जाएगा मॉक ड्रिल की खबर और उस सायरन को सुनकर। इस असुरक्षा को हर मां-बाप और स्कूल के शिक्षक को समझना होगा और करुणा और संवेदना के मूल्यों को एकीकृत कर उनको अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास, 'द ओल्ड मैन एंड द सी' के उस सिंटिया नामक बूढ़े मछुआरे के कथन को दोहराना होगा, 'मनुष्य को पराजित नहीं किया जा सकता।'

edit@amarujala.com

जीवन धारा

तोबियास बेक

अभी जो आप हैं, उससे आगे जाने और पहले से बेहतर होने के लिए अपने ऊपर एक दबाव जरूर लाएं। ऐसा दबाव, जो आपको काम करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहे।

दबाव सहने वाला ही हीरा बन जाता है

प्रकृति में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। यदि कोई बड़ा पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जंगल में खड़ा रहता है और अचानक बुरे मौसम की वजह से धराशायी हो जाता है, तो क्या वह खत्म हो गया? नहीं, इसके विपरीत! वह सड़ता है। समय के साथ धीरे-धीरे। थोड़ा-थोड़ा करके प्रकृति उसे धरती के भीतर समा लेती है। कई वर्षों के दबाव के बाद, एक समय ऐसा आता है, जब कुछ नया बनता है, वह कोयले का रूप ले लेता है। जब कोयले पर और अधिक दबाव पड़ता है, तो परिमाणस्वरूप वह हीरा (डायमंड) बन जाता है। आम तौर पर, किसी भी कण पर जब एक सीमा से अधिक बाहरी दबाव डाला जाएगा, तो आखिरकार उसकी सहनशक्ति के बाहर हो जाएगा और कुछ नया पैदा होगा। इस सरल अवधारणा ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया।

आजकल, मैं जान-बूझकर खुद को काफी दबाव वाली स्थितियों में डालता हूं, ताकि कुछ नया, अद्भुत और रचनात्मक उभरकर आ सके। इसका आपसे और आपके जीवन से क्या लेना-देना है? दरअसल, ऐसे कई लोग, जिन्हें मैं जानता हूं, अपनी पूरी जिंदगी दर्द और दबाव से बचने की कोशिश करते रहते हैं, इस डर से कि कुछ बुरा हो सकता है। जिंदगी की नाव चलाने में महारत कैसे हासिल करनी है, यह सीखने के लिए मेरा मानना है कि हमें तूफानों में प्रवेश करना होगा, क्योंकि ऊंची लहरों के बीच ही एक कप्तान अपने जहाज को बुरी से बुरी परिस्थितियों में नियंत्रित करना सीख सकता है। यही वजह है कि मैं अक्सर ऐसे सेमिनार अटेंड करने की कोशिश करता हूं, जो मुझे अपनी व्यक्तिगत सीमाओं तक ले जाएं। दो साल पहले, मलयेशिया में एक कार्यशाला में, मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर एक फाइटर से बचने का प्रयास करने के लिए कहा गया। दहशत और पसीने से तर-बतर होने के बावजूद, मैंने एहसास किया कि हमारे भीतर का दिशासूचक कितना शक्तिशाली होता है। जब आप अपनी सीमाओं को परखते हैं, तो आपको एक चीज के लिए तैयार रहना होगा।

मेरे जीवन में, कई ऐसी परिस्थितियां रहीं, जहां मुझे महसूस हुआ कि अब मैं दबाव सहन नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक महान साहसिक कार्य के बीच में था, और जिसे मैं केवल आंशिक रूप से ही प्रभावित कर सकता था। यह चुनौतीपूर्ण जीवन इस खोज के बारे में था कि हमारे भीतर क्या छिपा हुआ है। अपने जीवन की किन परिस्थितियों को आप याद कर सकते हैं, जहां पर दबाव इतना अधिक था कि सहन करना मुश्किल था? इन परिस्थितियों का आखिर क्या परिणाम हुआ? जीवन में खुद को अभी जो आप हैं, उससे आगे जाने और पहले से बेहतर होने के लिए अपने ऊपर एक दबाव जरूर लाएं। ऐसा दबाव जो आपको काम करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहे।

-'अनबॉक्स यॉर लाइफ के अनूदित अंश'

सबको गले लगाएं

सूत्र

जीवन में कामयाबी का असली रहस्य-अपनी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से हासिल करें। एक ऐसा दबाव, जो हमें सफलता और सही मार्ग पर ले जाने के लिए हो, तो यह हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। खुद को ऐसा बनाएं कि हर स्थिति को हां कहें, चाहे वह सबसे अच्छी हो या बुरी, सबको गले लगाएं।

दूसरा पहलू

मस्तिष्क एक सुपरकंप्यूटर की तरह होता है। इसका हर एक हिस्सा एक खास काम के लिए होता है।

आखिर दिमाग सोचता कैसे है

क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे सोचता है या अचानक कोई विचार क्यों उभरता है? यह जादू जैसा लग सकता है, पर वास्तव में दिमाग एक सुपरकंप्यूटर की तरह है, जो आपकी सोचने, सीखने व फैसले लेने में मदद करता है। दिमाग का हर हिस्सा एक खास काम करता है। न्यूरॉन मस्तिष्क में अहम भूमिका निभाता है, ये छोटी कोशिकाएं हैं, जो एक-दूसरे से संवाद करने के लिए संदेश भेजती और प्राप्त करती हैं। दिमाग में 80 से 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो अक्सर एकसाथ मिलकर तंत्रिका पथ बनाते हैं। जब मन में कोई विचार आता है, तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं और विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। ये आवेग आम तौर पर समान मार्गों से गुजरकर रास्ते में न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन छोड़ते हैं, जिससे संदेशों का संचार आसान हो जाता है।

जेनिफर रॉबिन्सन

दिमाग में 80 से 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो अक्सर एकसाथ मिलकर तंत्रिका पथ बनाते हैं। जब मन में कोई विचार आता है, तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं।

नई चीजें सीखने और आसपास की दुनिया के अनुभव से ये संबंध और मजबूत हो जाते हैं। आपके अभ्यास करने से ये न्यूरॉन्स और ज्यादा सक्रिय होते हैं। तंत्रिका नेटवर्क बनते हैं और जितनी बार ये आपस में संवाद करते हैं, उतने ही मजबूत होते जाते हैं। यह लगातार आपकी इंद्रियों से इनपुट प्राप्त करता रहता है-दृश्य, ध्वनि, स्वाद, गंध और स्पर्श। जब आप कोई प्यारा पिल्ला देखते हैं या अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, तो आपकी इंद्रियां मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं, जिससे विचारों और भावनाओं की एक शृंखला शुरू हो जाती है।

मस्तिष्क एक अद्भुत अंग है, जो विचारों, स्मृतियों और कल्पनाओं को रचने के लिए अथक परिश्रम करता है। वैज्ञानिकों ने काफी शोध किया है, पर दिमाग को पूरी तरह समझने के लिए बहुत कुछ सीखना बाकी है।

मस्तिष्क यादों को भी संजोता है, जिन्हें आप जब चाहें पा सकते हैं। रचनात्मकता दिमाग की एक और महान शक्ति है। कलाकार, लेखक और वैज्ञानिक अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल नई संभावनाओं को तलाशने और समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि नींद के साथ स्वस्थ भोजन और व्यायाम भी दिमाग के लिए जरूरी हैं। दिमाग को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ताकि वह बेहतर काम कर सके और आपकी सोचने की शक्ति बढ़े। आप जो भी ग्रहण करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका आपके मस्तिष्क पर असर पड़ता है। मस्तिष्क एक अद्भुत अंग है, जो विचारों, स्मृतियों और कल्पनाओं को रचने के लिए अथक परिश्रम करता है। जैसे-जैसे तकनीक में सुधार होता रहेगा, वैज्ञानिक इस बारे में और अधिक सीखते जाएंगे कि जैविक प्रक्रियाएं हमारे चेतन अनुभवों को कैसे जन्म देती हैं। दिमाग को समझने के लिए हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। -(द कन्वर्सेशन से)

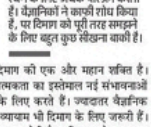

आंकड़े

ऊर्जा के विकल्प

पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।

2020	377
2021	521
2022	685
2023	1017
2024	1082

आंकड़े भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्टअप की संख्या के | स्रोत: MoNRE

भूखों को पहले भोजन कराने की बात ब्राह्मणों को पता चली, तो उन्होंने एकनाथ जी के यहां भोजन नहीं किया। पर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पितर स्वयं प्रकट हो गए।

श्रद्धा से प्रकट होते हैं पितर

भक्त एकनाथ जी बचपन से ही बड़े बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे। उनके पिता सूर्यनारायण जी का देहांत हो गया था और उसके कुछ दिन बाद माता रुक्मिणी का भी। जब एकनाथ जी के पिता का श्राद्ध था, तो ब्रह्मभोज के लिए रसोई तैयार हुई। आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में वह अपने द्वार पर खड़े थे। उसी समय कुछ लोग वहां से जा रहे थे। पकवानों की महक पाकर वे आपस में कहने लगे, 'कैसी सुगंध आ रही है, भूख न हो तो भूख लग जाए! पर ऐसा खाना हम लोगों के भाग्य में कहां।' एकनाथ जी ने यह बात सुन ली। उन्होंने तुरंत उन लोगों को बुलाया और ब्राह्मणों के लिए तैयार किया गया श्राद्ध का भोजन उन्हें खिला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके घरवालों को बुलाकर भोजन करवाया।

यह बात जब आमंत्रित ब्राह्मणों को मालूम हुई, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने एकनाथ जी को धर्मभ्रष्ट समझकर खूब भला-बुरा सुनाया और कहा कि तुम्हारे-जैसे पतित के यहां हम लोग भोजन नहीं करेंगे। वे लोग भला-बुरा कहकर चले गए। यथाविधि श्राद्ध का संकल्प करके श्री एकनाथ जी ने पितरों का 'ध्यान और आवाहन' किया। बताते हैं कि एकनाथ जी की निश्छल भक्ति और उनके संकल्प से प्रसन्न होकर पितर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुए। वे श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध से परितृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। एकनाथ जी का मानना था कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 17 जुलाई, 1951

जापान में कम्युनिस्ट बगावत करेंगे, चीन देगा सहायता

कोरिया संबंधी शांति वार्ता असफल हो गई, तो चीन जापानी कम्युनिस्टों को हथियार आदि की सहायता देकर उनके जरिये जापान में बगावत करा देगा। जो चीनी कम्युनिस्टों की ओर से लड़ेंगे, उन्हें जापानी बोलना सिखा दिया गया है।

चुनौतियां अभी बाकी हैं

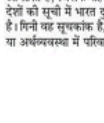

तेजी से घटती गरीबी और अर्थव्यवस्था की प्रगति के बावजूद 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के मद्देनजर आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश नहीं हैं।

जयंतीलाल भंडारी | आर्थिकी

इन दिनों भारत की गरीबी, सामाजिक सुरक्षा और समानता से संबंधित तीन महत्वपूर्ण रिपोर्टों को गंभीरता से पढ़ा जा रहा है। पहली रिपोर्ट विश्व बैंक की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में पिछले 11 वर्षों में जबर्दस्त गिरावट आई है और करीब 27 करोड़ देशवासी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। दूसरी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की है, जिसके मुताबिक, भारत में इस वर्ष 64 फीसदी से अधिक आबादी यानी करीब 95 करोड़ लोग किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि वर्ष 2015 में ये योजनाएं 25 करोड़ से भी कम लोगों तक पहुंच रही थीं।

तीसरी रिपोर्ट, विश्व बैंक के गिनी सूचकांक पर आधारित है, जिसके तहत तेजी से समानता बढ़ाने वाले देशों की सूची में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर आ गया है। गिनी वह सूचकांक है, जो यह मापता है कि किसी देश या अर्थव्यवस्था में परिवारों की आमदनी का बंटवारा या

उपभोग समानता से हो रहा है या नहीं। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंध में जो नए अनुमान जारी किए हैं, उनके मुताबिक, निम्न आय वाले देशों के लिए अत्यधिक गरीबी की रेखा 2.15 डॉलर प्रतिदिन के उपभोग व्यय से बढ़ाकर अब प्रतिदिन तीन डॉलर उपभोग व्यय पर निर्धारित की गई है। इससे अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ रह गई है। यह परिदृश्य पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की गरीब कल्याण लक्षित योजनाओं की सार्थकता भी प्रस्तुत करता है।

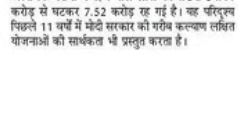

भारत तेजी से सामाजिक सुरक्षा और समानता की डगर पर आगे बढ़ रहा है। आईएलओ के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ हुंगबो ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा में विश्व स्तर पर भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। आईएलओ ने अपने आकलन में केंद्र और राज्य सरकार की 32 योजनाओं के आंकड़े शामिल किए हैं, जिनमें 24 योजनाएं पेंशन से जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं में अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना और पीएम पोषण जैसी योजनाएं शामिल हैं।

एक दशक पहले तक विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कल्याणकारी योजनाओं के सुरक्षा दायरे में नहीं आते थे। इस चुनौती को समझते हुए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुआयामी संरचनात्मक सुधार शुरू किए। इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और इस योजना को लागू करने वाले राज्यों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है।

केंद्र सरकार ने विगत वर्ष 11 सितंबर, 2024 को 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वर्गों के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है, जिसके तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इससे देश के 4.5 करोड़ परिवारों के करीब छह करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलता है। यही नहीं वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए पहला विशिष्ट राष्ट्रीय डिजिटल डाटाबेस ई-श्रम पोर्टल शुरू किया। केवल चार वर्षों में गिग वर्कर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित 30 करोड़ 80 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक इस पोर्टल से जुड़ गए हैं। यह सक्रिय पोर्टल एकल समाधान के रूप में श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ता है। सामाजिक सुरक्षा की कुछ अन्य योजनाएं भी लाभप्रद साबित हो रही हैं।

विश्व बैंक के गिनी सूचकांक के मुताबिक, भारत विकसित देशों के समूह जी-7 और इससे भी बड़े समूह जी-20 के प्रत्येक सदस्य देश से कहीं अधिक तेजी से सामाजिक समानता बढ़ाने वाला देश बन गया है। इस बार भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जिसे विश्व बैंक 'औसत से कम' असमानता वाला देश मानता है। भारत में आर्थिक नीति-निर्माण का सबसे मजबूत व समावेशी मॉडल अपनाया गया है, जहां आर्थिक अवसरों का लाभ देश के हर वर्ग को मिला है।

आर्थिक-सामाजिक कल्याण के संतोषप्रद नतीजों, तेजी से घटती गरीबी व अर्थव्यवस्था के सुकून के बावजूद हमें अभी आम आदमी के कल्याण और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए मीलों चलना होगा। 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। अब भी देश के करीब 52 करोड़ लोगों का सामाजिक सुरक्षा की छतरी के बाहर रहना एक बड़ी आर्थिक-सामाजिक चुनौती है। उम्मीद करें कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के मद्देनजर गरीबी में और तेजी से कमी, निजी-असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों के श्रमबल को मजबूत सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ देश में समानता को बढ़ावा देने की डगर पर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी।

कल्पमेधा

हम जो सोचते हैं, जानते हैं या जिन तथ्यों पर विश्वास करते हैं, वे महत्त्वहीन हैं। महत्त्वपूर्ण है-हमारा कर्म

- जान रस्किन

दोहरे मापदंड

आतंकवाद अब पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण है कुछ देशों की कथनी और करनी में अंतर, जो कई अवसरों और मंचों पर साफ नजर आता है। इस मामले में भारत की नीति और नीयत पूरी तरह स्पष्ट है कि आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्क दोहरे मापदंड अपना कर एक तरफ खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताते हैं, दूसरी ओर अपनी जमीन पर आतंकियों की फौज भी तैयार कर रहे हैं। इन तथ्यों का आकलन शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की हालिया बैठकों में आतंक के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के रुख से किया जा सकता है। चीन के तियानजिन में बीते मंगलवार को हुई एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि इस समूह को आतंकवाद से निपटने के अपने स्थापना उद्देश्य पर कायम रहना चाहिए। भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए नए विचारों और प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपना रहा है।

एससीओ की स्थापना के मूल उद्देश्य में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से निपटने के मुद्दे भी शामिल थे। हालांकि, इस संगठन में शामिल पाकिस्तान और चीन की दखल से इन मुद्दों को हाशिये पर धकेलने का प्रयास किया जाता रहा है। इसके पीछे नापाक मंसूबे छिपे हुए हैं, जो आतंकियों का वित्त पोषण कर उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करने से प्रेरित हैं। भारत कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के इन खतरनाक इरादों को बेनकाब कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता आया है। एससीओ सम्मेलन में भी उसने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी भूमिका नहीं कबूली। जबकि, कंधार विमान अपहरण से लेकर मुंबई हमले, संसद पर हमला तथा उरी, पठानकोट और पहलगाम हमले में उसका हाथ होने की बात साक्ष्यों के साथ जाहिर हो चुकी है। वैश्विक आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ की हालिया रपट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि पहलगाम आतंकी हमला बिना वित्त पोषण के संभव नहीं था।

इससे पहले जून में हुए एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए कहा था कि कुछ देश अपनी नीतियों में सीमापार आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। इसके बाद जब सम्मेलन का संयुक्त घोषणा-पत्र तैयार किया गया, तो उसमें पहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। इससे पाकिस्तान और चीन के मंसूबों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अगर ये देश वास्तव में आतंकवाद को खत्म करने की इच्छा रखते हैं, तो संयुक्त घोषणा-पत्र में पहलगाम हमले की निंदा करने से गुरेज क्यों किया गया? दोराय नहीं कि ऐसे दोहरे मापदंड को खत्म करना बेहद जरूरी है और एससीओ जैसे मंच को ऐसी ताकतों की खुलेआम आलोचना करनी चाहिए। अब जरूरी है कि आतंकवाद के वित्त पोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएं।

असल चिंता

छोटे शहरों से लेकर महानगरों में कुत्तों के काटने से लोगों के जख्मी होने और जान जाने की घटनाएं पहले की अपेक्षा बढ़ गई हैं। इसके कई कारण हैं। आमतौर पर कुत्ते इंसानों के साथ हिंसक नहीं होते। मगर, बढ़ते शहरीकरण के साथ जिस तरह से उनके सुरक्षित पर्यावास और भोजन का संकट पैदा हुआ, उनकी प्रवृत्ति हिंसक होती जा रही है। नतीजा यह कि अब आवारा कुत्तों को गली और सड़क पर भोजन देने पर आपत्तियां उठ रही हैं। इसे पसंद और नापसंद करने वालों के बीच टकराव अदालतों तक जा पहुंचा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनिया में कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज से मौत के छत्तीस फीसद मामले भारत में ही सामने आते हैं। घायलों का ठीक से उपचार न होना भी बड़ी समस्या है। फिलहाल, सड़कों पर घूमते कुत्तों को खाना देने और न देने पर एक विवाद शीर्ष अदालत में है। खाना देने पर परेशान किए जाने का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता से अदालत ने पूछा है कि आप गली-मुहल्ले के प्रत्येक कुत्ते को घर पर ही खाना क्यों नहीं देते। निस्संदेह यह सवाल वाजिब है, क्योंकि सड़कों के किनारे या गलियों में खाना देते समय कई कुत्ते एक जगह जमा हो जाते हैं। यही कुत्ते आते-जाते लोगों खासकर बच्चों और दोपहिया पर सवार लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं।

पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 का नियम पशुओं को भोजन देने की बात रेखांकित तो करता है, लेकिन इसका दायित्व स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र के निवासियों के संगठन पर डाला है। मगर, आज लोग कहीं पर भी पशुओं विशेषकर कुत्तों को खाना खिलाते दिख जाते हैं। मना करने पर झगड़ा और मारपीट की घटनाएं आम हैं। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत को यह कहना पड़ा कि क्या हर गली और सड़क कुत्तों को खाना खिलाने वाले बड़े दिल वालों के लिए छोड़ देनी चाहिए? इसमें दोराय नहीं कि आम आदमी की चिंता सर्वोपरि है। आवारा कुत्तों की देखभाल होनी चाहिए, लेकिन लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए पशु प्रेमियों को आम नागरिकों की चिंता के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

गिरते पुलों के नीचे दबे सवाल

देश में पुलों के ढहने की त्रासदी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कई अन्य राज्यों में हर साल पुल गिरने की घटनाएं दर्ज होती हैं। बिहार में तो हालात सबसे खराब हैं।

योगेश कुमार गोयल

पुलों का निर्माण किसी भी देश के बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा होता है। पुल केवल भौगोलिक दूरी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को जोड़ने का माध्यम भी होते हैं। मगर जब यही पुल अचानक टूटने लगें और उन पर से गुजरते लोग मौत के मुंह में समा जाएं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह कैसा 'विकास' है? देश में पिछले कुछ वर्षों में पुलों के गिरने की घटनाएं जिस भयावहता और निरंतरता के साथ सामने आई हैं, वे न केवल सरकारी तंत्र की लापरवाही की कहानी बयां करती हैं, बल्कि एक भ्रष्ट, गैर-जवाबदेह और संवेदनहीन व्यवस्था की तस्वीर भी प्रस्तुत करती हैं। ताजा मामला गुजरात के वडोदरा जिले का है, जहां महिसागर नदी पर बना पुल अचानक उस समय ढह गया, जब उस पर वाहन गुजर रहे थे। दो ट्रक, दो कारें और एक आटो पुल के टूटे हिस्से के साथ नदी में समा गए। इस हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि भारत के उन अनगिनत पुल हादसों की एक और कड़ी है, जिनमें से प्रत्येक के पीछे कोई न कोई प्रशासनिक विफलता, भ्रष्टाचार या लापरवाही अवश्य मौजूद रही है।

चौंकाने वाली बात यह है कि वडोदरा में जो पुल गिरा, वह कोई सौ साल पुराना नहीं था। यह 45 साल पहले ही बना था। इतने कम समय में पुल का पूरी तरह जर्जर हो जाना तकनीकी विफलता नहीं तो और क्या है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब आज हम कहीं अधिक उन्नत तकनीकी दौर में जी रहे हैं, तब मौजूदा पुल अंग्रेजों के बनाए पुलों की तुलना में इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं? कानपुर-उन्नाव के बीच गंगा पर बना पुल, जिसे वर्ष 1875 में अंग्रेजों ने बनाया था, वह 1998 तक सेवा में था। कासगंज के नदरई पुल ने सौ साल तक साथ निभाया और प्रयागराज का करजन ब्रिज 90 साल से अधिक चला, लेकिन आज बनाए जा रहे पुल बीस-तीस साल में ही कमजोर हो जाते हैं।

देश में पुलों के ढहने की त्रासदी केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और कई अन्य राज्यों में हर साल पुल गिरने की घटनाएं दर्ज होती हैं। बिहार में तो हालात सबसे खराब हैं। वहां हाल के वर्षों में दर्जनों पुल या तो निर्माण के दौरान ढह गए या उद्घाटन से पहले ही गिर गए। पटना और हाजीपुर के बीच गंगा पर बने ऐतिहासिक गांधी सेतु की हालत इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। वर्ष 1982 में इसकी पहली लेन और 1987 में दूसरी लेन शुरू हुई, लेकिन 1991 तक ही उसकी मरम्मत की नौबत आ गई। वर्ष 2000 तक पुल जर्जर हो चुका था और उसके ढांचे को बदलने में 21 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। आखिर इतने कम समय में पुल की यह दुर्दशा क्यों हुई? स्थानीय लोग खुल कर कहते रहे हैं कि 'आटे में नमक नहीं, नमक में आटा मिलाया गया' यानी भ्रष्टाचार इतना हावी था कि निर्माण में गुणवत्ता को ताक पर रख दिया गया। पुलों के निर्माण और

रखरखाव की जिम्मेदारी सरकारी महकमों की है, लेकिन क्या यह सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि जब ऐसे हादसे होते हैं, तब उनकी जांच रपटें क्यों सार्वजनिक नहीं होतीं? यदि होती भी हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या कभी यह बताया गया कि

पिछले दिनों गुजरात के वडोदरा में जो पुल गिरा, वह कोई सौ साल पुराना नहीं था। कम समय में ही पुल का पूरी तरह जर्जर हो जाना तकनीकी विफलता नहीं तो और क्या है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब आज हम कहीं अधिक उन्नत तकनीकी दौर में जी रहे हैं, तब मौजूदा पुल अंग्रेजों के बनाए पुलों की तुलना में इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं? कानपुर-उन्नाव के बीच गंगा पर बना पुल, जिसे वर्ष 1875 में अंग्रेजों ने बनाया था, वह 1998 तक सेवा में था। कासगंज के नदरई पुल ने सौ साल तक साथ निभाया और प्रयागराज का करजन ब्रिज 90 साल से अधिक चला, लेकिन आज बनाए जा रहे पुल बीस-तीस साल में ही कमजोर हो जाते हैं।

गांधी सेतु की इतनी खराब हालत के लिए कौन इंजीनियर, ठेकेदार और अधिकारी जिम्मेदार थे? और क्या उनमें से किसी को सजा दी गई? जवाब है, नहीं। यही कारण है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार का यह चक्र बिना किसी रोक-टोक के चलता जा रहा है। कुछ महीनों पहले ही महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल भी टूट गया था। वह पुल पहले से ही जर्जर था और प्रशासन ने उसे बंद कर दिया था। मगर न तो उस पर निगरानी थी, न ही कोई रोक-टोक। भारत में अब यह एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। मोरबी पुल हादसे को कोई कैसे भूल सकता है। अक्तूबर 2022 में एक झूला पुल टूट जाने से 135 लोगों की जान चली गई थी। उस समय भी यह कहा गया था कि सभी पुलों की जांच की जाएगी। कमजोर पुलों की मरम्मत कराई जाएगी।

सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? यदि हुआ होता, तो क्या वडोदरा और पुणे की ये त्रासदियां होतीं? दरअसल, समस्या केवल तकनीकी नहीं है, यह प्रणालीगत है। जिस वक्त कोई पुल बन रहा होता है, उसी समय उसमें भ्रष्टाचार की नींव रख दी जाती है। निविदा प्रक्रिया में धांधली होती है, सस्ती और घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल होती है। निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। यदि कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करना भी चाहता है, तो उसे या तो बाहर निकाल दिया जाता है या किनारे कर दिया जाता है।

इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि हमारी सार्वजनिक चेतना बहुत सीमित है। हर हादसे के बाद कुछ दिन शोक, कुछ दिन आक्रोश और फिर भूल जाने की प्रवृत्ति आम हो गई है। सरकारें जांच की घोषणा करती हैं, मुआवजे का एलान करती हैं, लेकिन न तो किसी दोषी को सजा मिलती है और न ही कोई स्थायी समाधान सामने आता है। नतीजा, हर एक अंतराल पर कोई नया पुल गिरता है। कुछ और जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। यदि इन हादसों को रोकना है, तो केवल जांच समितियां बनाने से काम नहीं चलेगा। देश के निर्माण और बुनियादी ढांचे की आत्मा को बचाने के लिए जरूरी है कि निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। निर्माण कार्यों की तीसरी-पक्षीय निगरानी हो, जहां निष्पक्ष एजंसियों द्वारा निरीक्षण और आडिट प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। जिन पुलों की हालत खराब है, उन्हें तत्काल बंद किया जाए और वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं।

यह भी जरूरी है कि पुल टूटने या गिरने के हादसों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वह अधिकारी हो, ठेकेदार हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि। जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस देश में निर्माण की गुणवत्ता सुधरने की कोई उम्मीद नहीं की सकती है। यदि कानूनी प्रक्रिया लचर होगी तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और देश की जनता इसी तरह पुलों के नीचे दबी रह जाएगी। हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है, मुआवजा, जांच समिति, रपट और फिर खामोशी। मगर अब इस मौन को तोड़ना होगा। जनता को भी जागरूक होना होगा, सवाल पूछने होंगे। ठेकेदारों, इंजीनियरों और अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह बेहद शर्मनाक है कि जिस देश में करोड़ों की योजनाएं एक दिन में मंजूर हो जाती हैं, वहां लोगों की जान लेने वाले पुल हादसे की जांच रपट वर्षों तक दबा कर रखी जाती है। यदि यह रवैया नहीं बदला गया, तो पुल गिरते रहेंगे और हम केवल आंसू बहाते रहेंगे।

विचार का विस्तार

अनिल त्रिवेदी

दुनिया मेरे आगे

विचार और प्रचार दोनों के बीच अंतर्संबंधों पर जब हम सोचते-विचारते है तो यह सूत्र मिलता है कि विचार ही प्रचार का जन्मदाता है। विचार मूलतः चिंतन प्रक्रिया का मूल या बीज ही माना जाएगा। अगर विचार न हो तो चिंतन, मनन, लेखन और सृजन या विध्वंस कुछ भी उत्पन्न हो ही नहीं सकता। विचार अस्तित्व है तो शून्य अस्तित्व का अभाव है। अस्तित्व साकार या सगुण है, तो शून्य निराकार निर्गुण है। रेखागणित में बिंदु की जो परिभाषा मानी गई है कि जिसमें न तो लंबाई हो और न चौड़ाई, उसे बिंदु माना गया है। यानी एक तरह से बिंदु काल्पनिक है, क्योंकि बिंदु की रेखागणितीय परिभाषा में कल्पना की गई है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई न हो, वह बिंदु है। इस मान्यता पर ही समूची रेखागणितीय अवधारणाएं अस्तित्व में आईं और मस्तिष्क में निराकार विचार-विमर्श या चिंतन परंपरा का उदय हुआ या इसे यों भी कहा जा सकता है कि मान कर सोचने-विचारने का एक विचार जन्मा। विचार कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी अचानक और सोचने-समझने तथा समझाने के दौरान, चलते-फिरते, काम करते या शांत भाव से बैठे-ठाले भी आ सकता है। विचार बातचीत या मिलने-जुलने पर भी आ सकते हैं। कई बार बहुत सोचने पर भी विचार नहीं आते या आते हैं तो उनमें कोई सार नहीं होता। फिर भी मन-मस्तिष्क में विचार की अंतहीन हलचलों का सिलसिला जारी रहता है।

विचार कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी अचानक और सोचने-समझने या समझाने के दौरान आ सकता है। विचार बातचीत या मिलने-जुलने पर भी आ सकते हैं। कई बार बहुत सोचने पर भी विचार नहीं आते या आते हैं तो उनमें कोई सार नहीं होता, फिर भी मनुष्य के मन-मस्तिष्क में विचार की अंतहीन हलचलों का सिलसिला जारी रहता है।

विचार यात्रा में मनुष्य को यह विचार आया कि विचारों को अपने आप तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए विचारों को फैलाना चाहिए, इसी क्रम में प्रचार के विचार का जन्म हुआ। इस तरह हम मान सकते हैं कि प्रचार भी विचार का किसी निश्चित हेतु की दृष्टि से किया गया विस्तार ही है। विचार को प्रचारित करने के विचार ने मनुष्य समाज की चिंतन प्रक्रिया को ही बदल डाला है और आज के कालखंड में प्रचार को लेकर नए-नए प्रयोग करने का एक शास्त्र या मनुष्य के मन-मस्तिष्क को प्रचार तंत्र के माध्यम से अपने अधीन करने का प्रचार साम्राज्य तो स्थापित हो चुका है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के काल खंड में मानव समाज में मौलिक विचार प्रक्रिया पर निर्भरता क्षीण होते जाने के साथ-साथ प्रचार की अंतहीन भूख बढ़ती ही जा रही है। यह सिलसिला सुनामी की तरह मनुष्य की विचार प्रक्रिया को कुंद कर रहा है।

प्रचार के कृत्रिम साम्राज्य के अधीन मानव सभ्यता और समाज के सोच विचार और आपसी व्यवहार में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बदलाव आते दिखाई देते हैं। विचार मनुष्य की प्राकृतिक शक्ति है, पर प्रचार के लिए अप्राकृतिक संसाधन और आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक और तकनीकी संस्थानों की शक्तियों का सहयोग और एजंडा चाहिए। अकेला मनुष्य अपने बलबूते विचार कर सकता है, पर प्रचार अकेले बिना संसाधनों के संभव नहीं है। आज की दुनिया को यह लगने लगा है कि बिना प्राकृतिक विचारों के भी हम जी सकते हैं, पर बिना प्रचार के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक या निजी और सार्वजनिक गतिविधियों को बिना प्रचार के सफलता के साथ संपन्न करना संभव नहीं है। यह चिंतन प्रक्रिया तेजी से फैलती हुई दिखाई पड़ती है और आधुनिक काल के मनुष्य अपनी वैचारिक तेजस्विता के बजाय आभासी प्रचार तंत्र को आसान जीवन का पर्याय मानने की दिशा पकड़ते दृष्टिगत हो रहे हैं।

आज के कालखंड में प्राकृतिक जीवन शृंखला के बजाय आभासी अप्राकृतिक संसाधनों की बाढ़ मानव बसाहटों में मानव सभ्यता का आवश्यक हिस्सा बनती जा रही है। विचार-विमर्श सहित लेखन चिंतन और सृजनात्मक शक्तियों जैसे प्राकृतिक मानवीय गुण अब अप्राकृतिक संसाधनों या शक्तियों के विशेष अधिकार सामान्यतः बनते जा रहे हैं। हमारा समूचा मानव जीवन अप्राकृतिक विस्तार पर निर्भर होता जा रहा है। राज्य, समाज और बाजार तीनों मनुष्यों को सृजनात्मक शक्ति का वाहक बना कर चैतन्य नागरिकों का समाज खड़ा करने की दिशा में बढ़ने के बजाय यंत्र आधारित अप्राकृतिक प्रज्ञा आधारित मनुष्य सभ्यता की दिशा में बढ़ते हुए मानवीय सभ्यता की विविधता को विलुप्त करने की दिशा में अग्रसर होने को ही विकसित सभ्यता का पर्याय बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। मानव मस्तिष्क में प्राकृतिक विचार और व्यवहार क्षीण होकर अप्राकृतिक यंत्रों से चलने वाली दुनिया में मनुष्य यंत्रवत अप्राकृतिक संसाधनों के भरोसे जीने लगा है। मनुष्य जीवन को प्रकृति प्रदत्त वाणी, ज्ञानेंद्रियों और विचार-विमर्श से ओतप्रोत चैतन्य नागरिक बनने के बजाय अप्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित राज्य, समाज और बाजार का अदना उपभोक्ता बनता जा रहा है। आधुनिक दुनिया को अप्राकृतिक संसाधनों का अजायबघर जैसा बना रहा है।

इस तरह जीवंत प्राकृतिक दुनिया को अप्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित, जीवनी शक्ति विहीन उपभोक्ताओं का जीवन मानो एक कठपुतली के खेल में बदल रहा है। आज मानव समाज विचार की नैसर्गिक और जीवंत दिशा को त्याग कर एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत चलने वाले प्रचार साम्राज्य की आधुनिक दुनिया में मानव जीवन को बदलने की निरंतर कोशिश कर रहा है। विचारहीनता और विचार शून्यता एक तरह से मनुष्य की वैचारिकी के दो परस्पर विरोधी ध्रुव की तरह ही है। विचार प्राकृतिक स्वरूप में ओस की बूंद की तरह ही मन-मस्तिष्क में आता है और सूर्योदय के बाद धूप की प्रखरता बढ़ने के साथ ही अपने आप अदृश्य हो सृष्टि में समाहित हो जाता है, वैसे ही विचार का प्राकृतिक स्वरूप असंख्य मस्तिष्कों में समाहित होते ही अपने मूल स्वरूप स्वभाव और प्राकृतिक स्वरूप को ओस की बूंद की तरह ही सृष्टि में समाहित कर लेता है।

वनों पर संकट

वन मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय है। मध्यप्रदेश हो या देश का अन्य कोई राज्य, वन संपदा वहां अनमोल धरोहर के रूप में होती है। इसकी रक्षा करना न केवल राज्य सरकार का बल्कि हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन जब नेता वोट बैंक को प्रभावित करने और सत्ता प्राप्ति के लिए वन संपदा को दांव पर लगा रहे हों, तो फिर किससे उम्मीद की जाए। ऐसे में देश की वन संपदा को बचाने के लिए कौन आगे आएगा? आज वन भूमि पर अतिक्रमण तेजी से हो रहा है। वनों को बचाने के लिए शायद ही कभी किसी नेता ने आवाज उठाई हो। सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बना कर और वन एवं पर्यावरण विभाग का गठन कर वनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। यह विभाग प्रकृति प्रदत्त संपदा की सुरक्षा करता है। विचित्र है कि जब से वन संपदा को राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों का हिस्सा बनाया है, तब से वनों पर अतिक्रमण का दौर और बढ़ गया है।

- अरविंद रावल, गोपाल कालोनी, झाबुआ

निष्पक्षता और पारदर्शिता

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की अनुमति दी है। अब आयोग की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि देश में निष्पक्षता और पारदर्शिता से चुनाव हों। कोई भी वास्तविक मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे और फर्जी मतदाता वोट न देने पाए। इस उद्देश्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मतदाता गणना के लिए आधार और राशन कार्ड आदि को भी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण और पुनरीक्षण एक स्वाभाविक नियमित प्रकिया है और सूचियों में यदि गड़बड़ियां होंगी तो चुनावी निष्पक्षता खतरे में पड़ जाएगी। शीर्ष अदालत का यह निर्णय एक तरह से साफ संदेश है।

- वेद प्रकाश, गुरुग्राम, हरियाणा

नकारात्मक असर

आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सूचना एवं संवाद का अच्छा माध्यम है, लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक रिश्तों तथा सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक असर डाल रहा है। अब लोग एक-दूसरे से कम और मोबाइल स्क्रीन से ज्यादा जुड़े हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी आभासी दुनिया में व्यस्त हैं। युवा 'रील्स' बनाने एवं देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया का सीमित और सकारात्मक उपयोग हो, तो यह न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो सकता है। मगर इसमें संतुलन जरूरी है, ताकि तकनीक के साथ-साथ हमारी संवेदना भी सुरक्षित रहे। दुख-सुख आभासी दुनिया में ही नहीं, हम वास्तविक दुनिया में भी बांटें।

- सावित्री शाह, सिंगरौली

जांच के नाम पर

किसी भी जांच एजंसी का उद्देश्य होता है सच्चाई को सामने लाना, लेकिन अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रपट किसी मकसद तक पहुंचती नहीं दिखती। रपट का पूरा जोर इस बात पर है कि उड़ान के तुरंत बाद ईंधन टैंक के स्विच बंद हो गए थे। 'काकपिट' के भीतर दो वाक्य सार्वजनिक किए गए हैं, जिनमें एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या उसने स्विच आफ किया और फिर दूसरे ने नहीं में जवाब दिया। ऐसा लगता है कि इस जांच रपट में अमेरिकी उड्डयन कंपनी ड्रीमलाइनर की साख को बचाने की कोशिश की गई है। जबकि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच रपट में सवाल तो उठाए गए हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं है। यह वास्तव में निराशाजनक है।

- चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com